चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 11 सितंबर– 17 सितंबर 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

इराक़ के ग्राउंड ज़ीरो से संतोष भारतीय की रिपोर्ट

आईएसआईएस के ख़िलाफ़ जनयुद्ध

इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ इराक में युद्ध चल रहा है. आईएसआईएस ने इराक के एक हिस्से पर क़ब्ज़ा जमा रखा है. पहले उन्होंने बड़े क्षेत्र पर क़ब्ज़ा जमाया था. वो पूरे इराक के ऊपर क़ब्ज़ा करना चाहते थे, पर धीरे-धीरे इराकी सेना ने उन्हें पीछे धकेल दिया. अब वे केवल तलअफर के इलाके में सिमट कर रह गए हैं. इस युद्ध में अमेरिका सहित पश्चिमी देश आईएसआईएस के खिलाफ इराक के लोगों की मदद कर रहे हैं, यह समाचार भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है. मैं इस युद्ध को महसूस करने और जो लोग इराक में सीधे लड़ाई में शामिल हैं, उन लोगों से बात करने इराक गया. 54 डिग्री से ज्यादा भयानक गर्मी, रेगिस्तान, पानी की कमी और आमने-सामने की लड़ाई में जूझ रहे लोगों से जब मेरा सामना हुआ, तब मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं. इराकी सेना की वास्तविकता, अमेरिका और पश्चिमी देशों की सच्चाई तथा आईएसआईएस से कौन लोग लड़ रहे हैं, यह जानकारी मेरे लिए चौंकाने वाली थी. मैं पब्लिक मोबला-इजेशन, जिसे इराक में पीएम कहा जाता है और जिसका अरबी नाम ह१द अलशाबी है, उनके दो कमांडरों से मिला. इनके नाम हैं सैयद मोहम्मद अल तला गनी और सैयद अहमद मुसावी. मैं उन लोगों से भी मिला, जो ह१द अलशाबी के सदस्य हैं और जिन्होंने आईएसआईएस को यानि दाईश को मोसूल से निकालकर एक छोटे कस्बे में घेर रखा है. आईएसआईएस के अत्याधुनिक हथियारों, उनकी क्रूर रणनीति, उनके अमानवीय कार्यों के खिलाफ कैसे छोटे हथियारों से नौजवानों ने लड़ाई लड़ी और अपनी शहादत दी, ये जानकर युद्ध में शहीद हुए नौजवानों के प्रति मेरा सिर श्रद्धा से झुक गया. मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि दरअसल आईएसआईएस के खिलाफ चल रहे युद्ध की सच्चाई क्या है? उसमें जो लोग शामिल हुए, उनकी मानसिकता क्या थी और इस समय युद्ध की हालत क्या है? ये रिपोर्ट सीधे इराक के युद्धग्रस्त क्षेत्र से मैंने भेजी है.

संतोष भारतीय

दरअसल अरब दुनिया और खास तौर पर इस्लामी देश हमेशा उग्रवाद और बाहरी ताक़तों के प्रभाव में रहे हैं. इन ताक़तों ने अरब देशों की सुरक्षा और स्थिरता को हिला कर रख दिया. नतीजतन क्रूर शासकों को यहां की सत्ता पर क़ब्जा जमाने का मौक़ा मिला. इन बाहरी ताक़तों का मकसद यह था कि अरब दुनिया को बर्बाद कर दिया जाए. अरब देशों में सबसे अधिक बर्बादी इराक की हुई है. पूर्व में यह क्षेत्र ज़ालिम हुक्मरानों की वजह से उग्रवाद का सामना करता रहा है और इराक इसका एक उदाहरण है.

कौन इराक़ को बर्बाद करना चाहता है

पिछले 35 वर्षों से बाथ पार्टी इराक की सत्ता पर काबिज़ रही. बाथ पार्टी की स्थापना एक गैर-मुस्लिम, गैर-अरब ने की थी. कमांडर के मुताबिक, बाथ पार्टी ज़ाइनिस्ट एजेंडे के साथ सत्ता में आई थी. इसका संस्थापक एक गैर अरब, यहूदी ज़ाइनिस्ट मिशेल अफ्लाक था. उसका इराक की एकता और अखंडता व इराकी अवाम की गरिमा से कोई लेना-देना नहीं था. सद्दाम हुसैन की सरकार के पतन के बाद इराक तानाशाही से लोकतान्त्रिक व्यवस्था में दाखिल हुआ और इराक की जनता भय के माहौल से बाहर निकली. हालांकि सद्दाम हुसैन के दौर में भी यहां लोकतंत्र था, लेकिन यह ऐसा लोकतंत्र था जिसमें सत्ता हर हाल में उन्ही की पार्टी के हिस्से में आती थी. ज़ाहिर है यह लोकतंत्र का बेहतर उदाहरण नहीं है. लिहाज़ा यह कहा जा सकता है कि इराकी जनता ने सद्दाम हुसैन के बाद लोकतान्त्रिक तरीके से अपने मसलों को हल करने में अधिक उत्साह दिखाया. बल्कि यूं कहा जाए कि इराकियों ने एक नई दुनिया का सफ़र तय किया, तानाशाही से लोकतंत्र की दुनिया का सफ़र. लेकिन इन सबके बावजूद इराक के अपने नस्लीय और क्षेत्रीय मसले थे. इन मसलों का हल देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी. कुछ ताकतें शिया और सुन्नी में नस्लीय झगड़े करवाकर गृह युद्ध का माहौल बनाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने इराक को तबाह करने के लिए दूसरा तरीका अपनाया. उन्होंने इराक के पश्चिमी हिस्से, जहां शिया और सुन्नी दोनों रहते हैं, में नस्लीय झगड़े कराने की साजिश रची. उन्होंने सुन्नियों में ये धारणा पैदा करने की कोशिश की कि इराक में शिया फौज है जो सुन्नियों पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है. उनकी ये कोशिशें बहुत हद तक सफल भी हुईं और इराक में कई तरह की समस्याएं खड़ी होने लगीं. इन ताकतों ने इराक में लोकतंत्र की बहाली को नुकसान पहुंचाया और इस विचार को जन्म दिया कि इराक पर शियाओं का कब्जा है. इस ख्याल से सुन्नियों के बीच बेचैनी और उलझन पैदा होने लगी. यहीं से उन ताकतों को बल मिलना शुरू हुआ, जो इराक को बर्बाद करना चाहते थे.

पश्चिमी इराक में हर फिरके के लोग (सुन्नी, शिया आदि) रहते हैं और उनमें वैचारिक मतभेद भी हैं. लिहाजा बाहरी ताकतों ने इस मतभेद का फायदा उठाने की योजना बनाई. अलकायदा जो इस इलाके में अपने कारनामों की वजह से बदनाम है, ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी. इराकी अवाम ने इस साजिश को जल्द ही भांप लिया और उनके ये प्रयास विफल हो गए. उसके बाद यही अलकायदा अमेरिका और इजराइल की मदद से आईएसआईएस के नए नाम से सरगरम हुआ.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

ह१द अलशाबी के कमांडर सैयद मोहम्मद अलतला गनी और सैयद अहमद मुसावी.

राम रहीम के ख़िलाफ़ सबसे पहले छपी रिपोर्ट

(03 दिसंबर-09 दिसंबर 2012)

पूरी रिपोर्ट के लिए पढ़िए पेज 7

आईएसआईएस के ख़िलाफ़ जनयुद्ध

पृष्ठ 1 का शेष

जिन क्षेत्रों में विवाद था, उसने वहां जाकर नौजवानों को बरगलाया और उनके दिमाग में जहर घोला. इसका प्रशिक्षण उन्होंने अफगानिस्तान में लिया था. उन्होंने शिया समुदाय के लोगों का कत्ल करना शुरू किया. यहां से हालात खराब होने शुरू हुए. इराक के इस पश्चिमी क्षेत्र में शिया बाहुल्य सेना मौजूद थी. इस पृष्ठभूमि में यह मुमकिन नहीं था कि अमेरिका सुन्नियों की कोई फौज तैयार करता. लिहाजा उसने स्थानीय ताकतों की मदद से अलकायदा का जाल बिछाना शुरू किया. उसने शियाओं के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया. इन तमाम कारगुजारियों में अमेरिका का समर्थन हासिल रहा. नतीजा ये हुआ कि यह इलाका देखते-देखते फौजी छावनी में बदल गया.

इन तमाम कारगुजारियों का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए माहौल तैयार करना था. गड़बड़ी पैदा करने वाले तत्व सीरिया से तलअफर होते हुए इराक के कई हिस्सों में पहुंच गए. इन तत्वों को सऊदी के शेखों और कतर की सहायता प्राप्त थी, जिसने उन्हें फलने-फूलने का खूब मौका दिया. इन तत्वों को इराक के शियाओं और सुन्नियों के बीच फूट पैदा करने में कामयाबी हासिल हुई. वहाबी विचार के नौजवानों में यह सोच पैदा की गई कि यदि इराक में शिया हुकूमत को मजबूती मिली तो ईरान के साथ मिलकर वो सऊदी अरब और इस्लामी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं. लिहाजा विश्व में शांति स्थापित करने और इस्लाम की बुनियाद को मजबूत करने के लिए इराकी सरकार के खात्मे के लिए संघर्ष करें. इस प्रचार से आईएसआईएस को मजबूती मिली और पूरा इलाका जिसमें इराक, सीरिया और तुर्की शामिल हैं, उनके प्रभाव में आ गया, जिससे यहां का माहौल खराब हो गया.

आईएसआईएस को मदद कहां से मिली

अब सवाल ये उठता है कि जॉर्डन, तुर्की, सीरिया और सऊदी अरब, जो इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश हैं, में आईएसआईएस का प्रभाव कैसे पहुंचा. सीरिया तो इराक की तरह ही आतंकवाद का शिकार हुआ. उसके पीछे भी वही कोशिशें हैं, जिसने नौजवानों को बरगलाकर आईएसआईएस को मजबूत करने का मौका दिया. आईएसआईएस के गिरोह में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग इस्लाम के गलत विश्लेषण के नाम पर जमा हुए. उनका कोई अपना देश और खास ठिकाना नहीं था. उनमें चेचेन्या, अफगानिस्तान, अमेरिका और यूरोप के नौजवान शामिल थे. उनका संबंध इराक से नहीं है. उन्होंने इस्लाम की अलग विवेचना की और नौजवानों को गुमराह कर अपने साथ कर लिया.

बहरहाल, आईएसआईएस इराक में दाखिल हुआ. वो अपने नेतृत्व और दल-बल के साथ यहां आया. उन्होंने यहां अमेरिकी और जाइनिस्ट (इजरायली) विचारों को मजबूती देने की बात की और इस्लाम की शक्ल बिगाड़ कर पेश की. उनके मुखिया ने ऐसी इस्लामी हुकूमत स्थापित करने की बात की, जो इस्लामी सोच से मेल नहीं खाती. हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकी कांग्रेस में यह स्वीकार किया कि हमारी कोताहियों की वजह से ही आईएसआईएस को मजबूती मिली है, जिससे अरब की एकता धराशाई हो गई और उन्हीं की वजह से इराक में गृह युद्ध के हालात पैदा हुए हैं. अरब स्प्रिंग (गुलाबी क्रांति) के बाद अरब देशों में क्रांति आई. अमेरिका ने वहां अपनी मर्जी की संस्थाएं स्थापित की, अपनी मर्जी की सरकार बनवाई और उनके मंत्री तय किए, उसी तरह इराक में भी क्रांति लाकर एक लोकतांत्रिक देश को इस्लामिक देश में बदलने की कोशिश की गई. जब इराकी जनता ने इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया, तो वहां आईएसआईएस को लाया गया, जिसने इराकी

अब सवाल यह पैदा होता है कि इसमें सऊदी अरब का कौन सा हित था? दरअसल सऊदी अरब एक ऐसा देश है, जो वहाबी विचार रखता है, जबकि इराक में लोकतंत्र है और यह पूरी तरह से वहाबी सोच के खिलाफ है. इराक के बाद ईरान भी उन देशों में से है, जो वहाबियत को पसंद नहीं करता. इसका साफ मतलब है कि सऊदी अरब के इस वहाबी विचारधारा के खिलाफ इराक और ईरान एकजुट हैं. वैसे इस क्षेत्र में इराक एकमात्र ऐसा देश है, जहां लोकतांत्रिक ढंग से वोटिंग कराकर सरकार चुनी जाती है. यही वजह है कि सऊदी अरब संपूर्ण इराक को अपनी विचारधारा के तहत करना चाहता है. इसी मकसद की प्राप्ति के लिए उसने अपने नौजवानों को तैयार किया और उन्हें सुन्नी बहुल मोसूल, बगदाद और समारा भेजा. ये सिर्फ इस वजह से हुआ, क्योंकि सऊदी अरब को अपने देश में जारी शाही हुकूमत पर खतरा नजर आ रहा

मरजई को पब्लिक मोबलाइजेशन के लिए बयान देना पड़ा. मरजई की धार्मिक हैसियत को समझने के लिए यह साफ करना जरूरी है कि इमाम जाफर शियाओं के बारहवें और आखिरी इमाम हैं. उनके बारे में ये मान्यता है कि वे जिंदा हैं, लेकिन वो हमारी नजरों से ओझल हैं. वे चार अयातुल्लाह के जरिए अपना पैगाम देते हैं. अयातुल्लाह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहते, बल्कि इमाम जाफर के निर्देश के मुताबिक ही अपना बयान या फतवा देते हैं. मरजई चारों अयातुल्लाह के नुमाइंदे होते हैं. इनके फतवे को मानना हरेक के लिए जरूरी है. शिया समुदाय के लोग उनकी बातों पर सौ फीसद अमल करते हैं. यदि वो कुछ करने का आदेश दें तो उसे करते हैं, न करने को कहें तो नहीं करते हैं. उनका बयान कुरान की बुनियाद पर होता है. मरजई का यह बयान तमाम इराकियों के लिए आह्वान के तौर पर होता है, जिसे स्वीकार करना या जिस पर

हमें नहीं पता कि इराक में 39 लापता भारतीय कहां हैं : हश्द अलशाबी

(चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने अपने इराक दौरे पर हश्द अलशाबी के दो प्रतिनिधियों से विस्तार से बातचीत की, जिसका मुख्य अंश यहां पेश किया जा रहा है.)

सवाल: अल बगदादी के बारे में कुछ बताएं. उसे किसने बनाया और क्या वो इराकी हैं?
जवाब: बगदादी इराक का रहने वाला है, लेकिन वो एक विदेशी एजेंट है.

सवाल: आईएसआईएस के जो लड़ाके आप की हिरासत में हैं, आप उनका क्या करते हैं या क्या करेंगे? क्या वे अब भी जेल में हैं या आपने उन्हें सजा दे दी है?
जवाब: जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो मानवाधिकार हनन के मामलों की जानकारी लेने, मरने वालों को एक दूसरे के हवाले करने के लिए रेड क्रॉस दोनों तरफ का जायजा लेता है. लेकिन आतंकवादियों के मामले में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं. जो लड़ाई के दौरान मारे गए, उन्हें हमने वहीं दफन कर दिया क्योंकि वे आतंकवादी थे, लेकिन जिन्हें हमने पकड़ा है, उन्हें हमने जेल में डाल दिया है. फ़िलहाल हम उनकी राष्ट्रीयता का पता लगा रहे हैं, ताकि उनके देश की सरकारों से उनके बारे में बातचीत की जा सके. उनके खिलाफ अदालत जो फैसला करेगी, उसी के मुताबिक उन्हें सजा दी जाएगी. चूंकि वे हत्यारे हैं, इसलिए उन्हें सजा हमारे अपने कानून के तहत दी जाएगी. इस्लामी कानून के मुताबिक दी जाएगी. इस्लामी कानून में इसका ज़िक्र है कि कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए.

सवाल: ये खबरें आईं कि कुर्द औरतों ने आईएसआईएस से जंग किया. इसमें कितनी सच्चाई है?
जवाब: कुर्द सेना ने आईएसआईएस से लड़ाई नहीं की. आईएसआईएस से उनका आमना-सामना हुआ, लेकिन उन्होंने जंग नहीं लड़ी. शायद वो तस्वीरें सीरिया से सम्बन्धित हों.

वे सीरिया की सेना से युद्ध लड़ रहे थे. हां, एज़ीदियों ने एक बहुत ही छोटे स्तर पर उनका मुकाबला ज़रूर किया.

सवाल: आपने जिस समूह का अभी ज़िक्र किया, उसे भारत में एज़ीदी के नाम से जाना जाता है. जिस एज़ीद ने इमाम हुसैन का क़त्ल किया, उससे इस समूह का कोई सम्बन्ध है क्या?
जवाब: नहीं, उससे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है. इन्हें एजीदी कहा जाता है. ये मआद बिन याबह के वंश से सम्बन्ध रखते हैं. हालांकि पहले वो मुस्लिम थे, लेकिन अब उनकी कोई किताब नहीं है, कोई पवित्र स्थल नहीं है, उनकी कुछ रस्में हैं, जो सिर्फ उनकी हैं. जैसा कि हमने कहा कि वे मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वे इराकी हैं और हम उनका आदर करते हैं. उनमें से कुछ हमारे साथ आईएसआईएस के खिलाफ जंग भी लड़ रहे थे.

सवाल : इराक में 39 भारतीय लापता हैं. यह माना जाता है कि वे आईएसआईएस केकब्जे में हैं. तो आप लोगों को उनके बारे में कोई जानकारी है कि वे ज़िंदा हैं या नहीं?
जवाब: हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वे ज़िंदा हैं या नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि 39 भारतीय इराक में लापता हैं.

सवाल: क्या वे तलाफा में नहीं हैं? क्योंकि ये ऐसा इलाका है जो आईएसआईएस के कब्जे में है.
जवाब: हो सकता है कि वे वहां हो और यह भी हो सकता है वहां न हों.

अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया.

आईएसआईएस की मदद किसने की, के बारे में यह कहा जा सकता है कि उनके मददगारों में अमेरिका सर्वोपरि था. उन्हें सऊदी अरब और कतर से आर्थिक सहायता मिली. जाहिर है कि यह सब खुफिया तौर पर हो रहा था. इसका सबूत यह है कि आईएसआईएस के युद्ध क्षेत्र से ऐसी गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिन पर सऊदी अरब और कतर के नंबर प्लेट लगे हुए हैं. इसके अलावा यहां मारे गए या पकड़े गए लड़ाकों के पास सऊदी अरब और कतर के पहचान पत्र मिले हैं और ऐसे हथियार भी मिले हैं, जिनपर सऊदी अरब के निशान मौजूद हैं. इससे यह जाहिर होता है कि इन तत्वों की मदद कौन कर रहा है? दरअसल मकसद यह था कि जब ये पश्चिमी इराक पर पूरी तरह से कब्जा जमा लें, तो इराक को दो हिस्सों में बांट दिया जाए. इस तरह से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि उनका मकसद इराकी जनता को शिया और सुन्नी में बांटने का नहीं था, बल्कि इराक को दो हिस्सों में बांट कर एक हिस्से पर कब्जा जमाना था.

था. वे इराक की तरक्की और लोकतांत्रिक शक्ति से भयभीत थे. ये बातें यूं ही नहीं कही जा रही है, बल्कि लड़ाई के दौरान गिरफ्तार कैदियों से ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे इस बात का पता चलता है.

पब्लिक मोबलाइजेशन के पीछे कौन

पश्चिमी इराक स्थित मोसूल शिया बहुल क्षेत्र है. यहां सुन्नियों की भी आबादी है. यहां आईएसआईएस ने धावा बोल दिया और बगदाद के आसपास उनकी आहट सुनाई देने लगी. यह खौफ जाहिर होने लगा कि वे बगदाद में भी दाखिल हो जाएंगे. उन्हें रोकने के लिए सरकार की तरफ से ठोस उपाय नहीं किए जा रहे थे. अगर वे बगदाद में दाखिल हो जाते, तो इराकियों खासतौर पर शियाओं का कत्लेआम कर देते. इराक की राजधानी बगदाद पर उनके कब्जे के बाद पूरी दुनिया में यह संदेश जाता कि इराक पर आईएसआईएस की हुकूमत है. लिहाजा आईएसआईएस को रोकना बहुत जरूरी था. लेकिन ये काम कैसे हो, यह सवाल बरकरार था. जब सरकार की तरफ से नाउम्मीदी नजर आने लगी, तब शिया धर्मगुरु

अमल करना इराकियों के हर समुदाय के लिए अनिवार्य होता है, चाहे वो सुन्नी हों या शिया या फिर गैरमुस्लिम ही क्यों न हों. मरजई के इस बयान को नजफ और दक्षिणी इराक के लोगों ने फौरन मान लिया और इराक की रक्षा के लिए एकजुट हो गए. दरअसल हश्द अलशाबी (सेना की आम भर्ती या पब्लिक मोबलाइजेशन) के लिए आदेश मरजई की तरफ से ही आते थे. उनका आदेश था कि इधर-उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है. उनसे भयभीत नहीं होना है. करबला में जुमे की नमाज के खुतबे में अयातुल्लाह की तरफ से आम भर्ती के लिए 14 निर्देश दिए गए कि कैसे आदेश लेना है, कैसे लोगों को बचाना है आदि-आदि. हर जुमे की नमाज के साथ लोगों के लिए निर्देश जारी किए जाते थे. दरअसल ये निर्देश इस्लाम की सही व्याख्या पेश कर रहे थे. सही इस्लाम यही है कि शिया, सुन्नी या गैरमुस्लिमों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो. इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए इराकियों ने अपना घर-बार छोड़ा और जंग लड़ी. उन्होंने आईएसआईएस के अत्याधुनिक हथियारों के मुकाबले यह लड़ाई पिस्तौल और छोटे हथियारों (शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 09 अंक 28
11 सितंबर- 17 सितंबर 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

आईएसआईएस के ख़िलाफ़ जनयुद्ध

पृष्ठ 2 का शेष

से लड़ी. उन्होंने यह कुर्बानी किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं दी. वो सिर्फ ये चाहते थे कि देश के नागरिकों की रक्षा करें. यही चाह हर नौजवान में थी और वो इस यकीन के साथ आगे बढ़े कि जंग में उन्हें जीत हासिल होगी. उनका यह विश्वास बहुत ही अटल था, क्योंकि इमाम हुसैन ने चार हजार दुश्मनों का मुकाबला 72 लोगों के साथ मिलकर किया था. आज नौजवान इसी विचार को अपनाने जा रहे थे. आम भर्ती के एक प्रतिनिधि ने बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने गांधी की इस बात से भी सबक लिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि हमने इमाम हुसैन से सीखा कि कैसे हताहत होकर भी जंग जीता जा सकता है. यहां के लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी मुसलमान नहीं थे, मगर उनको यकीन था कि इमाम हुसैन की राह पर चलकर कामयाबी हासिल की जा सकती है. इन महान व्यक्तियों के विचारों से हौसला पाकर इराकी नौजवानों ने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया. इसका नतीजा यह हुआ कि आईएसआईएस के कदम आगे बढ़ने से रुक गए. इन नौजवानों को जनता, सरकार और इराकी फौज की मदद हासिल रही. तुर्की और ईरान जैसे देशों ने भी उनका विश्वास बढ़ाया और इस तरह एक आम भर्ती की सेना तैयार हुई.

हश्द अलशाबी ने कैसे दी टक्कर

इस सेना ने आईएसआईएस का पूरी ताकत से मुकाबला किया. लड़ाई से पहले रणनीति बनाई गई कि कैसे आईएसआईएस का मुकाबला किया जाए. आईएसआईएस से इराक की जनता, पुलिस और आम भर्ती की सेना के नौजवानों ने हर स्तर पर लड़ाई लड़ी. आम भर्ती की सेना ने जंग के मैदान में अपनी ताकत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. इस सेना का मकसद यह था कि मरजई के आदेश को पूरा करते हुए इसकी ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए, ताकि वहां विदेशी दखलंदाजी रोकी जा सके. इसलिए कर्बला में जुमे की नमाज के मौके पर मरजई के आदेश को पढ़कर सुनाया गया कि कैसे मुल्क की हिफाजत के लिए अयातुल्लाह यानि मरजई के आदेशों को लागू यानि जमीनी और हवाई हमलों में समन्वय स्थापित करना. इसके अलावा आईएसआईएस की आपूर्ति के रास्ते को काटना भी शामिल था. इस सिलसिले में इराकी सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आईएसआईएस को अमेरिका की तरफ से आपूर्ति जारी थी. उन पर हवाई हमला करने से अमेरिका ने मना कर दिया था. आम भर्ती की सेना ने सुन्नी इलाकों के लिए अपनी रणनीति तैयार की, ताकि आईएसआईएस उनके क्षेत्र में कदम न जमा सके. इस सेना ने आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला कर तक आम यातायात भी बिल्कुल ठप पड़ा था. इसके लिए रणनीति तैयार की गई और हैरानी की बात यह है कि आम भर्ती की सेना ने तीन-चार दिन में ही आईएसआईएस के दबदबे को समाप्त कर दिया. अंदाजा था कि इस इलाके को फौजी कार्रवाई से आजाद कराने में नौ से दस माह लग जाएंगे.

इराक़ी जनता अब कमज़ोर नहीं रही

सवाल यह है कि आखिर इस कार्रवाई में आईएसआईएस को सीरिया में दाखिल होने से कैसे रोका गया? इस सिलसिले में आम भर्ती की सेना ने तमाम रास्तों और मदद पहुंचाने वाले ठिकानों को घेर लिया था, जिससे आईएसआईएस की गतिविधियां थम गईं. यह बात भी गौर करने लायक है कि सीरिया के रास्ते पर इस्माइलिया के करीब अमेरिकी वायु सेना ने आम भर्ती की सेना पर हमला कर दिया, जिसमें 50 लोगों की जानें गईं. अमेरिका से जब इसकी शिकायत की गई तो उसका जवाब था कि निशाना लगाने में उनसे चूक हो गई. बहरहाल पिछले दिनों तलअफर को आईएसआईएस से आजाद कराने की मुहिम चली. यह मुहिम प्रधानमंत्री एबादी और आम भर्ती की सेना के बीच एक समझौते के तहत शुरू हुई. इस समझौते के तहत देश की सभी फौजें शामिल हुईं. तलअफर आईएसआईएस के कब्जे से आजाद हो चुका है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब इराक से आईएसआईएस का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा.

ये भी आशंका जताई जा रही है कि आईएसआईएस के लड़ाके रमादी, फलूजा, पश्चिमी इराक में कहीं-कहीं छुपे हो सकते हैं और भविष्य में कुछ मुश्किलें पैदा कर सकते हैं. मौजूदा स्थिति यह है कि अमेरिका ने अब यह सोचना शुरू कर दिया है कि अल जवाहिरी, अल रजाकावी, अल कायदा और आईएसआईएस के बाद उसकी रणनीति क्या होगी? मौजूदा स्थिति में सऊदी अरब और यूएई में बदले की भावना पैदा हुई है. लिहाजा उनकी मदद से इराक में फिर अशांति फैल सकती है. आम भर्ती सेना की कामयाबी के बाद भरोसा किया जा सकता है कि इराक के पास बड़ी फौजी ताकत है और वो किसी भी साजिश को कुचलने की क्षमता रखता है. बहरहाल आम भर्ती की सेना को मदद पहुंचा कर इराक के प्रधानमंत्री और हुकूमत ने बुलंद हौसले का सबूत दिया और सेना को बड़ी ताकत बना दी.

यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आईएसआईएस से पहले अलकायदा की शक्ल में यहूदियों ने मोसूल के कबीलों में और व्यापारियों ने तल अफर के अलग-अलग इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत की. वे फिलीस्तीन की तरह यहां भी गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने की कोशिश में लगे रहे. ये लोग इराक के असली नागरिक नहीं हैं, बल्कि 1973 की जंग के दौरान यहां आकर बस गए थे और यहां अब व्यापार करते हैं. मोसुल में भी यहूदी रहते हैं, लेकिन वे इस देश के असली नागरिक नहीं हैं. बहरहाल, आम भर्ती की सेना अब इतनी ताकतवर जरूर हो गई है कि वो किसी भी साजिश का सर कुचल सकती है.

ये सच्चाई जो अभी आपने पढ़ी, दुनिया में लोगों को नहीं मालूम है. दुनिया को मालूम भी नहीं होगी, क्योंकि प्रचार तंत्र इतना बड़ा भ्रम पैदा करता है, जिसका कोई उदाहरण नहीं मिलता. मैं भी यहां ये सोच कर आया था कि इराकी सेना ने दाइश को पीछे धकेला है. लेकिन यह देखकर मेरा जनता के प्रति विश्वास और प्रगाढ़ हुआ कि अगर जनता चाहे तो किसी भी स्थिति का सामना कर सकती है. आमने-सामने के हथियारबंद युद्ध में, शायद चीन और वियतनाम के बाद, ये पहला उदाहरण है, जहां इराक की जनता ने सेना की काहिली के खिलाफ, सेना की हथियार डाल देने की कायराना मानसिकता के खिलाफ खड़े होकर, शिया और सुन्नी का भेद मिटाकर, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का भेद मिटाकर, अपने हाथ में छोटे-छोटे हथियार लिए और अपनी शहादत दी. दाइश को हर जगह घेर कर रखा और सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया. जनता द्वारा युद्ध लड़ने और जनता द्वारा युद्ध जीतने की यह अद्भुत मिसाल है. रिपोर्ट के अंत में मैं इराक की आम जनता, वहां के नौजवान और हश्द अलशाबी के तमाम सिपाहियों को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने बिना किसी देश की मदद के, बिना बड़े हथियारों के, सिर्फ अपना देश और संस्कृति बचाने के लिए शिया, सुन्नी, मुस्लिम और गैरमुस्लिम का भेद समाप्त कर, एक ऐसा युद्ध लड़ा, जिसका इतिहास जब लिखा जाएगा, तब उस इतिहास को पढ़ने वाले इराकी जनता के प्रति श्रद्धा से अपना सर अवश्य झुकाएंगे. ■

editor@chauthiduniya.com

इराक़ में आईएसआईएस का आख़िरी क़िला भी ध्वस्त

27 अगस्त इराक के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया. उस दिन इराकी सेना और हश्द अलशाबी के जवानों ने आईएसआईएस के कब्जे में इराक के आखिरी सबसे बड़े शहर तलअफर पर तीन साल बाद फिर से अपना कब्जा जमा लिया है. 8 दिनों तक चली इस जंग में तलअफर पर आईएसआईएस का कब्जा लगभग खत्म हो गया है. अब वे कुछ छोटे-छोटे इलाकों में सिमट कर रह गए हैं. इस लड़ाई में इराकी सेना और हश्द अलशाबी के जवानों ने तलअफर और उसके आसपास के 29 ठिकानों को आईएसआईएस के कब्जे से छुड़ा लिया. गौरतलब है कि आईएसआईएस ने दो दिन की लड़ाई के बाद 16 जून 2014 को तलअफर पर कब्जा कर लिया था. आईएसआईएस इस शहर को सीरिया और मोसूल के लिए सप्लाई रूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था. तलअफर की हार के बाद आईएसआईएस ने यहां से 11 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अल अयादा इन्क्लेव और उसके आसपास के अन्य गांवों में पनाह ली है. अब इराकी सेना के निशाने पर आईएसआईएस का यही आखिरी इलाका बच गया है. खबरों के मुताबिक, तलअफर की लड़ाई में आईएसआईएस के कुल 302 आतंकी मारे गए. इस लड़ाई में 2000 आईएसआईएस आतंकियों का मुकाबला 50 हजार इराकी सैनिकों के साथ हुआ. जाहिर है, मोसूल में इसी साल जून महीने में आईएसआईएस को शिकस्त मिली थी. अब तलअफर की हार आईएसआईएस की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी.

करना है. इस मौके पर उन शिया शहीदों को भी याद किया गया, जिन्होंने देश के नाम पर कुर्बानी दी थी.

इसके बाद पश्चिमी इराक के लोगों ने शिया फौज के उद्देश्यों और कुर्बानियों को महसूस किया और ये समझा कि शियाओं की इस क्षेत्र पर कब्जा करने की बातें केवल दुष्प्रचार थीं. इस दौरान अमेरिका ने वहां के कबीलों में हश्दुल शबड़ी या आम भर्ती की सेना के बारे में दुष्प्रचार शुरू कर दिया, जिसका समर्थन कुछ सुन्नी नेताओं ने भी किया. लेकिन यह दुष्प्रचार बहुत दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि लोगों ने देखा कि सीरिया के कुछ इलाकों और मोसूल में सुन्नी भी बड़ी संख्या में आईएसआईएस के जुल्म का शिकार हो रहे हैं. लिहाजा सबने मिलकर सेना का साथ दिया और आईएसआईएस को बगदाद की तरफ बढ़ने से रोक दिया. इस सिलसिले में हाजी सईद ने वहां का आंखों देखा हाल कुछ इस अंदाज में बताया कि आम भर्ती की सेना जब इस क्षेत्र में दाखिल हुई, तो सुन्नियों ने उनका स्वागत किया और उनके कंधे से कंधा मिलाकर आईएसआईएस को भगाने में मदद की. गौरतलब है कि आईएसआईएस से मुकाबला करने के लिए अमेरिका या अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कोई मदद नहीं मिल रही थी. आम भर्ती की सेना को प्रशिक्षण देने के लिए ईरान के विशेषज्ञों ने कदम बढ़ाया और इराक के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए. इन्हीं विशेषज्ञों ने उन्हें हरेक मोर्चे पर लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया. यहां यह बताना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय गठबंधन या अमेरिकी फाइटर्स विमानों से हश्द अलशाबी को कोई मदद नहीं मिल पा रही थी. जब हश्द अलशाबी ने मोर्चा संभाला, तब अमेरिका ने फिर एक खेल खेला और कहा कि अंतरराष्ट्रीय गठबंधन और अमेरिका हश्द अलशाबी की मदद करना चाहते हैं और हर मोर्चे पर उसके साथ रहना चाहते हैं. लेकिन हश्द अलशाबी अपने दम पर लड़ना चाहता था. आम भर्ती की सेना को कई चरणों में प्रशिक्षित किया गया. पहला चरण था सेना को प्रशिक्षण देना. दूसरा चरण आईएसआईएस के हमलों के तरीकों पर विचार करना और रणनीति तैयार करना उनको तबाह करना शुरू कर दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया. तलअफर में आईएसआईएस को सीरिया और तुर्की के रास्ते मदद पहुंचाई जा रही थी. आम भर्ती की सेना के लिए ये एक मुश्किलों भरा दौर था. प्रधानमंत्री से ये शिकायत की गई कि सीरिया के रास्ते पर तलअफर से पशमर्ग तक आईएसआईएस अपना मजबूत ठिकाना बनाए हुए है. जब सेना उसको तोड़ना चाहती है तो उसे जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है. तलअफर से सीरिया

लालू का जादू

सरोज सिंह

इसे जादू नहीं तो फिर क्या कहिएगा, 17 जिले बाढ़ से प्रभावित, सत्ता जाने का टटका गम और लगभग पूरे परिवार पर चारा से लेकर लारा घोटाले का कानूनी घेरा. इसके बावजूद अगर पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान 27 अगस्त को लालू के एक ललकार पर लगभग भर जाता है तो यकीन मानिए यह लालू का जादू ही है. लालू प्रसाद ने यह कारनामा पहली बार नहीं किया है. ऐसे कई मौके आए जब यह कह दिया गया कि लालू प्रसाद अब बिहार की राजनीति में बड़े खिलाड़ी नहीं रह गए, लेकिन हर बार लालू प्रसाद ने अपने आलोचकों को निराश ही किया है. प्रदेश की राजनीति पर बारीकी से नजर रखने वाले कहते हैं कि आप लालू प्रसाद से राजनीतिक तौर पर नफरत कर सकते हैं पर उन्हें नकार नहीं सकते. बिहार का जो सामाजिक और जातीय ताना-बाना है उसमें लालू प्रसाद की भूमिका और उनकी ताकत पिछले दो दशकों से सब देख और समझ रहे हैं. किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले यह आकलन कर लेना जरूरी होगा कि लालू के समर्थक कितने बदल रहे हैं? क्या सूबे का मौजूदा राजनीतिक ताना-बाना लालू समर्थकों को बदलने का मौका दे रहा है या फिर उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि चाहे लालू में लाख बुराई हो पर फिलहाल उनके पास इससे बेहतर विकल्प नहीं है. लालू प्रसाद ने समाज के जिस तबके को बोलने और कुछ पाने का मौका दिया, वह समाज चाहे अनचाहे आज भी लालटेन थामे गांधी मैदान में दिख रहा है. बिना लाग लपेट के कहा जाए तो यह बात सोलह आने सच है कि यादवों और मुसलमानों का पूरा समर्थन आज भी लालू प्रसाद को मिल रहा है जो 27 अगस्त को भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली में भी दिखा. लालू प्रसाद की इस रैली का देश और सूबे की राजनीति पर असर पड़ना तय है क्योंकि इस रैली ने कई राजनीतिक लक्ष्यों को एक साथ भेद दिया है.

लालू प्रसाद अमूमन दो मौकों पर रैलियां बुलाते हैं. जब वे राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत स्थिति में हों या फिर तब, जब संकट के समय उन्हें अपनी राजनीतिक ताकत देश और सूबे में अपने विरोधियों को दिखाने की जरूरत हो. लालू की यह सातवीं रैली थी. इसके पहले वे छह रैलियां कर चुके हैं. उनकी सबसे बड़ी रैली 1997 की महागरीब रैला थी. उतनी बड़ी रैली लालू दोबारा नहीं कर सके. दूसरे दल भी उतनी भीड़ नहीं जुटा सके. 2013 में नरेंद्र मोदी की रैली में जुटी भीड़ उसी के आसपास थी, जब उस रैली में बम धमाका हुआ था. 2003 में लालू ने तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली की थी. यह दुनिया की अनूठी रैली थी, जिसमें लोग लाठी लेकर आए थे. 2007 में चेतावनी रैली और 2012 में परिवर्तन रैली लालू कर चुके हैं. उनकी पहली रैली 1995 की गरीब रैली थी. जनता दल से अलग होने के बाद उन्होंने यह रैली बुलाई थी.

जब हम भाजपा भगाओ, देश बचाओ रैली की बात करते हैं, तो हमें इसकी पृष्ठभूमि पर भी गौर करना होगा. यह वह समय था जब देश की राजनीति में छाने के लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में होड़ मची थी. नीतीश कुमार ने जदयू की कमान अपने हाथ में लेकर देश का दौरा शुरू कर दिया था और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का केंद्र बनने का जतन करने लगे. गाहे बगाहे चर्चा भी होने लगी कि 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं. हालांकि नीतीश कुमार ऐसी खबरों का खंडन करते रहे पर उनके समर्थक और कई विश्लेषक नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई 2019 में बताने और दिखाने लगे. लालू प्रसाद को यही बात नागवार गुजरी. इसकी एक वजह यह भी थी कि जब बिहार में 2015 में नीतीश कुमार की सरकार महागठबंधन के बैनर तले बनी तो उसी समय लालू प्रसाद ने यह ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार बिहार की बागडोर संभालेंगे और मैं पूरे देश में घूम-घूम कर नरेंद्र मोदी को बेनकाब करने का काम करूंगा. जैसे ही नीतीश कुमार के कदम बिहार के बाहर पड़ने लगे, लालू प्रसाद के कान खड़े हो गए. जब नीतीश कुमार ने खुद को पार्टी का अध्यक्ष बनवा लिया, तब लालू प्रसाद और भी चौकन्ने हो गए. अब तक वह इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की दखलंदाजी अब रुकने वाली नहीं है और देर-सवेर दिल्ली और पटना दोनों में ही नीतीश कुमार का चेहरा नजर आने लगेगा. इसी पृष्ठभूमि में लालू प्रसाद ने राजगीर में आयोजित अपनी पार्टी के कार्यक्रम में 27 अगस्त की रैली का एलान कर दिया. लालू प्रसाद ने कहा कि 27 अगस्त की यह रैली विपक्षी एकता की बुनियाद रखेगी. इस रैली से जो संदेश जाएगा उससे पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हो जाएगी. गौरतलब है कि जिस समय रैली का एलान किया गया था उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता थे और बिहार में बाढ़ भी नहीं थी. रैली का एकमात्र मकसद यह था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विपक्षी मुहिम छेड़नी है, उसके अगुवा लालू प्रसाद ही नजर आएं. लालू प्रसाद चाहते थे कि नीतीश कुमार ने दिल्ली के बाहर जो छल-कूद मचाई है, उसका विसर्जन इस रैली में हो जाए और रैली से यह संदेश निकले कि लालू प्रसाद ही सारे विपक्षी दलों को भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट करने की ताकत रखते हैं. लेकिन रैली की तारीख आते-आते बिहार की राजनीति पूरी तरह से करवट ले चुकी थी. राजद सत्ता से बाहर हो चुका था और सूबे में जदयू और भाजपा की सरकार बन गई थी. प्रदेश का 17 जिला बाढ़ से प्रभावित था. लालू और उनके परिवार पर चारा से लेकर लारा घोटाले का शिकंजा कसा जा चुका था. जाहिर है रैली होने तक हालात काफी बदल चुके थे. लेकिन लालू प्रसाद ऐसी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में माहिर हैं. अपने को चारों तरफ से घिरा देख लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटों को जिलों में भेजा और पटना व रांची में बैठकर खुद पूरी कमान अपने हाथ में ले ली.

लालू को अब तक पता लग गया था कि जो रैली पहले विपक्षी एकता का अगुवा बनने के मकसद से होनी थी, उसे अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का हथियार बनाना है. विपक्षी एकता प्राथमिकता में दूसरे स्थान पर आ गई और सारा ध्यान राजद और अपने बेटों को स्थापित करने में लगा दिया गया. तेजस्वी और तेजप्रताप पटना से बाहर निकले और अपने समर्थकों से कहा कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया. लालू बार-बार अपील करते रहे कि

रैली का दूसरा मकसद था अपने दोनों बेटों को स्थापित करना. लालू ने तेजस्वी यादव को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया. तेजप्रताप का भाषण ठेठ गंवई अंदाज में करवाया गया.

मतलब लालू के चाहने वाले जिस अंदाज में उन्हें दो दशकों से सुनते और देखते आए हैं, उसकी झलक तेजप्रताप में दिखी. तेजप्रताप ने कहा कि वे कृष्ण हैं और तेजस्वी अर्जुन और हम दोनों भाई मिलकर कौरवी सेना का नाश कर देंगे. इससे लालू ने यह संदेश भी साफ दिलवा दिया कि दोनों भाइयों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और दोनों साथ-साथ हैं.

गरीबों और कमजोर वर्गों के खिलाफ आरएसएस और भाजपा ने साजिश रची है और नहीं चेते तो पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा. लालू को इस बात का अहसास था कि बाढ़ के कारण सीमांचल और चंपारण के इलाके से उनके समर्थकों को आने में दिक्कत होगी इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान मगध और पटना के आस पास के इलाकों में लगाया.

26 अगस्त की रात से ही राजद समर्थक पटना में जुटने लगे. जैसे ही यह खबर राबड़ी निवास तक पहुंची, लालू अपने पुराने रंग में दिखने लगे. जनता का नब्ज टटोलने में माहिर लालू प्रसाद ने एलान कर दिया कि रैली में पूरा पटना राजद समर्थकों से भर जाएगा. देर रात तक लालू अलग-अलग जिलों से फीडबैक लेते रहे और जब तसल्ली हो गई कि कल सब कुछ ठीक रहेगा तभी सोने गए.

27 तारीख को गांधी मैदान का पूरा शो लालू प्रसाद के नाम रहा. रैली का पहला मकसद था अपनी ताकत विरोधियों को दिखाना. अपने पहले मकसद में लालू कामयाब रहे. भीषण बाढ़ के बावजूद प्रभावित जिलों से लोग रैली में आए. संख्या भले ही कम थी पर उन जिलों की उपस्थिति ने यह जता दिया कि वे लोग हर हाल में लालू के साथ हैं. रैली में मुसलमानों की संख्या कम दिखी और इसकी एकमात्र वजह यह थी कि सीमांचल और चंपारण के ज्यादातर जिले बाढ़ से प्रभावित थे. रैली में आए बहुत सारे लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि पहली बार वे लोग आपस में चंदा करके पटना आए हैं. अमूमन हर बार पार्टी या जिले के प्रभावी नेता रैली में आने-जाने का इंतजाम करते रहे हैं. लेकिन यह पहली बार हुआ कि बहुत सारे लोग अपनी व्यवस्था से पटना आए. लालू प्रसाद ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया और इसके लिए अपने समर्थकों को धन्यवाद कहा. रैली में जुटी भीड़ को लेकर अलग-अलग राय है, लेकिन किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इस रैली का आयोजन किया गया. यह एक बार फिर साबित हुआ कि सूबे के ज्यादातर यादव और मुसलमान लालू पर भरोसा करते हैं.

रैली का दूसरा मकसद था अपने दोनों बेटों को स्थापित करना. लालू ने तेजस्वी यादव को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया. तेजप्रताप का भाषण ठेठ गंवई अंदाज में करवाया गया. मतलब लालू के चाहने वाले जिस अंदाज में उन्हें दो दशकों से सुनते और देखते आए हैं, उसकी झलक तेजप्रताप में दिखी. तेजप्रताप ने कहा कि वे कृष्ण हैं और तेजस्वी अर्जुन और हम दोनों भाई मिलकर कौरवी सेना का नाश कर देंगे. इससे लालू ने यह संदेश भी साफ दिलवा दिया कि दोनों भाइयों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और दोनों साथ-साथ हैं.

रैली का तीसरा मकसद था कुछ और दलों को राजद के साथ जोड़ने की बिसात बिछाना. लालू अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल माय के भरोसे सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है. इसलिए राबड़ी देवी ने अपने भाषण में जीतन राम मांझी को बेदखल करने का जिक्र किया.

उन्होंने कहा कि मांझी को हमने बाहर से समर्थन दिया, पर नीतीश कुमार को अपने अलावे कोई बर्दाश्त नहीं है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्नेह देनेवाली पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी उन पर काफी आक्रोशित दिखीं. राबड़ी ने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि जिसने उनके डीएनए में खोट बताया था उसके साथ वे चले गए. जनता ने भी अपना नाखून-बाल भेजा. न जाने नाखून बाल को गड्ढे में फेंका कि क्या किया? नीतीश कुमार से देखा नहीं गया. तेजस्वी पर झूठा केस कराया गया, जबकि नीतीश कुमार के खिलाफ चल रहे मुकदमे को छिपाकर रखा है. भोजपुरी कहावत की चर्चा करते हुए कहा, चलनिया दूसे सूप के जेकरा अपने बहत्तर छेद. उन्होंने कहा कि चारा चोर लालू को कहा जाता है. सृजन घोटाला हुआ है. तीन चार जिला में निकला है. सेम केस है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। नीतीश कुमार व सुशील कुमार मोदी काहे नहीं गद्दी छोड़ेंगे. नालंदा जिला के एक जाति की बहाली हो रही है. नीतीश का यह सब खेल तमाशा है. हमारे परिवार पर केस कराकर डरवाना चाहता है. जहां बोलाएगा, वहां जाएंगे. हम डरनेवाले नहीं हैं. जो बिहार की जनता कहेगी, वही करेंगे. हम तो न्योता देते हैं सीबीआई वाले को। वे घर में बैठे और जांच करे. घर में क्या मिलेगा? ठेंगा मिलेगा. राबड़ी ने कहा कि रात भर में ही नीतीश कुमार व सुशील मोदी का शादी ब्याह हो गया. सही में नीतीश का नाम पलटू राम रखा गया. राबड़ी देवी बोलीं कि कवन चेहरा लेकर जइबअ नीतीश जनता के बीच. उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े. करेजा (कलेजा) नहीं है. भाजपा आरोप लगाया तो डर गया. अब जदयू भी नहीं रहा. नीतीश न घर के न घाट के रहेंगे. दो-तीन माह में क्या होगा उसका देखिएगा. लालू प्रसाद ने पासी समाज पर हो रहे अत्याचार का जिक्र अपने भाषण में किया और कहा कि मैंने ताड़ी को टैक्स फ्री कर दिया पर नीतीश ने ताड़ी पर रोक लगा दिया. हमारी सरकार बनेगी तो ताड़ी को फिर टैक्स फ्री कर देंगे. लालू ने भाजपा व नीतीश कुमार के खिलाफ सभी का सहयोग मांगा. मतलब साफ है कि राबड़ी और लालू प्रसाद ने वैसे लोगों को अपने पास आने का न्योता दिया जो भाजपा और नीतीश के खिलाफ हैं. राबड़ी और लालू के इस न्योते का असर आने वाले दिनों में दिखना तय है.

रैली का चौथा मकसद था विपक्षी एकता की बुनियाद रखना तो इसमें में बहुत हद तक लालू प्रसाद कामयाब ही रहे. भले मायावती ने साथ नहीं दिया पर सोनिया और राहुल गांधी ने अपना संदेश भिजवा दिया. झारखंड से हेमंत सोरन और बाबूलाल मरांडी का एक साथ आना बड़ी बात है. अखिलेश आए भी और लालू प्रसाद के कायल होकर गए. सबसे बड़ी बात यह रही कि ममता बनर्जी पूरे जोश के साथ रैली में आईं और जमकर लालू की तारीफ की. जयंत चौधरी और तारिक अनवर ने भी लालू का साथ दिया. शरद यादव ने रैली में आकर साफ कर दिया कि वे डरने वाले नहीं और नीतीश कुमार को चैन से रहने नहीं देंगे. कहा जाए तो यह रैली हर लिहाज से लालू के मकसद को पूरा करने में सफल रही. हालांकि लालू के विरोधी कह रहे हैं कि यह लालू की सबसे कमजोर रैली थी. खैर, बहस तो अब इस बात पर होनी चाहिए कि लालू ने रैली के माध्यम से जो राजनीतिक बिसात बिछाई है और जो चालें चली हैं, उसका जबाव लालू विरोधी आने वाले दिनों में किस तरह देंगे. शुरुआती झटकों के बाद लालू आगे बढ़ चुके हैं, 2019 की जंग होनी है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और नीतीश कुमार लालू को रोकने के लिए अगला क्या कदम उठाते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

‘चौथी दुनिया’ ने दो महीने पहले ही बिखेर दी थीं हवाला सरगना मोईन कुरैशी के तिलस्म की खीलें

कुरैशी को बचाने में लगे हैं हितैषी

मोईन कुरैशी की गिरफ्तारी से छटपटाए नेता-नौकरशाह

प्रभात रंजन दीन

काले धन को सफेद करने वाला अंतरराष्ट्रीय धंधेबाज मोईन अख्तर कुरैशी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में कुरैशी ने वे सारे तथ्य उगल दिए, जो अभी तक सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छानबीन का हिस्सा थे. ‘चौथी दुनिया’ ने 31 जुलाई 2017 के अंक में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला धंधे के सरगना मोईन कुरैशी की दमकती तिलस्मी दुनिया की खीलें बिखेरी थीं, जिनमें नेता, नौकरशाह, फिल्मकार और संवैधानिक कुर्सी पर धंसने वाले राज्यपाल तक के नाम सार्वजनिक स्तर पर छितरा गए थे. मोईन कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद अब सब लोग बताने, दिखाने और छापने लगे कि हवाला सरगना को संरक्षण देने और उसकी मदद से कालाधन पचाने में केंद्र से लेकर यूपी तक के बड़े नेता और सीबीआई से लेकर यूपी पुलिस तक के बड़े अधिकारी लिप्त रहे हैं. लेकिन नाम बताने से वे अब भी परहेज कर रहे हैं. ‘चौथी दुनिया’ उन सबके नाम दो महीने पहले छाप चुका है.

मीट कारोबार के बहाने हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा दुनियाभर में फैलाने वाले मोईन कुरैशी को पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट) ने गिरफ्तार किया. कुरैशी ने हवाला कारोबार के जरिए दुनिया के कई देशों में अकूत काला धन भेजा. यह धन नेताओं, नौकरशाहों और व्यापारिक हस्तियों के थे. इससे कुरैशी ने भी जबरदस्त कमाई की. प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2015 में ही कुरैशी के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध कानून (फेमा) के तहत जांच शुरू की थी. आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर यह जांच शुरू हुई थी. इन दस्तावेजों में कुरैशी और उसकी पचासों कंपनियों के हवाला कारोबार में लिप्त होने और फेमा कानून का उल्लंघन करने के सबूत मिले थे. इस बात के भी सबूत मिले थे कि देश की नामचीन हस्तियां हवाला सरगना मोईन कुरैशी के इशारे पर नाचती हैं.

मोईन कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद अब जल्दी ही सीबीआई के एक और पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने वाली है. मोईन कुरैशी और रंजीत सिन्हा के गहरे सम्बन्ध रहे हैं. इसी मामले में सीबीआई के एक और पूर्व निदेशक एपी सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. जांच के दायरे में सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक व यूपी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जावीद अहमद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, प्रसिद्ध फिल्मकार मुजफ्फर अली और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) के ही एक आला अधिकारी राजेश्वर सिंह भी हैं, जिनके मोईन कुरैशी से जुड़े होने की पृष्ठभूमि सामने आई है. मोईन से जुड़े कांग्रेसी नेताओं की तो लंबी फेहरिस्त है. इन सबकी जांच हो रही है. कुरैशी के मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के धंधे के तार इतने फैले हैं कि दिल्ली, मुंबई, यूपी, कोलकाता, कर्नाटक, सीबीआई, ईडी से लेकर इंटरपोल तक जाकर जुड़ते हैं. कुरैशी के पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में गहरे लिंक हैं. सीबीआई के संयुक्त निदेशक (पॉलिसी) रहे जावीद अहमद भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि उनके समय में ही मोईन कुरैशी के धंधे की जांच का मसला सीबीआई के सामने आया था और पहले झटके में टाल दिया गया था. यही वजह है कि सीबीआई में जावीद का प्रमोशन और एक्सटेंशन गृह मंत्रालय के ‘ऑब्जेक्शन’ के कारण रुक गया और उन्हें यूपी कैडर में वापस भेज दिया गया. सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा और मोईन कुरैशी के सम्बन्ध इतने गहरे रहे हैं कि 15 महीने में दोनों की 90 मुलाकातें आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हैं. पूर्व निदेशक एपी सिंह से भी कुरैशी की ऐसी ही अंतरंग मुलाकातें सीबीआई और ईडी की छानबीन में दर्ज हैं. सीबीआई निदेशक रहते हुए रंजीत सिन्हा ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (सीबीडीटी) पर दबाव डाल कर मोईन कुरैशी के खिलाफ हो रही छानबीन का ब्यौरा जानने और छानबीन की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की थी. सीबीडीटी के पास रंजीत सिन्हा का वह पत्र भी है, जिसके जरिए उन्होंने छानबीन का ब्यौरा उपलब्ध कराने का औपचारिक दबाव डाला था. बाद में वित्त मंत्री बने अरुण जेटली ने सीबीडीटी को ऐसा करने से मना किया था. एपी सिंह और कुरैशी की अंतरंगता इतनी थी कि सिंह के घर के बेसमेंट से कुरैशी का एक दफ्तर चलता था. एपी सिंह और कुरैशी के बीच ब्लैक-बेरी-मैसेज के आदान-प्रदान की कथा सार्वजनिक हो चुकी है. सीबीआई के दूसरे निदेशक रंजीत सिन्हा के प्रसंग में सीबीआई के दस्तावेज बताते हैं कि मोईन कुरैशी अपनी कार (डीएल-12-सीसी-1138) से कई बार सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से मिलने उनके घर गया. कुरैशी की पत्नी नसरीन कुरैशी भी अपनी कार (डीएल-7-सीजी-3436) से कम से कम पांच बार सिन्हा से मिलने गई. कुरैशी दम्पति की दोनों कारें उनकी कंपनी एएमक्यू फ्रोजेन फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम और सी-134, ग्राउंड फ्लोर, डीफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली के पते से रजिस्टर्ड हैं. ये दोनों कारें कई बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर भी जाती रही हैं, जिनमें मोईन अपनी पत्नी के साथ रहा है. मोईन कुरैशी की बेटी परनिया कुरैशी की शादी कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के रिश्तेदार अर्जुन प्रसाद से हुई है.

अमेरिका के पेंसिलवानिया में अरबों रुपए की जालसाजी करने वाला जाफर नईम सादिक के कोलकाता के रवींद्र सरणी इलाके में पकड़े जाने के बाद यह रहस्य खुला था कि वह मोईन कुरैशी का ही आदमी है. इंटरपोल की नोटिस पर जाफर नईम भी पकड़ा गया था. बाद में रहस्य खुला कि इंटरपोल की वांटेड-लिस्ट और रेड-कॉर्नर नोटिस से जाफर नईम, दुबई के विनोद करनन और सिराज अब्दुल रज्जाक का नाम हटाने के लिए कुरैशी ने इंटरपोल के तत्कालीन प्रमुख रोनाल्ड के. नोबल से सिफारिश की थी. नोबल ने यह आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था कि उसके मोईन कुरैशी परिवार और सीबीआई के तत्कालीन निदेशक एपी सिंह से नजदीकी सम्बन्ध रहे हैं. कुरैशी की सिफारिश को नकारने का दावा करने वाले इंटरपोल प्रमुख रोनाल्ड के. नोबल के भाई जेम्स एल. नोबल जूनियर और भारत से फरार स्वनामधन्य ललित मोदी बिजनेस-पार्टनर हैं. अमेरिका में दोनों का साझा धंधा चलता है.

केंद्रीय खुफिया एजेंसी काले धन की आमद-रफ्त का पूरा नेटवर्क जानने की कोशिश में लगी है. मोईन कुरैशी से जुड़े उन तमाम लोगों के लिंक खंगाले जा रहे हैं, जिनके कभी न कभी मोईन कुरैशी से सम्बन्ध रहे हैं या मोईन कुरैशी का धन उनके धंधे में लगा है. इनमें नेता, अफसर, व्यापारी और फिल्मकारों से लेकर माफिया सरगना तक शामिल हैं. कुरैशी के नजदीकी सम्बन्ध समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से रहे हैं. आजम खान की बनाई मोहम्मद अली जौहर युनिवर्सिटी के उद्घाटन के मौके पर मोईन कुरैशी चार्टर हेलीकॉप्टर से रामपुर आया था. सीबीआई गलियारे में चर्चा थी कि आजम खान की युनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय की मान्यता दिलाने में मोईन कुरैशी ने यूपी के अल्पकालिक कार्यकारी राज्यपाल अजीज कुरैशी से सिफारिश की थी. स्वाभाविक है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि छानबीन से ही होगी. लेकिन इतना याद करते चलें कि उत्तर प्रदेश के दो निवर्तमान राज्यपालों क्रमश: टीवी राजेस्वर और बीएल जोशी ने मौलाना जौहर अली युनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा देने के विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था. जोशी के जाने के बाद और राम नाईक के राज्यपाल बन कर आने के बीच में महज एक महीने के लिए यूपी के कार्यकारी राज्यपाल बनाए गए अजीज कुरैशी ने आनन-फानन मौलाना अली जौहर युनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय की मान्यता के विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए. कुरैशी 17 जून 2014 को यूपी आए, 17 जुलाई 2014 को जौहर विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय की मान्यता दी और 21 जुलाई 2014 को वापस देहरादून चले गए.

मनी लॉन्ड्रिंग सरगना मोईन कुरैशी ने फिल्मकार मुजफ्फर अली की फिल्म ‘जानिसार’ में पैसा लगाया था और उस फिल्म में मोईन की बेटी परनिया कुरैशी हिरोइन थी. ‘जानिसार’ फिल्म के प्रोड्यूसर के बतौर मीरा अली का नाम दिखाया गया, लेकिन सब जानते हैं कि फिल्म में मोईन कुरैशी ने पैसा लगाया था. मोईन के अंतरंगों और उपकृतों की लिस्ट में ऐसे और कई नाम हैं. कांग्रेसियों के नाम तो भरे पड़े हैं. सोनिया गांधी का नाम इनमें शीर्ष पर है. पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद तो मोईन कुरैशी के रिश्तेदार ही हैं. वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल, कमलनाथ, आरपीएन सिंह, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे कई नेता इस सूची में शुमार हैं. ये उन नेताओं के नाम हैं, जो मोईन कुरैशी के घर पर नियमित उठने-बैठने वाले रहे हैं. सोनिया के घर पर मोईन परिवार नियमित तौर पर उठता-बैठता रहा है. आयकर विभाग की खुफिया शाखा ने मोईन कुरैशी की विभिन्न हस्तियों से होने वाली टेलीफोनिक बातचीत टेप की थी. यह तकरीबन साढ़े पांच सौ घंटे की रिकॉर्डिंग है. आईटी इंटेलिजेंस के सूत्र जो बताते हैं, उससे लगता है कि कुरैशी का मनी लॉन्ड्रिंग का तंत्र सरकारी सिस्टम को अब भी समानान्तर चुनौती देता रहा है. फोन टैपिंग में केंद्र सरकार के कई मंत्री, यूपी समेत कई राज्य सरकारों के मंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के कद्दावर नेता, सीबीआई के अधिकारी, बड़े कॉरपोरेट घरानों के अलमबरदार और कई फिल्मी हस्तियां शामिल हैं. इनमें भाजपा के भी कई नेताओं के नाम हैं. एक वरिष्ठ भाजपा नेता की बेटी का नाम भी है और उस भाजपा नेता का भी नाम है, जो मोईन कुरैशी के भाई को रामपुर से टिकट दिलाने की कोशिश कर रहा था. ■

feedback@chauthiduniya.com

अपनी बचाने के लिए कुरैशी को बचाना जरूरी

हवाला सरगना मोईन कुरैशी की ऊंची पहुंच का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसकी गिरफ्तारी पर पूरा तंत्र प्रवर्तन निदेशालय के पीछे पड़ गया. कहा जाने लगा कि कुरैशी को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है. आर्थिक अपराध करने वाले व्यक्ति के बचाव में सारे संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार धड़ाधड़ सामने रखे जाने लगे. कहा जाने लगा कि किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बगैर और प्रभावी कानूनी सहायता दिए बगैर हिरासत में नहीं लिया जा सकता. दिल्ली हाईकोर्ट ने तो कुरैशी की गिरफ्तारी पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब-तलब तक कर लिया. यही संरक्षण देश के आम नागरिक को भी मिल पाता, तो देश की यह दशा नहीं होती. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि मोईन के लिंक कई बड़े लोगों और हवाला कारोबारियों से हैं.

प्रवर्तन निदेशालय के सूत्र कहते हैं कि मोईन कुरैशी के मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला धंधे की चपेट में यूपीए शासनकाल के दो मंत्री सीधे तौर पर फंस रहे हैं. आयकर विभाग ने इन नेताओं और कुरैशी के साथ बड़ी धनराशि के लेनदेन के लिंक पकड़े हैं. इन दोनों मंत्रियों के हवाला रैकेट में शामिल होने के सबूत मिले हैं. यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए 2-जी स्कैम में फंसी एक बड़ी कंपनी से ली गई 1,500 करोड़ रुपए की रिश्वत की रकम मोईन कुरैशी ने ही हवाला के जरिए बाहर भेजी थी. पैसे का लेनदेन हांगकांग में हुआ था. छानबीन में यह बात भी सामने आई है कि मोईन कुरैशी ने हवाला के काम में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी के रिश्तेदारों के हांगकांग के बैंक अकाउंट्स का भी इस्तेमाल किया था. आयकर विभाग को उन ट्रांजैक्शंस के ‘ट्रेल’ उपलब्ध हो चुके हैं. जांच में कई और पूर्व मंत्रियों के भी नाम सामने आने की उम्मीद है. मोईन कुरैशी शीर्ष सत्ता गलियारे में दलाली का नेटवर्क फैला कर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का कारोबार चमका रहा था. सीबीआई के सूत्र कहते हैं कि मोईन कुरैशी के राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भी संलग्न रहने की आशंका है, जिसकी गहराई से छानबीन चल रही है. कुरैशी के पाकिस्तान से गहरे लिंक पाए गए हैं, जो खुफिया एजेंसियों की रडार पर हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से कहा है कि मोईन कुरैशी छानबीन में सहयोग नहीं कर रहा है. उसकी जो कुछ अवैध सम्पत्तियां बरामद की गई हैं, वह उसकी अकूत सम्पत्ति के सामने कुछ भी नहीं है. कुरैशी की कई देशों में आलीशान कोठियां हैं. मोईन कुरैशी का लंदन में साउथ ऑडले स्ट्रीट के चैस्टरफील्ड हाउस में फ्लैट नंबर-4, लंदन में ही पोर्टमैन स्क्वायर पर फिट्जर डिंगे हाउस में फ्लैट नंबर-6, दुबई में शेख जायद रोड पर पारामाउंट में 29वीं मंजिल पर पेंट हाउस (नंबर-2902), दुबई के मरीना में आलीशान फ्लैट और दुबई के विश्वविख्यात बुर्ज खलीफा में आलीशान बेशकीमती फ्लैट, न्यूयॉर्क में सेकंड एवेन्यु अपार्टमेंट में 265 नंबर फ्लैट और सोलो बिल्डिंग अपार्टमेंट में फ्लैट, सिंगापुर में बोलेवार्ड और सनटेक टावर में दो आलीशान फ्लैट्स पाए गए हैं. ■

प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
ENFORCEMENT DIRECTORATE
Government of India
6th Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Tel: 24693577 Fax: 24631847

5472-CGO

Dy. No. JD (FY) 1650 /CGO
Dated 01-9-2016

F.No.DE(KS)/Misc/2016
Dated: 31.08.2016

To

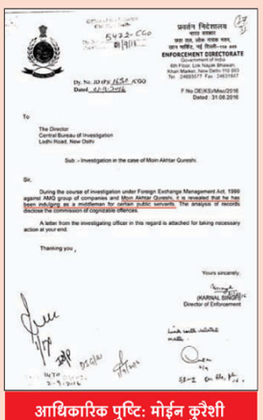

The Director
Central Bureau of Investigation
Lodhi Road, New Delhi

Sub :- Investigation in the case of Moin Akhtar Qureshi.

Sir,

During the course of investigation under Foreign Exchange Management Act, 1999 against AMQ group of companies and Moin Akhtar Qureshi, it is revealed that he has been indulging as a middleman for certain public servants. The analysis of records disclose the commission of cognizable offences.

A letter from the investigating officer in this regard is attached for taking necessary action at your end.

Thanking you,

Yours sincerely,

(KARNAL SINGH)
Director of Enforcement

आधिकारिक पुष्टि: मोईन कुरैशी नौकरशाहों का दलाल था.

Dated 31-8-16

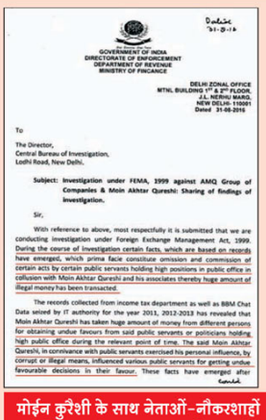

GOVERNMENT OF INDIA
DIRECTORATE OF ENFORCEMENT
DEPARTMENT OF REVENUE
MINISTRY OF FINCANCE

DELHI ZONAL OFFICE
MTNL BUILDING 1ST & 2ND FLOOR,
J.L. NERHU MARG,
NEW DELHI- 110001
Dated 31-08-2016

To

The Director,
Central Bureau of Investigation,
Lodhi Road, New Delhi.

Subject: Investigation under FEMA, 1999 against AMQ Group of Companies & Moin Akhtar Qureshi: Sharing of findings of investigation.

Sir,

With reference to above, most respectfully it is submitted that we are conducting investigation under Foreign Exchange Management Act, 1999. During the course of investigation certain facts, which are based on records have emerged, which prima facie constitute omission and commission of certain acts by certain public servants holding high positions in public office in collusion with Moin Akhtar Qureshi and his associates thereby huge amount of illegal money has been transacted.

The records collected from income tax department as well as BBM Chat Data seized by IT authority for the year 2011, 2012-2013 has revealed that Moin Akhtar Qureshi has taken huge amount of money from different persons for obtaining undue favours from said public servants or politicians holding high public office during the relevant point of time. The said Moin Akhtar Qureshi, in connivance with public servants exercised his personal influence, by corrupt or illegal means, influenced various public servants for getting undue favourable decisions in their favour. These facts have emerged after

Contd

मोईन कुरैशी के साथ नेताओं-नौकरशाहों ने मिलकर किया भ्रष्टाचार और बनाई अकूत सम्पत्ति.

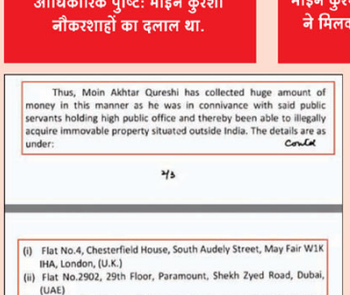

Thus, Moin Akhtar Qureshi has collected huge amount of money in this manner as he was in connivance with said public servants holding high public office and thereby been able to illegally acquire immovable property situated outside India. The details are as under:

Contd

(i) Flat No.4, Chesterfield House, South Audely Street, May Fair W1K IHA, London, (U.K.)
(ii) Flat No.2902, 29th Floor, Paramount, Shekh Zyed Road, Dubai, (UAE)
(iii) 265 East, 66th Street, 2nd Avenue Apartment - 2G, Sollo Building Apartment, New York, (USA)
(iv) 6, Temasek, Boulevard, 24-01, Suntec Tower IV, (Singapore)
(v) Flat No.6, Fitzhar Dinge House, 12-14, Portman Square, W1-H6-LQ, London, (U.K.)
(vi) Flat in Marina, Dubai, (UAE)
(vii) Flat in Burz Al Khalifa, Dubai, (UAE)

विदेशों में मोईन कुरैशी की आलीशान कोठियों का आधिकारिक खुलासा.

निजता का अधिकार: मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है

रवीश कुमार

सरकार कहती रही कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, सामान्य कानून का मामला है, लेकिन संविधान पीठ ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया. 1973 में एक फिल्म आई थी, 'यादों की बारात'. इसका एक गाना आज भी सुना जाता है, 'आप के कमरे में कोई रहता है, तरारा हम नहीं कहते ज़माना कहता है.' प्राइवेसी, निजता की बहस में आप चाहें, तो इस गाने को गुनगुना सकते हैं, 'हम नहीं कहते, ज़माना कहता है.' लिखने और गाने वाले को पता है कि किसी के कमरे में कौन रहता है, झांकना या किसी को बताना ठीक नहीं है. हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की खंडपीठ ने जो फैसला दिया है, उसके सहारे में हम गंवा चुके निजता को हासिल कर सकते हैं या नहीं. सरकार कहती रही कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, सामान्य कानून का मामला है, लेकिन संविधान पीठ ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया.

निजता का अधिकार वो अधिकार है, जिसकी ख़ुशबू संविधान में है. जज साहिबान ने बताया है कि संविधान के बगीचे में अलग-अलग अधिकारों से जो ख़ुशबू आ रही है, वो निजता के अधिकार की ख़ुशबू है. इस ख़ुशबू के बग़ैर संविधान की बगिया की रौनक फीकी पड़ जाती है. आज के फैसले में बस यही हुआ है कि उस ख़ुशबू का नाम दे दिया गया है कि यह जासमीन नहीं, गुलाब नहीं, ख़स नहीं बल्कि निजता का अधिकार है. यह लड़ाई आपके लिए जिन लोगों ने लड़ी पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं.

90 साल की उम्र में निजता के अधिकार मामले के पहले याचिकाकर्ता रिटायर्ड जस्टिस केएस पुत्तास्वामी का शुक्रिया. उनके साथ कई वकीलों ने भी इस केस में अपनी दलील रखी है. मशहूर वकील श्याम दीवान, अरविंद दातार, जी. सुब्रमणियम, युवा वकील गौतम भाटिया, कृतिका भारद्वाज, प्रसन्ना एस, अपार गुप्ता का भी शुक्रिया. इन लोगों ने लड़ाई अदालत के अलावा मीडिया और समाज के स्पेस में भी लड़ी, ताकि लोगों को समझ आए कि प्राइवेसी, निजता का मामला खाते-पीते घरों का मामला नहीं है, बल्कि यह अधिकार चला गया तो कमज़ोर आदमी ज़्यादा आसानी से मारा जाएगा. सरकारें उसे चबा जाएंगी. आपको लगता है कि चबा जाना थोड़ा ज़्यादा कह दिया, तो अगली पंक्ति का इंतज़ार कीजिए.

पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, मुकुल रोहतगी. संविधान पीठ के सामने उन्होंने सरकार का पक्ष नहीं रखा, क्योंकि तब तक पद छोड़ चुके थे. उन्होंने जस्टिस एके सिकरी और अशोक भूषण की बेंच के सामने आधार मामले में जो कहा उसे याद रखना ज़रूरी है. मुकुल रोहतगी की राय भी सरकार की ही राय मानी जाएगी और अलग संदर्भ में कहे जाने के बाद भी इस संदर्भ में उसका ज़िक्र ज़रूरी है. मुकुल रोहतगी अब अटॉर्नी जनरल नहीं हैं, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि नागरिकों का उनके शरीर पर संपूर्ण अधिकार नहीं है. प्राइवेसी का तर्क बोगस है.

आपके शरीर पर आपका अधिकार नहीं है तो किसका है. क्या सरकारों को यह हक़ है कि आपके शरीर का कोई अंग निकाल ले, आंख या किडनी निकाल ले, यह कहते हुए कि आपका शरीर आपका नहीं, सरकार का है. इस आलोक में देखें तो इस फैसले ने ऐसी सोच से सबको बचा लिया है. दुनिया और देश में भ्रष्टाचार है, इसे दूर करने के नाम पर जीने और निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं हो सकता. सब्सिडी से ज़्यादा भारतीय राजनीति और चुनाव को कालेधन से मुक्त करने की ज़रूरत है, जहां आज भी बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दल बग़ैर पैन नंबर और देने वाले का पता पूछे पैसा ले लेते हैं.

एडीआर कि रिपोर्ट से साफ होता है-

-राष्ट्रीय दलों को 384 करोड़ रुपए चंदा मिला है, जिसका पैन नंबर नहीं है.

-355 करोड़ का चंदा देने वालों का पता तक नहीं है.

संविधानपीठ के फैसले को बार-बार पढ़ा जाना चाहिए. इससे एक नागरिक के रूप में आपके प्राइवेट स्पेस की समझ बेहतर होती है, निजी चुनाव की समझ बेहतर होती है. इससे ये समझने में ताकत मिलेगी कि आपका चुनाव आपका है, किसी और का नहीं. जज साहिबान ने कहा-

-ठीक है कि आर्टिकल 21 और 19 में निजता के अधिकार का उल्लेख नहीं है.

-यह कहना कि भारत का संविधान निजता का अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है, सही नहीं है.

-जीने के अधिकार में भी निजता का अधिकार शामिल है.

-जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है.

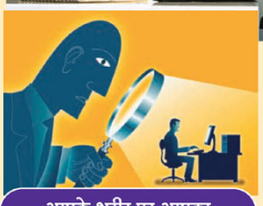

आपके शरीर पर आपका अधिकार नहीं है तो किसका है. क्या सरकारों को यह हक है कि आपके शरीर का कोई अंग निकाल ले, आंख या किडनी निकाल ले, यह कहते हुए कि आपका शरीर आपका नहीं, सरकार का है. इस आलोक में देखें तो इस फैसले ने ऐसी सोच से सबको बचा लिया है. दुनिया और देश में भ्रष्टाचार है, इसे दूर करने के नाम पर जीने और निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं हो सकता.

-व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता की चाह, समानता, ये सब भारतीय संविधान के आधारभूत स्तंभ हैं.

-जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान की रचना नहीं है, बल्कि संविधान इन्हें मान्यता देता है.

-प्राइवेसी का अधिकार, जीने और निजी स्वतंत्रता के अधिकार से निकलता है.

-मौलिक अधिकारों के विभिन्न तत्वों से भी निजता का अधिकार निकलता है.

प्राइवेसी का सवाल सिर्फ आधार नंबर के संदर्भ में नहीं है. इस संदर्भ में भी है कि एक धर्म की लड़की जब दूसरे धर्म के लड़के से शादी करेगी, तो सरकार की एजेंसियां जांच नहीं करेंगी. समलैंगिकों के सवाल को यह अधिकार मज़बूती देगा. यह सवाल वहां भी आता है कि क्या कोई सरकारी एजेंसी आपका फोन रिकॉर्ड कर सकती है. अदालत की संविधान पीठ ने कहा कि वे यहां उन सभी की सूची नहीं तैयार कर रहे हैं कि निजता क्या-क्या है. इसके बाद भी प्राइवेसी का जो दायरा बताया गया है, वो काफी महत्वपूर्ण है.

संविधान पीठ ने कहा है कि सेक्सुअल संबंध, व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक जीवन की मान्यता, शादी करना, बच्चे पैदा करना यह सब निजता के अधिकार हैं. प्राइवेसी का अधिकार वो है, जो व्यक्तिगत स्वायत्ता का बचाव करता है. यह अधिकार मान्यता देता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के वाइटल पहलुओं को कैसे नियंत्रित करता है. व्यक्तित चयन भी प्राइवेसी का हिस्सा है. प्राइवेसी हमारी संस्कृति की विविधता, बहुलता को भी संरक्षण देती है. कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में है, इस वजह से उसकी प्राइवेसी खत्म नहीं हो जाती है. इंसान की गरिमा का अभिन्न अंग है प्राइवेसी.

कोर्ट ने कहा कि संविधान के मायने, इसके बनने के दौर के संदर्भ में बंद नहीं किए जा सकते हैं. बदलते वक्त की लोकतांत्रिक चुनौतियों के अनुसार इसकी ठोस व्याख्या होती रहनी चाहिए. निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है. केके वेणुगोपाल, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने संविधान पीठ के सामने कहा था कि राज्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो हक देता है, उसके हित में निजता का अधिकार छोड़ा जा सकता है.

हमारा मत है कि निजता का अधिकार अमीरों की कल्पना है, जो बहुसंख्यक जनता की आकांक्षाओं और ज़रूरतों से काफी अलग है. अदालत मानती है कि इस दलील में दम नहीं है. यह दलील संविधान की समझ के साथ धोखा है. हमारा संविधान एक व्यक्ति को सबसे आगे रखता है. यह कहना सही नहीं है कि ग़रीब को सिर्फ आर्थिक उन्नति चाहिए, नागरिक और राजनीतिक अधिकार नहीं.

संविधान पीठ ने सरकार के कार्यों की समीक्षा, सवाल करने, उससे असहमत होने के अधिकार को भी संरक्षण दिया है. अदालत का कहना है कि यह सब लोकतंत्र में नागरिकों को सक्षम बनाता है, इससे वे राजनीतिक चुनाव बेहतर करते हैं. एक जगह तो सरकार के कटु आलोचक प्रोफेसर अमर्त्य सेन का भी ज़िक्र आया है, जिसे देखकर सरकार के मशहूर वकीलों को अच्छा नहीं लगेगा. अदालत ने बड़े विस्तार से समझाया कि सामाजिक आर्थिक तरक्की का नागरिक राजनीतिक अधिकारों से कोई झगड़ा नहीं है. इसी संदर्भ में संविधान पीठ के फैसले में एक जगह ज़िक्र आता है कि इनमें से कुछ चिंताओं की झलक नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के लेखों में भी मिलती है. सेन ने अकाल के समय में ग़ैर लोकतांत्रिक सरकारों और लोकतांत्रिक सरकारों की हरकतों की तुलना की है. उनका विश्लेषण बताता है कि निरंकुश राज्य में सरकार के नेताओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके कारण अकाल जैसी स्थिति में जनता को राहत नहीं मिल पाती है.■

(लेखक मशहूर टीवी पत्रकार हैं.)

एक साल में अवैध खनन के 96 हजार मामले दर्ज किए गए

अवैध खनन का काला साम्राज्य

चौथी दुनिया ब्यूरो

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में 2016-17 के दौरान अवैध खनन के 96 हजार से भी ज्यादा केस दर्ज किए गए. खनन मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में हाल में इस बात की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि इस दौरान महाराष्ट्र में अवैध खनन के सबसे अधिक 31,173 मामले दर्ज किए गए, जबकि मध्यप्रदेश में 13,880 और आंध्र प्रदेश में 9703 केस दर्ज किए गए. 2015-16 में यह संख्या 1,10,476 थी.

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रेत के अवैध खनन की निगरानी करने के लिए साइट पर पहुंचे न जाने कितने राजस्व अधिकारियों व तहसीलदारों पर जानलेवा हमले किए गए. रेत माफिया के लिए महाराष्ट्र को सोने की खान कहा जाता है. एक अनुमान के मुताबिक, राज्य में अवैध रेत खनन का कारोबार सालाना दस-पंद्रह हजार करोड़ रुपए का है. वहीं सरकार को राजस्व के रूप में इसका केवल कुछ हिस्सा ही मिलता है. बालू माफिया के लिए थाणे, रायगढ़, नासिक, जलगांव और कुछ अन्य जिले, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के इलाके से जुड़े हैं, प्रमुख केंद्र के तौर पर उभरे हैं. कर्नाटक के लोकायुक्त एन संतोष हेगड़े ने 2011 में राज्य में अवैध खनन की गतिविधियों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री व चार अन्य मंत्रियों को दोषी ठहराया था. कह सकते हैं कि खनन माफिया-अफसर और नेताओं का गठजोड़ देश के खजाने को अरबों रुपए का चूना लगा रहे हैं.

पश्चिम बंगाल का रानीगंज-आसनसोल कोयलांचल भी अवैध खनन का प्रमुख केंद्र रहा है. आज हाल यह है कि खनन माफिया की करतूतों के कारण इन इलाकों के निवासियों को अब धंसान जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है. रानीगंज कोयलांचल के डेढ़ हजार किलोमीटर इलाके के नीचे आग सुलग रही है. इस इलाके में 19 खुली हुई खदानें हैं, जहां अब खनन कार्य नहीं हो रहा है. इन्हें बालू से भरने के लिए सरकार अब तक निविदाएं भी नहीं मंगा सकी है.

ओड़ीशा, कर्नाटक के अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश, गोवा और पश्चिम बंगाल की कुछ खदानों से लौह अयस्क का अंधाधुंध अवैध खनन जारी है. उत्तर प्रदेश में बालू, सिल्क आदि का अवैध खनन जोरों पर है. हालात इतने बदतर हो गए कि आखिर में इलाहाबाद हाई कोर्ट को अवैध खनन मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था. नए कानून के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अब अवैध खनन का दोषी पाए जाने पर पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा.

कोयला कंपनियां खनन के बाद खदानों में स्टॉपिंग प्वाइंट पर पहुंचकर काम रोक देती हैं. इस प्वाइंट के बाद कंपनियों के लिए कोयला निकलना मुनाफे का सौदा नहीं रह जाता है. इसी के बाद कोल माफिया का अवैध कारोबार शुरू होता है. मजदूरों की जान जोखिम में डालकर रेड लाइन से आगे खदानों की खुदाई शुरू होती है. जितने भीतर तक खदानों से कोयला निकाला जाएगा, उतनी ही अधिक कोयला माफिया की कमाई भी होगी. कभी-कभी खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से मिथेन गैस निकल आती है और कई गांवों को अपनी चपेट में ले लेती है. एक अनुमान के मुताबिक, खनन माफिया हर साल 30 लाख टन कोयला खदानों से पार करा देते हैं. कोयला, लोहा, अल्युमिनियम, अभ्रक, तांबा, मैंगनीज समेत कई अन्य कीमती खनिजों के प्राकृतिक भंडारों में भी माफिया का खुला खेल चल रहा है.

ओड़ीशा, कर्नाटक के अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश, गोवा और पश्चिम बंगाल की कुछ खदानों से लौह अयस्क का अंधाधुंध अवैध खनन जारी है. उत्तर प्रदेश में बालू, सिल्क आदि का अवैध खनन जोरों पर है. हालात इतने बदतर हो गए कि आखिर में इलाहाबाद हाई कोर्ट को अवैध खनन मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था. नए कानून के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अब अवैध खनन का दोषी पाए जाने पर पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा. ऐसे मामले में दोषियों की सजा छह माह से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई.

मध्यप्रदेश सरकार भी खनिज माफिया पर मेहरबान रही है. वहां चल रहे अवैध खनन का असर सीमावर्ती बांदा क्षेत्र में भी देखा जा सकता है. मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने खदानों के पट्टे दे रखे हैं. मध्यप्रदेश में पन्ना जनपद से रोज 1000 ट्रक यहां से बालू लेकर अन्य राज्यों में जाते हैं. केन नदी के दूसरी ओर बांदा जनपद है. मध्यप्रदेश में चंदौरा घाट के नाम पर बांदा की खदानों से भी बालू का अवैध खनन जारी है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे बुंदेलखंड में पिछले वर्ष से बालू खनन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है. बुंदेलखंड में 1300 से ज्यादा खदानें हैं. इससे प्रदेश सरकार को 510 करोड़ का सालाना राजस्व मिलता था. आलम यह है कि बुंदेलखंड के कई बालू माफिया आज विधानसभा की चौखट तक पहुंच गए हैं.

उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में अवैध खनन पर रोक के लिए अब उपग्रह से निगरानी की जाएगी. एक साल पहले केंद्रीय विद्युत और खनन राज्यमंत्री पीयूष गोयल ने ये बात कही थी. उन्होंने कहा था कि चार महीने में यह योजना शुरू हो जाएगी. लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी अभी काम शुरू नहीं हुआ है. हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए जाने की योजना थी. केंद्रीय खान मंत्रालय ने इस प्रणाली को विकसित किया है. यह सिस्टम खनन सीमा के 500 मीटर के दायरे में चल रहे किसी भी असमान्य गतिविधि की जांच करने में सक्षम है. पीयूष गोयल ने दिल्ली में इस खनन निगरानी प्रणाली की शुरुआत भी की थी. उन्होंने बताया कि एमएसएस एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली है. इसमें रिमोट सेंसिंग के माध्यम से अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाया जाता है. उन्होंने यह भी कहा था कि आमलोग भी मोबाइल से अवैध खनन की जानकारी दे सकते हैं. अवैध खनन पर रोक के लिए खनन माफिया-नेता और अधिकारियों की मिलीभगत पर रोक लगानी होगी.■

डेरा सच्चा सौदा

पर्दे के पीछे का सच

‘राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के बारे में सबसे पहले चौथी दुनिया ने 03 दिसंबर-09 दिसंबर 2012 के अंक में खबर प्रकाशित की थी. इस खबर के जरिए हमने डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी.’

पुष्पराज

हरियाणा का सिरसा वैसे तो पर्यटन का केंद्र नहीं है, लेकिन अगर आप पत्रकार हैं और मूल्यपरक पत्रकारिता से आपका जुड़ाव है, तो सिरसा आपके लिए एक तीर्थ स्थान हो सकता है. पत्रकारिता की एक लीक सिरसा से शुरू होती है. अगर हम सबने मिलकर इस लीक को बचाने की कोशिश नहीं की, तो यह जल्द ही खत्म भी हो सकती है. सिरसा को पत्रकारिता का तीर्थ आप इस तौर पर भी मान सकते हैं कि इसी सिरसा में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने सच लिखने के कारण अपनी शहादत दी. 21 नवंबर, 2003 को स्वर्गीय प्रभाष जोशी ने छत्रपति की पहली बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चेताया था कि आज पत्रकारिता के क्षेत्र में कई छोटे-बड़े हिटलर खड़े हैं. अगर आप उन हिटलरों से नहीं लड़ेंगे, तो आपकी पत्रकारिता को घुन लग जाएगा. प्रभाष जोशी की चुनौती को अगर आप स्वीकार करते हैं, तो एक बार सिरसा की तरफ रुख जरूर कीजिए. छत्रपति की शहादत के बारे में जानने के लिए हमें उन वजहों की तलाश करनी होगी, जिसके नतीजे में उन्हें अपनी शहादत देनी पड़ी थी. छत्रपति के करीबी मित्र एवं हरियाणा के वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज ढोट कहते हैं कि छत्रपति को याद करने का मतलब है, डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ आवाज बुलंद करना. उसकी धमकियों के बावजूद दिल्ली के पत्रकारिता जगत ने उसके विरुद्ध उतरने का निर्णय लिया है. डेरा सच्चा सौदा का भूत अगर इतना डरा रहा है और उसका खौफ पत्रकारिता के लिए इतना भयानक है, तो हमें उस खौफ का करीब से दर्शन कर लेना चाहिए.

यहां एक डेरा है और डेरे में सच की सौदेबाजी हो रही है, यहां सब कुछ खुला-खुला है. रामचंद्र छत्रपति की हत्या के बाद हरियाणा के पत्रकारों की महापंचायत ने डेरा का हक्का-पानी बंद कर दिया. साथ ही कुछ डेरा समर्थक पत्रकारों को भी पत्रकार बिरादरी से बाहर कर दिया गया. महापंचायत द्वारा बहिष्कृत पत्रकार अब डेरा की कमेटी, प्रबंधकारिणी कमेटी और डेरा सच्चा सौदा के मुखपत्र सच कहूं की पत्रकारिता करने में जुट गए हैं. प्रेस कमेटी से जुड़े लोग आपको डेरा का दर्शन करा सकते हैं, बशर्ते उन्हें यह तसल्ली हो जाए कि आप डेरा के पक्ष में ही लिखने वाले हैं. सिरसा में छत्रपति की शहादत को सलाम कर लौटने के साथ ही डेरा सच्चा सौदा के सच को निहार लेना जरूरी है, जिसके सौंदर्य का सारा छद्म छत्रपति को मालूम हो चुका था. तीसरे दिन जगदीश सिंह, पवन बंसल एवं रामाश्रय गर्ग नामक तीन चेहरे गेस्ट हाउस पधारे. वे लोग डेरा सच्चा सौदा प्रेस कमेटी के सदस्य हैं और उन्हें नए आगंतुकों की विश्वसनीयता परखने का पूरा हक है. आखिरकार हमने तय किया है कि अगर सच की सौदेबाजी का दर्शन करना है, तो हमें हर तरह का झूठ बोलने के लिए तैयार रहना होगा. वे लोग मेरी बातों से मुग्ध हो चुके थे. क्या किसी ने फोन से कहीं कोई इंडिकेशन दिया है, क्या भगवान गुरमीत राम रहीम सिंह को हमारे बारे में बता दिया गया है? जगदीश सिंह ने मार्केट कमेटी का गेस्ट हाउस छोड़कर डेरा के एसी गेस्ट हाउस में टिकने का अनुरोध किया. यहां डेरा का अपना व्याकरण है और अपना शब्दकोश भी. डेरा परिसर क्षेत्र में सिरसा को सरसा लिखा जाता है. सच कहूं डेरा का दैनिक समाचारपत्र है. हमें बताया गया कि सच कहूं कि डेढ़ लाख प्रतियां रोजाना पंजाबी और हिंदी भाषा में छपती हैं. मेरे हाथ में सच कहूं का एक विशेषांक है. तस्वीरें आलीशान किलानुमा इमारतों की हैं और इन तस्वीरों के बीच में खबर का शीर्षक है, गर्ल्स स्कूल या परी लोक. शुरू में हैरत हुई, लेकिन जल्दी ही सतर्क हो गया. यह सच का डेरा है, यहां झूठ कुछ भी नहीं है. यहां डेरा बेटियों को परी कहकर संबोधित करता है. डेरा के व्याकरण में बेटी को परी कहते हैं, तो हमें क्या ऐतराज?

डेरा आने वाले अमीर साधु संगतों के लिए यहां की रंगीन, हसीन दुनिया का आनंद लेना जरूरी है. यहां स्वीमिंग पुल, अत्याधुनिक झूले एवं रेस्तरांओं के हसीन संसार भी मौजूद हैं. 140 कमरों का वातानुकूलित गेस्ट हाउस है. अंदर की दुनिया आपको एक पल के लिए फूलों के गुलदस्तों की तरह दिख सकती है. दो वर्ष पहले डेरा के पांच साधु संगतों ने मिलकर महाराज जी के आशीर्वाद से यह सब कुछ बनाया है. कशिश रेस्टोरेंट में हम खाने के लिए पहुंचे, तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था. दाएं बाजू सीस का घेरा है और घेरे से बाहर पानी भरा है. सीस पर पानी का रंग हरा-हरा दिखता है. बाहर से हम मछलियों की तरह दिखते हैं. बाहर वाटर स्लेटिंग-स्केचिंग करती लड़कियां दिख रही हैं. डेरा के भीतर मौजूद सजावट किसी परी लोक से कम नहीं थी. डेरा के एक छोर में 200 से ज्यादा गाय-भैंसें बंधी थीं. उनके लिए बाकायदा सेवादार दिन-रात काम कर रहे थे. दूसरी तरफ अंगूर, सेव, चीकू, लीची, लौंग, अमरूद, बादाम, शहतूत एवं नारियल के दर्जनों पेड़ लगे थे. कई युवतियों को साध्वी कहने को कहा गया. यहां डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की तस्वीरें सजी थीं. 23 वर्ष की उम्र में डेरा प्रमुख बनने वाले बाबा गुरमीत अभी भी युवा दिखते हैं. मुस्कराते बाबा, ट्रैक्टर चलाते बाबा, फावड़ा चलाते बाबा. अलग-अलग पोज के लिए अलग-अलग रंग-बिरंगी पोशाकों में हंसते-खिलखिलाते महाराज तस्वीरों की दुनिया में आज भी खूब जमते हैं. पानी, पहाड़, जंगल, उगते सूरज और डूबते सूरज को निहारते महाराज.

यहां प्रेस कमेटी का दफ्तर काफी सुव्यवस्थित है. पत्रकारों की महापंचायत से बाहर हुए पत्रकार आज डेरा में पत्रकारिता कर रहे हैं. डेरा सच्चा सौदा के लाखों भक्त गुरमीत राम रहीम सिंह को भगवान मानते हैं, उनके ऊपर एक साध्वी का यौन शोषण करने का आरोप है. सवाल यह है कि एक गुमनाम साध्वी के पत्र का रामचंद्र छत्रपति की शहादत से क्या रिश्ता है, आखिर वह गुमनाम साध्वी कब तक गुमनाम रहेगी? जब उस अज्ञात साध्वी के पत्र से गुरमीत राम रहीम के किस्से बाहर आए, तो हरियाणा में बवाल मच गया. डेरा और समाज आमने-सामने खड़े हो गए. चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुमनाम साध्वी के पत्र को बेहद गंभीर मानते हुए 24 सितंबर, 2002 को डेरा प्रमुख के ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को छह माह का समय दिया. डेरा सच्चा सौदा की ओर से उच्च न्यायालय में जिन आठ साध्वियों ने याचिका दायर कर सीबीआई जांच का पुरजोर विरोध किया था, उनमें से एक शीला पूनिया से मिलना हमारे लिए काफी अहम था. शीला पूनिया ने सीबीआई की विश्वसनीयता पर संदेह जाहिर करते हुए हरियाणा पुलिस की सीआईडी से जांच कराने का आग्रह किया था. यह अलग बात है कि अदालत ने उस बेवकूफी भरी याचिका को खारिज कर दिया था. शीला पूनिया उस गर्ल्स स्कूल की प्राचार्य हैं, जिसे डेरा के मुख्य पत्र सच कहूं ने परी लोक की संज्ञा दी है. पूनिया बताती हैं कि वह अंबाला में एमए, बीएड एवं कंप्यूटर कोर्स करके अपने डेरा भक्त पूर्व न्यायाधीश पिता के संपर्क से इस विद्यालय की टीचर बनीं और अब यहां प्राचार्य हैं. शीला पूनिया से बातचीत करने के बाद डेरा के विषय में और अधिक जानने की उत्सुकता मेरे मन में होने लगी. सबसे ज्यादा इच्छा हमें उस गुफा को देखने की थी, जहां डेरा प्रमुख निवास करते हैं.

प्रेस कमेटी के लोगों ने मुझसे कहा कि आपको गुफा के अंदर जाने की जिद नहीं करनी चाहिए. चलिए, आपको बाहर से ही दिखा दते हैं. गुफा के अंदर है ही क्या, जिसे आप देखना चाहते हैं. वहां सिर्फ दो कमरे की कुटिया है. महाराज जी का सीधा-सादा जीवन है. धीरे-धीरे हम गुफा की तरफ बढ़ रहे थे. दो उजले-चमकते हाथियों के आपस में जुड़ते हुए सूंड प्रवेश से पहले का तोरण द्वार है. जमीन की सतह से 40 फीट ऊंचाई पर चमकता हुए एक किला था. यहां हर दस गज की दूरी पर एक सुरक्षा प्रहरी तैनात था. असल में जिसे लोग गुफा कह रहे थे, वह देखने से पूरी तरह किला लग रहा था. लौह द्वार पर धातु से निर्मित केले के पेड़ों में बड़े-बड़े केले लटक रहे थे. उसके किनारे कोने में 25 फीट ऊंचे दो उजले हंस खड़े थे. उसके ठीक सामने 15 फीट ऊंचा प्याला था. सिरसा के कुछ पत्रकारों ने हमें पहले ही बताया था कि डेरा के बाहर हर माह एक-दो अज्ञात लाशें मिल जाती हैं और डेरा के अंदर भी अंत्येष्टि की बेहतर व्यवस्था है. हमने डेरा के भीतर छत्रपति का नाम कभी नहीं लिया. डेरा की यह तथाकथित गुफा बड़े-बड़े महलों को मात दे सकती है. गुफा के द्वार पर हमने देखा कि कोई शख्स सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दे रहा था. बाईं तरफ कुछ खूबसूरत साध्वी बहनें अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं. डेरा प्रवक्ता का कहना था कि गुफा के अंदर कोई नहीं जा सकता, तो फिर साध्वी बहनें वहां क्या कर रही थीं? रात ढलती जा रही थी, गुफा का सौंदर्य बढ़ता जा रहा था. यहां काफी देर घूमने के बाद हम वापस उसी कशिश रेस्टोरेंट में आए. सारा नजारा देखकर हमें डेरा सच्चा सौदा की असलियत का पता चला. भगवान, साध्वी और डेरा यानि हम जो देख रहे थे, वही आपको दिखा रहे हैं. जो धार्मिक जानकार हैं, वे यह कह सकते हैं कि कलयुग में भगवान का यह उदारवादी संस्करण है. छत्रपति की हत्या अगर भगवान के आदेश से हुई है, तो क्या इस लोकतंत्र में इस हत्यारे के लिए कोई सजा नहीं है? छत्रपति की शहादत को अगर आप सलाम कहने की हिम्मत रखते हैं, तो साफ-साफ कहिए कि यह धर्म का डेरा नहीं, धर्म का धोखा है. यहां चारों तरफ फरेब है और उसी की आड़ में चल रहा है व्याभिचार का खेल. ■

feedback@chauthiduniya.com

राम रहीम के ख़िलाफ सबसे पहले छपी रिपोर्ट (03 दिसंबर-09 दिसंबर 2012)

शीला पूनिया से चंद सवाल-जवाब

आप डेरा की वेतनभोगी प्राचार्या हैं?
नहीं, मैं साध्वी हूं.

एकाकी जीवन में कोई युवती कैसे ज्वाय फील कर सकती है?
मेरे गुरु जी पूरण संत हैं, इसलिए मैं संतुष्ट हूं.

क्या आप स्कूली लड़कियों को भी साध्वी बनने के लिए प्रेरित करती हैं?
सबको उनकी मंजिल बता दी जाती है. अपनी राह चुनना सबकी मनमर्जी पर है. यहां 2000 लड़कियां हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं है. कनाडा में रहने वाले माता-पिता भी अपनी बेटियों को यहां भेजकर सुरक्षित महसूस करते हैं.

वैवाहिक जीवन के बिना आपकी संतुष्टि का रहस्य क्या है?
अब मजलिस का समय हो रहा है, बाबा जी वहां सारे सवालों का जवाब दे देंगे.

मेधावी लड़कियों का चयन अच्छा है, सब खूबसूरत हैं..
जो खूबसूरत होती हैं, वही मेधावी होती हैं, आप भी मजलिस में चलिए, आपको पता चला जाएगा कि बाबा जी सचमुच पूरण संत हैं.

मजलिस की महिमा और गुफा

मजलिस लगी है. दस हजार से ज्यादा लोगों की भीड़. महिलाएं एक तरफ, पुरुष दूसरी तरफ. टीन की चादरों की स्थायी छत. महाराज सिंहासन पर विराजे तो सबने हाथ जोड़कर, आंख मूंदकर माथे को धरती पर नवाया. पसीने से तर-ब-तर सेवादार पंखा झलते थकता है, तो दूसरा खड़ा हो जाता है. अभी जो सेवादार भगवान को पंखा झल रहा है, एक अवकाशप्राप्त न्यायाधीश है, ऐसा बताया गया. भगवान गुफा से निकले थे, फिर गुफा में समा गए. यह पूछने पर कि क्या अब हम भगवान से मुलाकात कर सकते हैं? प्रेस प्रवक्ता आदित्य अरोड़ा कहते हैं, हुजूर भगवान की ओर से हम हर सवाल का जवाब देंगे.

लेकिन हमें तो अपने सवालों के जवाब भगवान से चाहिए, क्योंकि आरोपी वह हैं...
हमारे डेरे का अपना प्रोटोकाल है. संतों-फकीरों का अपना जीवन होता है. संतों के पास राम नाम का धन होता है, उन्हें मापने का एक ही पैमाना है. संतों ने जो राह दिखाई है, उस पर चला जाए.

देश में भूमिगत लड़ाई लड़ने वाले नक्सली भी अपना जीवन गोपनीय नहीं रखते, फिर किसी संत-फकीर के निर्मल जीवन को छुपाने की जिद क्यों?
बाबा जी जहां रहते हैं, वहां तक जाने की मुझे भी अनुमति नहीं है, फिर आप कैसे जा सकते हैं? किसी घर के कायदों में हस्तक्षेप ठीक नहीं. आप परेशान मत करिए. आप ई-मेल से सवाल करिए, सही-सही जवाब दिया जाएगा.

गुफा के भीतर जाकर हुजूर से मिलने पर पाबंदी क्यों?
बाबा जी कंस्ट्रक्शन के कामों को खुद देखते हैं, फिर मजलिस की व्यस्तता अलग. वह बहुत थक जाते हैं. संत-फकीर को उसके गुरु वचन से जानिए-परखिए.

गुफा के अंदर जाने की इजाजत न देने से डेरे के प्रति गलतफहमी बढ़ती है..
आप कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए. बाबा जी की गुफा के अंदर देश के किसी प्रेस, किसी पत्रकार को प्रवेश की इजाजत नहीं है, यह देश भर में प्रचार कर दीजिए.

राजनीति स्वीकार्य स्तर से नीचे गिर रही है

कमल मोरारका

www.kamalmorarka.com

कांग्रेस रिज़र्व बैंक के गवर्नर को घेर रही थी कि वे नोटबंदी से सम्बन्धित आंकड़े जारी करें. मनमोहन सिंह, जो प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री रह चुके हैं और स्थायी समिति के सदस्य भी थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर को इन सवालों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है. यह महत्वपूर्ण नहीं कि सरकार किसकी है. यह देश हमारा है. हमें ज़िम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए. मनमोहन सिंह उस वक्तव्य की अहमियत समझते थे. यदि रिज़र्व बैंक के गवर्नर को कुछ कहना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सार्वजानिक तौर पर कहें. इससे देश को नुकसान होगा. हर व्यक्ति वोट के बारे में सोच रहा है.

जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं, उनसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जितनी नई घोषणाएं कीं या उन्हें लागू करने की कोशिश की, वे या तो कम कारगर साबित हुईं या उनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ. हालिया घटना भारतीय रिज़र्व बैंक की है. रिज़र्व बैंक ने कहा है कि नोटबंदी के बाद 99 प्रतिशत विमुद्रीकृत नोट वापस आ गए हैं. इस दौरान रिज़र्व बैंक यह कहता रहा कि नोटों की गिनती का काम चल रहा है और इसमें समय लगेगा. अब रिज़र्व बैंक ने कहा है कि 99 प्रतिशत पुरानी मुद्रा बैंक सिस्टम में वापस आ गई है और बाकी की गिनती जारी है. तो इसका मतलब यह है कि 100 प्रतिशत से अधिक मुद्रा बैंकों में वापस आई है! यह बहुत ही संवेदनशील विषय है. इन विषयों से बहुत ही बेढंगे तरीके से निपटा गया. वित्त मंत्री और रिज़र्व बैंक गवर्नर से देश यह उम्मीद करता है कि वे अपना काम अधिक ज़िम्मेदारी से करें. ये ऐसे विषय नहीं हैं, जिन पर अधिक बयानबाज़ी की आवश्यकता है. अब 98 प्रतिशत नोट वापस आए या 99 प्रतिशत वापस आए, इससे आम आदमी के जीवन पर क्या फर्क पड़ता है? उसने अपने नोट पहले ही बदल लिए हैं और उनकी ज़िन्दगी नए–नए नोटों के साथ पहले की तरह चल रही है.

ये विषय अर्थशास्त्रियों, रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय के विचार करने के विषय हैं, न कि सार्वजनिक बयान जारी करने के. दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री ने लालकिले के अपने भाषण में कहा था कि तीन लाख करोड़ रुपए वापस आ गए हैं. मुझे नहीं लगता कि वे जो बातें कह रहे हैं, उसके परिणाम को समझते हैं. बहरहाल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस तरह के माड्डको इकोनॉमिक्स से सम्बंधित विषयों पर सार्वजनिक चर्चा का कोई मतलब नहीं है. यदि आप लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, शौचालयों के निर्माण, उज्ज्वल योजना के तहत एलपीजी के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक घोषणा करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. इसमें भी कोई बुराई नहीं है, यदि प्रधानमंत्री पुरानी योजनाओं को नए नामों से जारी करें, लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों जैसे वित्तीय या राजस्व घाटे के बिन्दुओं को जनता को समझाने की आवश्यकता नहीं है. ऐसा कर आप या तो देश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनसे ध्यान भटकना चाहते हैं या फिर आपने सोच लिया कि जनता अचानक इतनी होशियार हो गई है कि वो गंभीर आर्थिक मामलों पर बहस कर सके. ये बिना मतलब का परिश्रम है. मेरे हिसाब से एक सकारात्मक खतरा (पॉजिटिव डेंजर) यह है कि यदि फ़िलहाल नहीं, तो आने वाले चार–पांच वर्षों में लोग हमारी मुद्रा में विश्वास करना छोड़ देंगे. वो दिन देश के लिए बहुत ही दुखद होगा. ऐसा कई अफ्रीकी देशों में हो चुका है. हमारे देश में यह नहीं होना चाहिए. यही चीज़ संसद की स्थायी समिति में भी देखने को मिली, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद थीं. कांग्रेस रिज़र्व बैंक के गवर्नर को घेर रही थी कि वे नोटबंदी से सम्बन्धित आंकड़े जारी करें. मनमोहन सिंह, जो प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री रह चुके हैं और स्थायी समिति के सदस्य भी थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर को इन सवालों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है. यह महत्वपूर्ण नहीं कि सरकार किसकी है. यह देश हमारा है. हमें ज़िम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए. मनमोहन सिंह उस वक्तव्य की अहमियत समझते थे. यदि रिज़र्व बैंक के गवर्नर को कुछ कहना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सार्वजानिक तौर पर कहें. इससे देश को नुकसान होगा. हर व्यक्ति वोट के बारे में सोच रहा है. दो विधायकों के वोट के लिए छह मंत्री तड़के 4.30 बजे तक चुनाव आयुक्त को जगाए रखते हैं. ये लोग हमारी राजनैतिक व्यवस्था की प्रमाणिकता को स्वीकार्य स्तर से नीचे गिरा रहे हैं. इसे बंद होना चाहिए.

यह देश बहुत बड़ा है. भाजपा के यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया. वहीं कांग्रेस भी ये कह सकती है कि 5 साल में भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया. लेकिन यह सब चुनाव के छह महीने तक चलना चाहिए, उसके बाद आपको गंभीरता से काम करना चाहिए. देश वहीं रहेगा, समस्याएं भी वहीं रहेंगी और उन समस्याओं के समाधान का तरीका भी वही रहेगा. भारत जैसे बड़े देश में आप कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं कर सकते हैं. शासन के हिसाब से भारत एक जटिल देश है. डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि वे तीन महीने में संपूर्ण अमेरिका को बदल देंगे. उन्हें पहले यह समझ में नहीं आया कि वे बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं. उन्होंने अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए दीवार बनाने का एक साधारण सुझाव दिया. भारत में उसी तरह के काम हो रहे हैं.

उसी तरह से डोकलाम का मामला है. भारत, चीन और भूटान की सीमाएं जहां मिलती हैं, वहां पर जून से ही तनाव है. यह पहला मौका है, जब इस जगह पर ऐसी समस्या पैदा हुई है. किसी न किसी तरह इस मसले को सुलझा लिया गया है. कैसे, हमें मालूम नहीं, क्योंकि भारत अलग बयान दे रहा है और चीन अलग बयान दे रहा है. मेरे ख्याल से जब तक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने–सामने नहीं हों, तब तक दोनों अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए यही कहेंगे कि उनका पलड़ा भारी रहा. अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में यह जायज़ है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कूटनीतिक रास्ते से समस्या का समाधान हो गया.

गृह सचिव पिछले दिनों सेवानिवृत्त हो गए. उन्होंने सेवानिवृत्ति से पहले एक साक्षात्कार दिया. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, उसके लिए राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते. ये कहने में कोई खामी नहीं है, ये आम बातें हैं. ये बातें इसलिए हो रही थीं कि उनको चुनाव आयुक्त बनाए जाने की अफवाहें फैल रही थीं. हालांकि, अब उन्हें भारत का महालेखा परीक्षक (कैग) नियुक्त कर दिया गया है. भाजपा ने सोचा कि अचल कुमार ज्योति, जो पहले गुजरात के मुख्य सचिव थे, उनके इशारों पर काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. चुनाव आयुक्त की हैसियत से उन्होंने दो विधायकों के वोट को (गुजरात राज्यसभा चुनाव के दौरान) अवैध करार दिया, जिसकी वजह से अहमद पटेल चुनाव जीत गए. अब भाजपा असमंजस में है कि वह किस पर भरोसा करे. भाजपा ने सोचा कि जिस तरह उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर और मीडिया को खरीद लिया, वैसे ही वे चुनाव आयोग और नौकरशाही को भी खरीद लेंगे. मुझे खुशी है कि नौकरशाही ने ये संकेत दे दिया कि उसे खरीदा नहीं जा सकता है.

यह देश बहुत बड़ा है. भाजपा के यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया. वहीं कांग्रेस भी ये कह सकती है कि 5 साल में भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया. लेकिन यह सब चुनाव के छह महीने तक चलना चाहिए, उसके बाद आपको गंभीरता से काम करना चाहिए. देश वहीं रहेगा, समस्याएं भी वहीं रहेंगी और उन समस्याओं के समाधान का तरीका भी वही रहेगा. भारत जैसे बड़े देश में आप कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं कर सकते हैं. शासन के हिसाब से भारत एक जटिल देश है. डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि वे तीन महीने में संपूर्ण अमेरिका को बदल देंगे. उन्हें पहले यह समझ में नहीं आया कि वे बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं. उन्होंने अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए दीवार बनाने का एक साधारण सुझाव दिया. भारत में उसी तरह के काम हो रहे हैं. स्वच्छ भारत एक बहुत ही आदर्श विचार है, लेकिन यह एक एनजीओ का काम है, प्रधानमंत्री का नहीं. उन्हें देश को स्वच्छ करने का काम एनजीओ के हवाले कर देना चाहिए. स्वच्छ भारत में उन्होंने महात्मा गांधी को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया, ये एक बेहतर विचार था. लिहाजा, ये गंभीर मसले हैं, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए. जहां तक नोटबन्दी का सवाल है, तो अब ये साबित हो गया है कि उन्होंने (प्रधानमंत्री) वो काम करने की कोशिश की, जो वो नहीं कर सकते थे. उन्होंने अपने वित्त मंत्री और अन्य संबंधित लोगों को विश्वास में लिए बिना ये फैसला कर लिया. उन्हें लगा कि इस फैसले से वे भारत के महान रक्षक बन जाएंगे.

कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित होने के नाते मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कहूंगा कि ब्लैक मनी का विकल्प देश को कहीं भी नहीं ले जाएगा. ये ऐसी समस्या नहीं है, जो आज ही पैदा हुई हो. ये समस्या किसी एक व्यक्ति के द्वारा पैदा नहीं की गई है. भाजपा भी सत्ता में आती–जाती रही है. उस दौरान भी ब्लैक मनी बनता रहा. विदेशी खातों में जो पैसे हैं, उसे लेकर प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए. कहा गया कि इतना लाख करोड़ है, उसे हम वापस लाएंगे. जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. सवाल ये है कि भारत में कितना पैसा वापस आया है? ये पैसा भारत शायद ही आए क्योंकि स्विस बैंक कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है. तो सवाल है कि पैसा गया कहां? हम वो पैसा भारत में लाना चाहते हैं कि उसे किसी और देश में जाने देना चाहते हैं. हमारा मकसद क्या है? मैं नहीं समझता कि ये सरकार क्या सोचती है? इसे अपना मकसद नहीं पता. लेकिन, एक चीज साफ है कि वे किसी भी तरह 2019 का चुनाव जीतना चाहते हैं. यही लक्ष्य है इस सरकार का. ठीक है. हरेक 5 साल के बाद चुनाव आते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के लिए ठोस काम होते रहना चाहिए. देखते हैं, क्या होता है?

feedback@chauthiduniya.com

बिना दिल मिलाए गले लगाने से कोई फ़ायदा नहीं

शुजात बुखारी

प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस विचार को ख़ारिज करने की कोशिश की कि वे कश्मीर समस्या से निपटने के लिए गंभीर नहीं हैं. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त के अपने पारम्परिक भाषण में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तीन शब्दों कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत का हवाला नहीं दिया. उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान कश्मीरियों को गले लगाने से होगा. उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि समस्या का समाधान न तो गाली से होगा और न ही गोली से, बल्कि सभी कश्मीरियों को गले लगाने से होगा और हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं. उनके इस बयान के तुरंत बाद हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने उनके इस बयान का स्वागत किया. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह और बहुत सारे अन्य नेताओं ने भी इस बयान का स्वागत किया. लेकिन, इस सब ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये बयान सिर्फ बयान भर न रहे, इस पर अमल भी हो.

अब तक अपने शासन के तीन वर्षों में नरेंद्र मोदी, एक अपार बहुमत के बाद भी, कश्मीर मसले पर कोई अंतर नहीं ला सके हैं, सिवाय नौकरशाहों द्वारा बनाई गई कठोर नीति का पालन करने के. 2016 में कश्मीर विद्रोह से निपटने के लिए जो तरीका अपनाया गया, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य के खिलाफ जनता के मन में क्रोध और निराशा से निपटने के लिए केवल ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा.

दिल्ली की नीति का हमने ये देखा कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए, घायल हुए, युवा लड़कों और लड़कियों की दृष्टि क्षतिग्रस्त हुई या वे बिल्कुल ही अन्धे हो गए. आधिकारिक तौर पर इन सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया गया. कश्मीरी लोगों और उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को ही दोष दिया गया. टीवी पत्रकारों ने ये थ्योरी दी कि ये सिर्फ पांच प्रतिशत लोग हैं, जो उपद्रव फैला रहे हैं और यही 5 प्रतिशत लोग कश्मीर में परेशानी के लिए जिम्मेदार थे. मीडिया ने दुखद रूप से नागरिकों की हत्याओं और दुर्घटनाओं को उचित ठहराया. मीडिया ने भी सरकारी नीति के साथ हाथ मिला लिया.

सरकार की तरफ से किसी तरह के इलाज या सामंजस्य बिठाने का कोई प्रयास नहीं किया गया. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के साथ गठबंधन सरकार का हिस्सा होने के बावजूद, जो वैचारिक रूप से भाजपा के मुकाबले दूसरे ध्रुव पर है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार ने एजेंडा ऑफ अलायंस के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया. इस अलायंस का फोकस राजनीतिक समस्या पर था. भाजपा हुर्रियत और पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर प्रतिबद्ध थी और भाजपा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस की रक्षा के लिए भी शपथ ली थी.

वाजपेयी जी बोल्ड व्यक्ति थे और उन्होंने कदम उठाए, जबकि पाकिस्तान ने धोखा दिया. वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम किया, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ वार्ता शुरू की और हुर्रियत को मेज पर लेकर आए. कई आलोचकों का सवाल है कि क्या वाजपेयी के सिद्धांत ने काम किया? भले ही ये पटरी से उतर गई, लेकिन इसने जमीन पर असर दिखाया और संघर्ष से पीड़ित लाखों लोगों के लिए उम्मीदें जगाईं. यहां स्थिति यह है कि मोदी केवल इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं. कश्मीरियों को अपनाए जाने का मतलब है कि उनके विचारों का सम्मान करना, भले ही वे विचार असहमति वाले क्यों न हो.

हालांकि, इस हाईलाइन रवैये से भी कोई परिणाम नहीं निकला, जो ये बता सके कि कश्मीर इस स्थिति में कोई प्रतिक्रिया दे रहा है. आतंकवाद का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया और अधिक से अधिक युवा इनके साथ जुड़ते चले गए. हुर्रियत को उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जाल में फंसाने का प्रयास किया, ये आरोप लगाकर कि हुर्रियत पाकिस्तान से पैसा लेकर कश्मीर में अस्थिरता फैलाते हैं. इससे हुर्रियत अस्थायी तौर पर तो हतोत्साहित हो सकता है, लेकिन इस सब से एक ऐसा वैकल्पिक लोकतांत्रिक स्पेस बनाने में मदद नहीं मिली, जिससे मोदी की नीति को कश्मीर में लागू किया जा सके.

एक स्थायी समाधान खोजने के लिए एक उपचारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसे एक स्पष्ट राजनीतिक आश्रय भी मिले, ताकि लोगों को आश्वासन मिल सके कि निरंतर वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से समाधान मिल जाएगा. तीन साल में इस राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया. कश्मीर से निपटने के लिए जिस तरह से सशस्त्र बलों को मोदी सरकार ने आगे किया, उससे ये धारणा मजबूत हुई है कि नई दिल्ली केवल कश्मीर को (एक जमीन के टुकड़े के रूप में) अपने पास रखना चाहती है. उसे यहां के लोगों और लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है.

इसने अपने सहयोगी पीडीपी से किए गए किसी भी वादे का सम्मान नहीं किया और इसकी बजाय राजनीतिक अपमान के भारी बोझ के तहत उन वादों को दफना दिया. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को एक राजनीतिक योद्धा से सिर्फ एक प्रशासक बना दिया गया और कश्मीर के लिए प्रमुख नीतिगत सुरक्षा फैसले दिल्ली से ही चल कर आते हैं. महबूबा को अपनी ही जमीन पर इस सब के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी है.

एक कारण है, जिसकी वजह से कश्मीर के लोग मोदी पर विश्वास नहीं करते. अतीत में उन्होंने वाजपेयी की कश्मीरीयत, जम्हूरियत और इंसानियत (केजेआई) की बात की. इससे लोगों को एक संभावित राजनीतिक समाधान की उम्मीद बंधी. मोदी अब तक सात बार ऐसा बोल चुके हैं. पहली बार 2014 में उन्होंने ये बात कही, जब वे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे. 26 मार्च 2014 को उन्होंने जम्मू में एक जनसभा में कहा कि वह कश्मीर पर वाजपेयी द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि यह मेरी इच्छा है कि वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया काम पूरा करें. यह मेरी इच्छा है और मैं इसके लिए बार–बार यहां आऊंगा.

प्रधानमंत्री कार्यालय में आने के बाद 4 जुलाई 2014 को उन्होंने कटरा में एक सभा में कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए मेरा संदेश यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्लान को अमल में लाकर लोगों के दिलों को जीतना है. इसी प्रकार, 22 नवंबर, 2014 को उन्होंने किश्तवार में कहा था कि जम्हूरियत, इंसानियत और कश्मीरीयत, अटल जी के इन शब्दों को कश्मीरी लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान है और इसने बेहतर भविष्य के लिए हर कश्मीरी युवाओं के मन में आशा जगाई है.

10 अगस्त 2016 को जब कश्मीर राजनीतिक अशांति से जल रहा था, तो उन्होंने इस बारे में बात की. लेकिन सत्ता में आने के बाद से वे उस दिशा में एक इंच भी आगे नहीं गए हैं. उनकी इस भावना की ठोस अभिव्यक्ति कहीं नहीं देखने को मिलती. वाजपेयी जी बोल्ड व्यक्ति थे और उन्होंने कदम उठाए, जबकि पाकिस्तान ने धोखा दिया. वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम किया, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ वार्ता शुरू की और हुर्रियत को मेज पर लेकर आए. कई आलोचकों का सवाल है कि क्या वाजपेयी के सिद्धांत ने काम किया? भले ही ये पटरी से उतर गई, लेकिन इसने जमीन पर असर दिखाया और संघर्ष से पीड़ित लाखों लोगों के लिए उम्मीदें जगाईं.

यहां स्थिति यह है कि मोदी केवल इसके बारे में बात करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं. कश्मीरियों को अपनाए जाने का मतलब है कि उनके विचारों का सम्मान करना, भले ही वे विचार असहमति वाले क्यों न हो. लेकिन जमीनी वास्तविकताओं को स्वीकार किए बिना, गले लगाने की ये पेशकश विफल ही होगी. इसके लिए ठोस कदम ही एक अनुकूल माहौल बनाएंगे. इसका एकमात्र तरीका यह होगा कि पाकिस्तान और कश्मीरी, दोनों के साथ बातचीत हो. पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस भाषण में पाकिस्तानी हिस्से वाले कश्मीर, गिलगिट–बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान की बात की गई थी. शायद इस साल सिर्फ कश्मीर का ही उल्लेख किया जाना था.■

–लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

कमजोर और हतोत्साहित विपक्ष लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता है

नीतीश कुमार द्वारा बिहार में लालू यादव के साथ सरकार न चलाने और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने के फैसले ने देश में पूरे विपक्ष को एक तरह से झकझोर दिया. उसने विपक्ष के भीतर नए सिरे से पनप रही खतरनाक कमजोरियों, उनके आपसी रिश्तों और उनकी एकता को लेकर उठ रहे सवालों पर गंभीर रोशनी डाली है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आखिरी बार विपक्ष की आंशिक एकता की कोशिश हुई थी. बिना किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने चुनाव में हाथ मिलाया था. अखिलेश यादव ने जी-जान से चुनाव प्रचार किया. वहीं कांग्रेस ने आधे मन से उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध को लड़ा और एकता का वो तरीका जनता की नजर में बेकार साबित हुआ. अखिलेश यादव से एक बड़ी चूक यह हुई कि उन्होंने विपक्षी एकता की कोशिश नहीं की, बल्कि सीटों के तालमेल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सामना करने की रणनीति बनाई. दूसरी तरफ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी को अपना मुख्य दुश्मन न मानते हुए भी उन्हें चुनाव में हराने की पूरी कोशिश की. हालांकि आखिरी दिनों में उन्होंने संकेत दिया कि चुनाव के बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो मायावती जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए समझौता कर सकते हैं. इस समझौते में अखिलेश यादव ने यह कभी साफ नहीं किया कि अगर वैसी स्थिति आई तो मुख्यमंत्री उनके दल का होगा या बहुजन समाज पार्टी का होगा. ये सारे सवाल और इनके भीतर निहित अंतर्विरोध उत्तर प्रदेश में जनता को समझ में नहीं आए.

उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव ने पहली बड़ी कोशिश की. हालांकि जब उन्होंने 27 अगस्त को रैली की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने महारैली कहा, तब उसका उद्देश्य दूसरा था. उद्देश्य था कि विपक्ष के सारे नेताओं को इकट्ठा कर 2019 के चुनाव में विपक्षी एकता का शंखनाद किया जाए. इस विपक्षी एकता का सूत्रधार बनने की इच्छा लालू यादव में थी. लेकिन बिहार की सरकार टूटने के फैसले के साथ ही रैली का फोकस विपक्षी एकता कम और नीतीश कुमार ज्यादा हो गए. यह स्वाभाविक था. बिहार में बाढ़ आई हुई थी. लालू यादव के पास पैसे नहीं थे. देश में माहौल उनके खिलाफ बना हुआ था. सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे उनके यहां पड़ चुके थे, जिसमें उनके पुत्र और पुत्री गले तक सने हुए हैं, ऐसा प्रचार हो रहा था. इसके बावजूद लालू यादव ने 27 अगस्त की रैली स्थगित नहीं की और भारी बाढ़ के खतरे के साथ उन्होंने रैली की. रैली की तैयारी में तेजस्वी यादव बिहार में प्रमुख जगहों पर घूमे. लालू यादव ने पटना के आस-पास के क्षेत्र पर अपनी सारी ताकत लगाई, ताकि बाढ़ की वजह से श्रोताओं के न आने का खतरा कम से कम किया जा सके.

बिहार में जो परिस्थितियां थीं, उनमें 27 अगस्त की सभा सफल थी. लोग अपने साधनों से आए थे, उत्साह से आए थे. सभा में उत्साह था, पर उत्साह का लक्ष्य बदला हुआ था. लक्ष्य बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का था. देश में 2019 के चुनाव में कैसे केन्द्र सरकार पर कब्जा किया जा सकता है, यह लक्ष्य कमजोर था. पहले चारों तरफ ये हवा फैली कि राहुल गांधी और मायावती रैली में नहीं आ रहे हैं. ममता बनर्जी भी जाएंगी या नहीं, ये भी किसी को पता नहीं था. इसके बावजूद लालू यादव ने हार नहीं मानी और इसे लालू यादव की हिम्मत कह सकते हैं कि अपने खिलाफ संपूर्ण विपरीत वातावरण होने के बावजूद उन्होंने रैली की. उनके लगातार समझाने का परिणाम यह निकला कि इस रैली में कांग्रेस और ममता बनर्जी भी शामिल हुई. देश की छोटी-मोटी पार्टियां भी शामिल हुईं. कुल मिलाकर उनकी संख्या 18 के आसपास मानी जा रही है. रैली में सबका सुर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ की आलोचना पर था. नरेन्द्र मोदी की नीतियों की असफलता को उजागर करने में लोगों ने कम ताकत लगाया.

इस रैली ने ये साबित किया कि लालू यादव अगर ताकत लगाएंगे तो विपक्षी एकता की नए सिरे से कोशिश हो सकती है. लेकिन लालू यादव के सामने कम चुनौतियां नहीं हैं. मायावती ने साफ कहा कि वो इस रैली में इसलिए नहीं आईं कि सीट बंटवारे के ऊपर एकता की बात टूट जाती है. इसलिए पहले देश में सीट बंटवारे की बात हो जाए कि लोकसभा में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा. लालू यादव ने कहा कि जब सब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तब सीट की बात होगी. इस तरह के सवालों से लालू यादव को जूझना पड़ेगा. जिस एक सवाल का उन्हें सामना करना पड़ेगा, वह यह कि विपक्ष का नेता कौन होगा, जिसे लोग देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी के मुकाबले देख सकें. राहुल गांधी अपनी आदत के हिसाब से विदेश में थे. मौटे तौर पर वो नौ महीने विदेश में रहते हैं और वो आपके हिसाब से तीन महीने देश में रहते हैं. वो विदेश क्यों जाते हैं? उससे क्या हासिल होता है, किसी को नहीं पता, लेकिन वो विदेश जाते हैं. अगर राहुल गांधी पटना की रैली में शामिल होते, तो इस रैली को एक नया आयाम मिलता. लेकिन राहुल गांधी के शामिल नहीं होने से विपक्षी एकता के पहले कदम को भटकने का मौका मिल गया. क्या लालू यादव, ममता बनर्जी को नेता बनाएंगे, अखिलेश यादव को देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार करेंगे या फिर राहुल गांधी के ऊपर दांव लगाएंगे. इस सवाल का जवाब अगले दो-तीन महीने में अगर नहीं तलाशा गया, तो लालू यादव की देश की विपक्ष को एक करने की कोशिश धूल धूसरित हो जाएगी. अगर लालू यादव गंभीर हैं, तो इस समय सिर्फ उनके पास एक क्षमता है कि वो विपक्ष के हर नेता के पास जाएं और पहले विपक्षी एकता के फॉर्मूले की तलाश करें. संभावित सीट बंटवारे पर सबकी राय जानें और ये भी साफ करें कि अगला चुनाव किस प्रक्रिया से लड़ा जाएगा. क्या विपक्ष की एक पार्टी बनेगी, क्या विपक्ष का एक मोर्चा बनेगा या सिर्फ सीटों का तालमेल होगा. मैं उन सवालों की ओर बिल्कुल नहीं जा रहा, जिन सवालों को लोग लालू यादव को लेकर उठा रहे हैं. मेरा मानना है कि देश में अब भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जो लालू यादव में संभावनाएं देखता है. उनकी क्षमता को पहचानता है. लेकिन लालू यादव की परेशानी यह है कि मनमोहन सिंह सरकार के समय जिस बिल को राहुल गांधी ने फाड़ा था और देश में वाहवाही मिली थी, वही बिल लालू यादव के आड़े खड़ा हुआ है. उनके राजनीतिक वनवास के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है. तो फिर लालू यादव के कदमों में लोग गंभीरता की जमीन का आकलन हर कदम पर करेंगे.

मेरा ये भी मानना है कि बिहार की रैली असफल नहीं रही. मैं संख्या के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और आरजेडी की अंताक्षरी को देख रहा था. सवाल ये नहीं है कि लालू यादव ने 10 लाख कहा, तो 10 लाख थे या नहीं थे या भारतीय जनता पार्टी ने जिस रैली को पच्चीस हजार कह दिया वो सत्य है या नहीं. सत्य ये है कि बिहार के लोग जिसमें पिछड़े समाज के लोग ज्यादा थे, उनकी एक संख्या अपने साधनों से राजनीतिक सवाल पर उत्साह के साथ गांधी मैदान पहुंची. वो संख्या दो लाख रही हो, तीन लाख रही हो, पांच लाख रही हो, इस बहस में जाना व्यर्थ है. लेकिन इस रैली ने यह बताया कि लालू यादव में अब भी लड़ने की क्षमता है. वहीं इस रैली से देश के पैमाने पर तेजस्वी यादव नामक एक नए नेता का उदय हुआ. तेजस्वी यादव को लोग राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन के मुकाबले आंकना शुरू कर चुके हैं. इस बात पर उनकी नजर है कि क्या तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार में रहते हैं या देश के दूसरे हिस्सों में भी जाने का साहस जुटा पाते हैं. लालू यादव को इस बात का एहसास होगा कि यह देश बहुत बड़ा है. अगर उन्हें नरेन्द्र मोदी के मुकाबले विपक्षी एकता का एजेंडा उठाना है तो उन्हें अभी से सारे देश में कम से कम 50-60 आम सभाएं करनी पड़ेंगी. इन आम सभाओं में जो नेता जाएंगे, वे अपने अंतर्विरोध को कैसे दूर करते हैं या उन्हें दूर करने में कौन व्यक्ति मुख्य रोल निभाता है, ये सवाल तो हैं. लालू यादव या देश के संपूर्ण विपक्ष के सामने शरद पवार की कांग्रेस का ढुलमुल रवैया भी एक सवाल बनकर खड़ा हुआ है. दक्षिण से सिर्फ एचडी देवेगौड़ा के नुमाइंदे दानीश अली इस रैली में थे. भारत के नक्शे के हिसाब से महाराष्ट्र से लेकर केरल तक का प्रतिनिधित्व इस रैली में नहीं था. इसलिए माना जाना चाहिए कि यह रैली विपक्षी एकता के नाम पर उत्तर भारत के तमाम नेताओं को इकट्ठा करने में तो कोई रोल अदा कर सकती है, पूरे देश में छाप छोड़ने में इस रैली का बहुत योगदान नहीं है.

इन सबके बावजूद इस रैली में लालू यादव ने विपक्ष को एक करने की क्षमता का एक नया परिचय दिया है और तेजस्वी यादव के रूप में एक नयी संभावना देश के सामने रखी है. तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेजप्रताप यादव ने इस रैली में यह घोषणा कर कि तेजस्वी यादव अर्जुन हैं, इस संभावना को खारिज कर दिया कि भविष्य में लालू यादव के परिवार में कोई राजनैतिक संघर्ष हो सकता है.

क्या इस रैली के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता को लेकर कोई बड़ी रैली करेंगे या ममता बनर्जी बंगाल में कोई रैली करेंगी या देवेगौड़ा कर्नाटक में कोई रैली करेंगे, ये सवाल हैं. इन तीन प्रदेशों के अलावा मध्य प्रदेश में कौन रैली करेगा, राजस्थान में कौन रैली करेगा, ओड़ीशा में कौन रैली करेगा, महाराष्ट्र में कौन रैली करेगा, ये सवाल मुंह बाए खड़े हैं. इन सवालों का उत्तर जब तक लालू यादव, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी नहीं देते, तब तक ये मानना चाहिए कि विपक्षी एकता का रास्ता अभी बिल्कुल सूना है. इसके ऊपर चलने वालों की तैयारी तो दिखाई देती है, लेकिन वे चलते हुए नहीं दिखाई देते. जितना कमजोर, दिशाहीन, अशक्त और निरुत्साहित विपक्ष इस समय है, वैसा भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं रहा. विपक्ष का अशक्त, निर्जीव और निरुत्साहित होना लोकतंत्र के लिए कभी शुभ होता ही नहीं है.■

इस रैली में लालू यादव ने विपक्ष को एक करने की क्षमता का एक नया परिचय दिया है और तेजस्वी यादव के रूप में एक नयी संभावना देश के सामने रखी है. तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेजप्रताप यादव ने इस रैली में यह घोषणा कर कि तेजस्वी यादव अर्जुन हैं, इस संभावना को खारिज कर दिया कि भविष्य में लालू यादव के परिवार में कोई राजनैतिक संघर्ष हो सकता है. क्या इस रैली के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता को लेकर कोई बड़ी रैली करेंगे या ममता बनर्जी बंगाल में कोई रैली करेंगी या देवेगौड़ा कर्नाटक में कोई रैली करेंगे, ये सवाल हैं. इन तीन प्रदेशों के अलावा मध्य प्रदेश में कौन रैली करेगा, राजस्थान में कौन रैली करेगा, ओड़ीशा में कौन रैली करेगा, महाराष्ट्र में कौन रैली करेगा, ये सवाल मुंह बाए खड़े हैं. इन सवालों का उत्तर जब तक लालू यादव, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी नहीं देते, तब तक ये मानना चाहिए कि विपक्षी एकता का रास्ता अभी बिल्कुल सूना है. इसके ऊपर चलने वालों की तैयारी तो दिखाई देती है, लेकिन वे चलते हुए नहीं दिखाई देते.

editor@chauthiduniya.com

एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ सूखे से मर रहे यूपी के लोग

कुदरत की मार, सरकार बेकार

बुंदेलखंड में सूखे की तबाही, भूख से फिर मर गया मजदूर

खूफी यायावर

यूपी के कई जिलों में बारिश और बाढ़ तबाही मचा रही है. शासन-प्रशासन का राहत कार्य और मुख्यमंत्री का हवाई सर्वेक्षण सब एक घिसी-पिटी फिल्म की तरह दोहरा रहा है. लोग बारिश और बाढ़ से मर रहे हैं और इसी प्रदेश में लोग सूखे से भी मर रहे हैं. अभी पिछले ही दिनों बुंदेलखंड में एक आदमी भूख से मर गया. आदतन प्रशासन ने कह दिया कि वह बीमारी से मरा. गनीमत है कि प्रशासन ने बसपाई शासन की नकल करते हुए यह नहीं कहा कि मरने वाला पागल था.

बुंदेलखंड में महोबा जिले के धंडुआ गांव में भुखमरी के कारण छुट्टन नामक जिस व्यक्ति की मौत हुई वह मजदूर था. उसकी पत्नी ने कहा कि हफ्तेभर से घर में चूल्हा जला ही नहीं. मनरेगा में कई दिन से छुट्टन को काम नहीं मिल रहा था. परिवार भीषण आर्थिक तंगी से गुजर रहा था. उसके बच्चे कई दिनों से भीख मांगकर पेट भर रहे थे. हालात ऐसे थे कि छुट्टन का अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे. छुट्टन के पास कुछ जमीन तो थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह खेती नहीं कर पा रहा था. छुट्टन और उसकी पत्नी उषा अपने तीन बच्चों और बूढ़ी मां के पालन-पोषण के लिए मनरेगा में मजदूरी करते थे. दोनों ने मनरेगा में मजदूरी की थी, लेकिन उन्हें उसका भी भुगतान नहीं मिला. प्रशासन कहता है कि छुट्टन बीमार था, इसी वजह से मरा. छुट्टन का परिवार कहता है कि भूख की वजह से छुट्टन की तबीयत खराब होती गई और मौत हो गई. छुट्टन की विधवा उषा कहती हैं कि उनके पति पर दो लाख रुपए का कर्ज था. छुट्टन के जीते जी उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा, लेकिन उसके मरने के बाद प्रशासन के अफसर छुट्टन के घर आए. उसके अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपए दिए. कुछ अनाज भी दिया और चले गए. स्थानीय लोग कहते हैं कि गांव के लोगों ने चंदा देकर छुट्टन का अंतिम संस्कार किया. इसके पहले भी भुखमरी के कारण महोबा के ही ऐला गांव में नत्थू रैदास की मौत हो चुकी है.

उत्तर प्रदेश में एक तरफ बारिश और बाढ़, तो दूसरी तरफ सूखा विचित्र त्रासदी की तरह आया है. पूरब में बारिश से तबाही है, तो पश्चिम में बारिश के अभाव में खेत सूखे पड़े हैं. आगरा क्षेत्र के किसान बारिश के लिए तरस रहे हैं. इटावा मैनपुरी क्षेत्र में ऐसे ही हालात हैं. बुंदेलखंड के चित्रकूट और बांदा में बारिश के लिए पूजा-पाठ हो रहा है और किसानों की आत्महत्या की खबरें भी आ रही हैं. जालौन और हमीरपुर में भी बारिश नहीं हुई. जबकि पूर्वांचल के जिलों में बाढ़ की विनाशलीला चल रही है. नेशनल हाइवे समेत कई सम्पर्क मार्ग डूब गए या बह गए. गांव, कस्बे, बाजार जलमग्न हैं. हजारों परिवार बांधों, सड़कों और रेलवे ट्रैक के किनारे शरण लिए हैं. बिजली और टेलीफोन सेवा ठप्प पड़ी है. सेना, एनडीआरएफ, पीएसी, एसएसबी बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद में लगी है. दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश सूखे के कारण बेहाल हो रहा है. बुंदेलखंड तो लगातार प्राकृतिक आपदा का शिकार हो रहा है. कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि बुंदेलखंड को बर्बाद कर रहा है. यहां के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बुंदलेखंड में पिछले पांच वर्ष में 3223 किसानों ने आत्महत्या की. ओलावृष्टि और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण वर्ष 2015 और 2016 में 1500 से अधिक किसानों की मौत हुई. यह तो आधिकारिक आंकड़ा है, जबकि गैर सरकारी सर्वेक्षणों के आधार पर निकाले गए आंकड़े सरकारी आंकड़े से कहीं अधिक हैं.

भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष 2016 के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों पर कुल कृषि ऋण 86241.20 करोड़ है. भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि ढाई एकड़ से कम जोत वाले 31 प्रतिशत सीमांत और लघु किसानों को ऋण दिया गया है. यानि, प्रदेश सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के कुल 27,419.70 करोड़ का कर्ज माफ किया. कर्जे का औसत प्रति किसान लगभग 1.34 लाख रुपए का है. सरकारी दस्तावेज कहता है कि कर्जा लेने वाले लघु और सीमांत कृषकों की संख्या लगभग डेढ़ करोड़ है. जबकि 10 करोड़ किसानों में से 2.33 करोड़ लघु और दो करोड़ सीमांत कृषक हैं. स्पष्ट है कि इन सभी पर किसी न किसी प्रकार का कर्ज जरूर है. फिर सवाल उठता है कि सरकार ने किस आधार पर महज डेढ़ करोड़ कर्जदार किसानों की सूची बनाई? खैर, उत्तर प्रदेश का इस वर्ष (2016-17) का सालाना बजट 3.46 लाख करोड़ रुपए का है. सरकार को इस वर्ष के कुल बजट का 33 प्रतिशत हिस्सा कर्ज माफी के लिए बैंकों को देना होगा. इससे वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश को 49,960.88 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा होगा. यह घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है. कर्ज माफी के बाद यह घाटा 55 प्रतिशत बढ़ जाएगा. उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत पहले से ही खराब चल रही है. इस प्रदेश में किसानों की हालत यह रही है कि वर्ष 2013 में यहां 750 किसानों ने आत्महत्याएं की थीं. वर्ष 2016 में 1800 किसानों ने आत्महत्या की. आधे से अधिक आत्महत्याएं सूखाग्रस्त बुंदेलखंड और गरीब पूर्वांचल में हुईं. इन आत्महत्याओं का मुख्य कारण किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का ऋण और उससे भी अधिक साहूकारों का ऋण है. साहूकारों से किसानों ने 20 से 24 प्रतिशत ब्याज पर कर्जा ले रखा है. इसमें किसान की खेती-बाड़ी सब गिरवी पड़ी हुई है और किसान साहूकारों का बंधुआ मजदूर बन गया है. साहूकारों से किसानों को मुक्ति दिलाने की सरकार की तरफ से कोई कानूनी कोशिश नहीं हो रही है.

सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के गांवों में हैंडपंपों से पानी निकलना बंद हो गया है. कुएं सूखे हैं. भूगर्भजल का स्तर पाताल में चला गया है. चुनिंदा लोगों के पास गहरे खर्चीले हैंडपंप हैं. लेकिन यह पानी कुछ खास लोगों की ही प्यास बुझाती है. बुंदेलखंड के 80 प्रतिशत किसान कर्ज में डूबे हैं. रोजी-रोटी की तलाश में शहरों में मजदूरी के लिए भाग चुके हैं. गांव के गांव खाली पड़े हैं. केंद्र सरकार की संसदीय समिति की रिपोर्ट तक यह बता चुकी है कि बुंदेलखंड से लोगों का अंधाधुंध पलायन हो रहा है. केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि बांदा से 7 लाख 37 हजार 920, चित्रकूट से 3 लाख, 44 हजार 920, महोबा से 2 लाख, 97 हजार 547, हमीरपुर से 4 लाख, 17 हजार 489, उरई से 5 लाख, 38 हजार 147, झांसी से 5 लाख, 58 हजार 377 और ललितपुर से 3 लाख 81 हजार 316 लोग पलायन कर चुके हैं. केंद्र सरकार की यह रिपोर्ट दो साल पहले की है. अब तो यह आंकड़ा और बढ़ चुका होगा. यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस धरती से यमुना, चंबल, धसान, बेतवा और केन जैसी नदियां बहती हों, वहां से भूख-प्यास के कारण लाखों लोग पलायन कर जाते हैं. जहां दस वर्षों में चार हजार से अधिक किसान खुदकुशी कर लेते हैं. वहीं पत्थर खोद कर नेता और माफिया करोड़पति और अरबपति होते रहते हैं. बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के सात जिले झांसी, हमीरपुर, बांदा, महोबा, जालौन और चित्रकूट आते हैं. इन सात जिलों में 19 विधानसभा सीटें हैं. इन सभी सीटों पर भाजपा जीती है. लेकिन इस क्षेत्र की असलियत है, टूटी-फूटी सड़कें, मील दर मील सूखे खेतों का रेगिस्तान, छोटे-छोटे बियाबान पड़े गांव, फूस और खपरैल की छतों के नीचे बैठे सूखे मरियल लोग और मातमी सन्नाटा. ■

feedback@chauthiduniya.com

भूखमरी के खिलाफ जंग लड़ रहा है 'रोटी बैंक'

बुंदेलखंड में पिछले करीब तीन वर्षों से भुखमरी के खिलाफ 'रोटी बैंक' जंग लड़ रहा है. 'रोटी बैंक' के प्रणेता और संयोजक स्वामी तारा पाटकर कहते हैं कि इसकी शुरुआत तब हुई थी, जब पूरा बुंदेलखंड अकाल की चपेट में था. 'रोटी बैंक' ने भूखों की मदद करने के लिए सक्षम लोगों से दो रोटी और थोड़ी सब्जी देने की अपील की, तो हजारों हाथ मदद के लिए उठ खड़े हुए. 'रोटी बैंक' भोजन इकट्ठा करके भूखे, लाचार और जरूरतमंदों को वितरित करता है. यह सिलसिला आज भी अनवरत जारी है. महोबा में 'रोटी बैंक' की पांच शाखाएं चल रही हैं, जिनमें लोग भोजन जमा करते हैं और इन शाखाओं से गरीबों को दिनभर भोजन बांटा जाता है. शाम को कुछ स्वयंसेवक घरों से भी भोजन इकट्ठा करते हैं और उसे गरीबों को खिलाते हैं. पाटकर कहते हैं, 'हम नहीं चाहते कि बुंदेलखंड दुनिया में भुखमरी व पिछड़ेपन के लिए जाना जाए. इसीलिए हमने लोगों के सहयोग से 'रोटी बैंक' की शुरुआत की. आखिर हम संवेदनहीन सरकार के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे. हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास कोई भूखा रहे, अपने शहर में कोई व्यक्ति भूखा सोए.' महोबा के 'रोटी बैंक' मॉडल से प्रेरित होकर बुंदेलखंड के हमीरपुर, उरई, बांदा आदि जनपदों में भी 'रोटी बैंक' शुरू हुए, जो सफलतापूर्वक चल रहे हैं. इसके अलावा लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, हजारीबाग, इंदौर समेत देशभर में सौ से अधिक रोटी बैंक चल रहे हैं. ■

राष्ट्रवादी पार्टी की सांसद का ध्वज-ज्ञान और सामान्य-ज्ञान दोनों चौपट

चौपटा-नंदनों के बूते भाजपा

उल्टा झंडा फहराया और अटल की फोटो पर फूल चढ़ा कर दे दी श्रद्धांजलि

संजीव गुप्ता

उत्तर प्रदेश में मदरसों ने जश्न-ए-आजादी पर झंडा फहरा कर और राष्ट्रगान गाकर अपनी देशभक्ति और तिरंगे के प्रति अपना सम्मान और प्रतिबद्धता ज्ञापित की. लेकिन तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा की सांसद ने जिस तरह से राष्ट्रध्वज का अपमान किया, वह भाजपा के राष्ट्रवाद की असलियत है. भाजपा ऐसे ही चौपटनंदनों के बूते देश में राष्ट्रभक्ति की भावना लाएगी. मदरसों से स्वतंत्रता दिवस के त्यौहार का सबूत मांगने वाली भाजपा राष्ट्रध्वज के अस्मान और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने की मूर्ख हरकत पर शातिराना चुप्पी साधे हुई है. लेकिन सामाजिक स्तर पर इस घटना की खिल्लियां उड़ रही हैं.

सीतापुर के धौरहरा संसदीय क्षेत्र के पिसांवा ब्लॉक में आयोजित तिरंगा यात्रा के दरम्यान स्थानीय भाजपा सांसद रेखा वर्मा बड़े शान से उल्टा झंडा लिए अगुवाई कर रही थीं. लोग भी सांसद की इस बेवकूफाना राष्ट्रभक्ति पर मौज ले रहे थे लेकिन कोई उन्हें इस गलती पर ध्यान दिलाने की समझदारी नहीं दिखा रहा था. धौरहरा की 'दीदी' के इस बौद्धिक रवैये को स्थानीय लोग दीदे फाड़ कर देख रहे थे. दरअसल, महोली के पिसावां ब्लॉक में स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले तिरंगा यात्रा आयोजित की गई थी. यह यात्रा कार्यालय परिसर से शुरू होकर जल्लापुर चौराहे से बरगावां और फिर सेज खुर्द होते हुए वापस पिसावां पहुंची. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति स्थल के नजदीक पार्टी पदाधिकारियों ने भाजपा सांसद का स्वागत किया. सांसद ने पूरे आन-बान-शान से उल्टा राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर यात्रा की शुरुआत की और बाकायदा तस्वीरें भी खिंचवाईं. भाजपा सांसद और वहां मौजूद भाजपाइयों ने तिरंगा के नाम पर हो रही यात्रा की शुरुआत ही राष्ट्रध्वज के अपमान से की. इस दौरान भाजपा के पिसावां मंडल अध्यक्ष शिवप्रताप सिंह, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष इन्दु सिंह, भाजपा के जिला महामंत्री अचिन मेहरोत्रा, सुमित तिवारी, हरीश पटेल, नैमिष रतन तिवारी सहित तमाम भाजपाई मौजूद थे. लेकिन किसी ने भी राष्ट्रध्वज पर ध्यान नहीं दिया. सबका ध्यान झंडे से अधिक सांसद की चाटुकारिता पर था. ■

अटल बिहारी वाजपेयी को दे चुकी हैं श्रद्धांजलि

भाजपा सांसद रेखा वर्मा की बौद्धिकता और उनके सामान्य ज्ञान का यह कोई पहला उदाहरण नहीं है. इसके पहले भी वे ऐसा उदाहरणीय ज्ञान-प्रदर्शन करती रही हैं. हरगांव विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम में वे बड़ी शिद्दत से अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दे चुकी हैं. चुनाव जीतने के बाद रेखा वर्मा का हरगांव विधानसभा क्षेत्र में स्वागत समारोह आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम के आयोजक भी उतने ही महामूर्धन्य थे. उन्होंने एक ही पंक्ति में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो के साथ-साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी लगा रखी थी. दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माला भी चढ़ी हुई थी. बस फिर क्या था, भाजपा सांसद रेखा वर्मा ने वहां पहुंचते ही दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो पर फूल चढ़ा कर श्रद्धांजलि अर्पित कर दी. सामान्य ज्ञान से महरूम भाजपा सांसद को यह पता ही नहीं था कि अटल जी अभी मरहूम नहीं हुए हैं. सामान्य-ज्ञान में कार्यक्रम के आयोजक भी उतने ही 'प्रखर-प्रतियोगी' साबित हुए. ■

feedback@chauthiduniya.com

लद गए लाल हरे और नीले, अब भगवा कपड़े सी ले

रंग बदल रहे, ढंग नहीं...

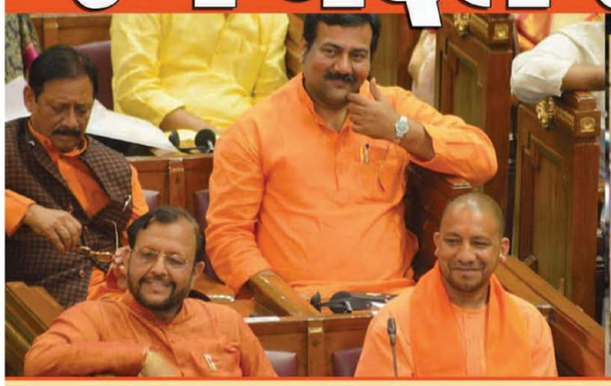

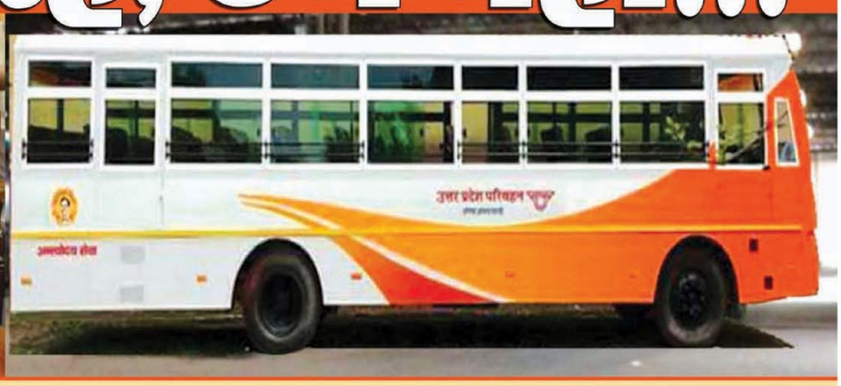

यूपी को रंग रोगः सड़क परिवहन निगम की बसें रंगेंगी भगवा रंग में

नेता मंत्री कार्यकर्ता खरीद रहे भगवा कपड़े, दुकानदार काट रहे चांदी

अखिल पांडेय

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों का विचित्र रंग-ढंग है. जो भी पार्टी सत्ता में आई, वह प्रदेश को अपने ही रंग में ढालने की कोशिश करने लगती है. इस लत से यूपी को रंग रोग लग गया है. लोग रंग बदलता देखते हैं, पर ढंग बदलता नहीं देखते. सत्ता में बसपा आई थी, तो नेताओं की टोपी से लेकर परिवहन निगम की बसों और रोड डिवाइडरों तक के रंग नीले होने लग गए थे. सपा आई तो नेताओं की टोपी, बसें और सपाइयों के मिजाज हरे और लाल रंग में दिखने लगे. अब भाजपा आई है, तो सब तरफ भगवा-भगवा नजर आ रहा है. प्रदेश में अब बसें भी भगवा रंग में पुती नजर आएंगी. रंगों का रोग मौलिक तौर पर भाजपाइयों का ही फैलाया हुआ है. कल्याण सिंह जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने परिवहन निगम की बसों का रंग भगवा कराया था. इसके बाद तो सभी पार्टियों को रंग-रोग लग गया. अब जल्दी ही उत्तर प्रदेश के यात्री भगवा रंग की रोडवेज बसों में सफर शुरू करेंगे. राजधानी समेत प्रदेशभर की सड़कों पर भगवा रंग की रोडवेज बसें दौड़ती नजर आएंगी. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम शीघ्र ही भगवा रंग से सराबोर अंत्योदय बस सेवा का शुभारंभ करने जा रहा है.

उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हुए तकरीबन छह महीने हो चुके. योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही लोगों के माथे और कंधे पर भगवा रंग का गमछा दिखने लगा. मोटरसाइकिलों से लेकर मोटर वाहन तक का रंग भगवा होने लगा और छह माह बीतते-बीतते यूपी पर भगवा रंग छा गया. इस भगवा रंगीकरण पर सरकारी योजना कम चाटुकारिता का रंग अधिक हावी और प्रभावी है. परिवहन निगम की बसों की तो बात छोड़िए, अब तो 'समाजवादी एम्बुलेंस' (102-108) का भी रंग भगवाई होने जा रहा है. एम्बुलेंसों का नाम भी बदला जाएगा. स्वाभाविक है कि उसका नाम अब 'समाजवादी' नहीं रहेगा. अब एम्बुलेंस का नाम किसी भाजपाई महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा. अब तो बाजार में भी देखिए तो जैकेट, साड़ी, पगड़ी, तौलिया, गमछा, घर के साज सामान, यहां तक कि टेलीफोन और तार के रंग भी भगवा होने लगे हैं. छुटभैये चाटुकार नेताओं के साथ-साथ बड़े नेता, मंत्री और विधायक तक अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए भगवाई निष्ठा का रंग कपड़ों पर पोत रहे हैं. भगवाई कपड़े बेचने वाले एक दुकानदार ने कहा कि नेताओं का वश चले, तो वे अपना मुंह भी भगवा रंग में पुतवा लेंगे. फिर उसी दुकानदार ने इस संवाददाता से पूछा कि क्या किसी पार्टी का रंग काला है? फिर स्वगत बोला, 'ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई, तो नेता मुंह काला करके घूमते मिलेंगे'. आप सत्ता के गलियारे में घूमें, आपको मंत्री, विधायक, नेता-कार्यकर्ता सब भगवा रंग की सदरी (जैकेट) और भगवा रंग का तह किया गमछा कंधे पर रखे दिखेंगे. महिला नेता और महिला कार्यकर्ता भी अब भगवा रंग की ही साड़ियों में दिख रही हैं. इकलौते सिख मंत्री भी भगवा रंग की पगड़ी में दिख रहे हैं और इकलौते मुस्लिम मंत्री भी भगवा रंग के कुर्ते और जैकेट में नजर आ रहे हैं. उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भले ही भीतर-भीतर मौके की तलाश में रहते हों, लेकिन ऊपर से भगवा रंग की जैकेट पहने कार में भगवा रंग की कवर वाली सीट पर बैठे हुए योगी के परम समर्थक दिखने-दिखाने की कोशिश करते नजर आते हैं.

जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सवाल है, तो उस सवाल का सारा जवाब भगवा में ही है. जिन कुर्सियों पर वे बैठते हैं वो भी भगवा रंग की चादर से ढंकी रहती हैं. उनके कार्यालय का सोफा, कुर्सी, पर्दे सब पर भगवा रंग है. मुख्यमंत्री सचिवालय में योगी के कार्यालय कक्ष से लेकर कैबिनेट सभाकक्ष तक भगवा ही भगवा है. यहां तक कि माइक्रोफोन के तार तक भगवा कपड़े में लपेट दिए गए हैं. दिलचस्प तो यह है कि योगी को भगवा रंग पसंद है, तो उनके चाटुकार नौकरशाह उन्हें नारंगी रंग का 'मिरांडा' या वैसा ही 'ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक' भी पिलाते हैं. पिछले दिनों बुंदेलखंड के दौरे के समय मुख्यमंत्री को नारंगी रंग वाला ही कोल्ड ड्रिंक दिया गया और जब वे वाराणसी गए, तो वहां भी भगवा रंग छाया रहा. मेजों को भी भगवा रंग से ही ढांप दिया गया था.

अब आते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को भगवा रंग में रंगने की मची होड़ पर. भाजपा सरकार ने गरीबों की सुविधा के लिए अंत्योदय बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया. इन बसों का किराया सामान्य बसों की तुलना में कम होगा. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष में इसकी शुरुआत होगी. 25 सितम्बर को इसका उद्घाटन होगा. अंत्योदय बस सेवा की बसें भगवा रंग की होंगी. परिवहन निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक (तकनीकी) जयदीप वर्मा ने कहा कि इन बसों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. भगवा रंग की जो बसें यूपी की सड़कों पर उतरेंगी, इन बसों की सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें यूरो-4 इंजन लगा हुआ है, जिससे प्रदूषण नहीं फैलेगा. 52 सीटर बसें नई तकनीकी से लैस होंगी. पहले चरण में भगवा रंग की 50 बसों का संचालन किया जाएगा. ये बसें कानुपर में रोडवेज की राममनोहर लोहिया केंद्रीय कार्यशाला में तैयार की जा रही हैं. उल्लेखनीय है कि प्रदेश की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार ने गरीबों को रोडवेज बसों में सफर की सुविधा देने के लिए समाजवादी ग्रामीण लोहिया बस सेवा की शुरुआत की थी. इन बसों को सपा के झंडे के ही रंग में रंगा गया था.

उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने का असर सारे विभागों पर पड़ता है, लेकिन परिवहन निगम ऐसा विभाग है, जो सरकार बदलते ही सबसे पहले सरकारी पार्टी के रंग में रंग जाता है. यूपी में सपा सरकार के जाते ही और भाजपा सरकार के आते ही परिवहन निगम ने बसों का रंग हरा-लाल की जगह भगवा करने की तैयारी शुरू कर दी थी. बसपा काल में बसों के बेड़े में जब वातानुकूलित वॉल्वो बसें शामिल हुई थीं, तो उन बसों का रंग नीला कर दिया गया था. बसपाई आगमन के वर्ष 2007 में आलमबाग बस स्टेशन से बसों का संचालन शुरू हुआ और हाईटेक वॉल्वो बस सेवा लांच हुई थी. बसपा सरकार ने उसी समय बसों पर पार्टी का रंग चढ़ाने का काम शुरू कर दिया. साधारण बसों को नीले रंग में पोत कर उन बसों का नाम 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' रख दिया गया. इसके बाद सौ करोड़ के सरकारी अनुदान से नीले रंग की बसपाई वॉल्वो बसें खरीदी गईं. तब से नीले रंग की वॉल्वो और नीले रंग की ही 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' बसें प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रही हैं. बसपा सरकार के जाने के बाद सपा ने सत्ता में आते ही अपनी पार्टी का रंग बसों पर चढ़ाना शुरू किया. समाजवादी लोहिया ग्रामीण बस सेवा के नाम से वर्ष 2014 में डेढ़ हजार बसें लांच की गईं, सब की सब हरे और लाल रंग के सपाई कलेवर में. परिवहन निगम के इस रंग-रोगन पर खुश होकर अखिलेश सरकार ने परिवहन निगम का एक तिहाई टैक्स माफ कर दिया, जिससे निगम को 76 करोड़ का सीधा फायदा हुआ. अब भाजपा की सरकार आ गई है. स्वाभाविक है कि रंग बदलेगा. हालांकि सरकार का निर्णय आने के पहले ही रंग-रोग से ग्रस्त परिवहन निगम ने बसों को भगवा रंग में रंगने की तैयारी शुरू कर दी थी. निगम के अधिकारी कहते हैं कि बसों को पार्टी के रंग में रंगने की शुरुआत भाजपा सरकार के ही कार्यकाल के दौरान हुई थी. कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे, तब पहली बार परिवहन निगम की बसों पर हल्का भगवा रंग चढ़ाया गया था. अब तो भाजपा की सत्ता पर पकड़ भी गहरी है, इसलिए बसों पर भगवा रंग भी गहरा ही चढ़ रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

महिलाओं के लिए चलेंगी गुलाबी बसें

नीली, हरी-लाल और भगवा रंग की बसें चलेंगी तो गुलाबी बसें पीछे क्यों रहें! इन गुलाबी बसों के पीछे गुलाबी-गैंग का हाथ नहीं बल्कि इसके पीछे महिला-सशक्तिकरण का रंग है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में निर्भया फंड के तहत प्रदेश में 50 गुलाबी (पिंक) बसों का संचालन होना है. इन बसों का रंग गुलाबी होगा और इनमें महिला यात्रियों को ढेर सारे तोहफे भी मिलेंगे. इन बसों में महिला यात्रियों को सुरक्षा के साथ ही किराए में छूट, मुफ्त वाई-फाई की सुविधा, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और जूस उपलब्ध कराने की भी योजना है. गुलाबी बसों से सौ किलोमीटर या इससे अधिक दूरी तक सफर करने वाली महिलाओं को खाना दिया जाएगा. अभी तक परिवहन निगम में महिलाओं के लिए मात्र एक एसी पिंक बस थी, जिसमें महिला यात्रियों को फ्री वाई-फाई के साथ टीवी की सुविधा और पीने का पानी मिलता था. महिला यात्रियों को सबसे बड़ी सुविधा यह मिलेगी कि अगर एक साथ पांच महिलाओं ने एक ही स्थान से टिकट बुक कराया, तो पिंक-बस उन्हें 'पिक' करने उनके द्वारा बताए गए एक निर्धारित स्थान तक जाएगी. पिंक बसों के सफल संचालन के लिए परिवहन निगम कई ऐसे गर्ल्स हॉस्टल और दफ्तरों को चिन्हित कर रहा है, जहां से अधिकांश महिलाएं शुक्रवार की रात को अपने घरों के लिए सफर करती हैं. इनमें से कुछ जगहों पर परिवहन निगम अपने बोर्डिंग प्वाइंट बनाएगा, जहां से महिला यात्री आराम से बस पकड़ सकेंगी. पिंक बसों में सफर करने वाली महिलाओं के साथ उनके सगे परिजनों को भी सफर करने की इजाजत दी जाएगी. इसके लिए सम्बन्धित व्यक्ति को अपनी अधिकृत पहचान बतानी होगी. अगर किसी एक महिला ने बस में सफर करने के लिए किसी अन्य महिला को भी तैयार किया, तो उसे किराए में पांच से 10 फीसद तक छूट दी जाएगी. ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर भी महिलाओं को किराए में अतिरिक्त छूट मिलेगी.

पिंक बसों से सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजामात किए जा रहे हैं. इसके लिए निगम अलग से 83 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है. बसों को सुरक्षा की दृष्टि से अत्याधुनिक मशीनरी से लैस किया जाएगा. बसों में सीसीटीवी कैमरों के साथ ही जीपीएस और पैनिक-बटन भी लगा होगा. ब्लू-टूथ से डीवीआर कनेक्ट होगा. जिससे सीसीटीवी से होने वाली रिकॉर्डिंग कंट्रोल रूम के डीवीआर में सुरक्षित रहेगी. महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'आदिशक्ति' ग्रुप बनाया जा रहा है, जो महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा. 'आदिशक्ति' ग्रुप में चार सौ महिलाएं शामिल होंगी, जिनमें वर्तमान में रोडवेज में तैनात तीन सौ महिला कंडक्टर और सौ महिला अधिकारी व कर्मचारी शामिल होंगी. 'आदिशक्ति' ग्रुप के पास 24 इंटरसेप्टर हर समय मौजूद रहेंगे. ये सभी इंटरसेप्टर वायरलेस और जीपीएस से लैस होंगे. इंटरसेप्टर पर एक पुरुष ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट और एक महिला ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट हमेशा तैनात रहेंगे. उनके साथ पुलिस की चौकस टीम साथ रहेगी, जिसमें पुरुष और महिला पुलिसकर्मी साथ-साथ तैनात रहेंगे. पिंक-बसों में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों का अलग से एस्कॉर्ट रखने की योजना पर भी विचार-विमर्श चल रहा है. ■

VASTU DOORS
सुरक्षा का वादा
www.vastudoors.com

* मजबूत
* दीमकरोधी
* सीलनरोधी
* जंकरोधी
by वास्तु विहार®
FINAL TOUCH
by वास्तु विहार®

अब, घर सजाने की बारी...
Phone : 7280023037, 9534095340

चम्पारण के लोगों के लिए प्रलयकारी साबित हुई भारी बारिश और उफनाई नदियां

बाढ़ ने मचाई तबाही

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ ग्रस्त पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण का दौरा किया और राहत कार्यों का निरीक्षण कर पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने मोतिहारी में विशेष डीएम अनुपम कुमार से राहत कार्यों की जानकारी ली, वहीं बेतिया में भी राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की. सुगौली के एक कम्युनिटी किचेन में उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और उनकी समस्याएं सुनीं.

राकेश कुमार

नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार वर्षा होने के कारण पहाड़ी नदियों सहित बागमती, त्रिवेणी, कमला और नारायणी में एकाएक पानी का सैलाब आ गया और इसने पूरे चम्पारण को जलमग्न कर दिया. पूर्व के सभी रिकार्ड तोड़ते हुए इस बाढ़ ने जो क्षति पहुंचाई है, उसे पूरा करने में कई वर्ष लग जाएंगे. इस बाढ़ ने जिन लोगों को काल के गाल में पहुंचा दिया, वे तो कभी लौट कर आ भी नहीं सकते. दोनों जिलों, पूर्वी चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण के लोगों के लिए ये बाढ़ एक तरह से काल बनकर आई और जन-जीवन में जहर घोल दिया.

प्रलयकारी बाढ़ का कहर

पूर्वी चम्पारण के 22 प्रखण्डों के 260 पंचायतों में बाढ़ कहर बनकर टूट पड़ी. इससे यहां करीब 24 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. मोतिहारी, बंजरीया, सुगौली, रामगढ़वा, चिरैया और पताहीं सबसे ज्यादा प्रभावित प्रखण्डों में शामिल हैं. 12 अगस्त को मध्य रात्रि में आई बाढ़ 24 अगस्त तक रही. बुढ़ी गंडक, बागमती, लाल बकेया, कछुआ, सरिसवा, तियर, बंगरी, पसाह, दुधौरा, कड़िया आदि नदियों ने लगभग 40 लाख की आबादी को दस दिनों तक डुबोए रखा. बाढ़ प्रभावितों की मानें, तो इस बाढ़ ने 1974, 1986 और 2007 में आई भीषण बाढ़ को भी छोटा साबित कर दिया. पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिला. एक स्थानीय बुजुर्ग ने बताया कि हमनें जिन्दगी में ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी. इस बाढ़ ने घर-द्वार, खेत-खलिहान और फसलों की जो क्षति की, उसकी भरपाई कैसे और कब तक होगी, कहा नहीं जा सकता. बाढ़ खत्म होने के बाद अब तबाही का असली मंजर सामने आने लगा है.

तबाही का मंजर

जिला प्रशासन के प्रारंभिक जांच के अनुसार, जिले में 15 हजार बासगित घर ध्वस्त हो गए हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस बाढ़ में 37 लोगों की मौत हो गई. कई लोग मौत के मुंह से बच के निकले. बाढ़ के पानी में 800 से ज्यादा मवेशी बह गए, जो मवेशी बचे हैं वे अब चारा के अभाव में मरने के कगार पर हैं. धान का कटोरा के नाम से विख्यात पूर्वी चम्पारण में बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि अब लोग दाने-दाने को मोहताज दिख रहे हैं. जिला कृषि पदाधिकारी ओंकार नाथ सिंह के अनुसार, जिले के 27 प्रखण्डों में से 24 प्रखण्डों के सर्वे रिपोर्ट बताते हैं कि बाढ़ से लगभग 48 अरब कीमत की फसलों की क्षति हुई है. एक लाख 9 हजार हेक्टेयर में लगा खरीफ पूरी तरह बर्बाद हो गया, जिसमें धान, मक्का आदि शामिल हैं. सर्वाधिक क्षति रामगढ़वा, पताही और ढाका प्रखण्डों में हुई है. मत्स्य पालकों की तो बाढ़ ने कमर तोड़ कर रख दी है. तालाब, पईन, पोखरा के भर जाने से उनमें पाली गईं करोड़ों की मछलियां निकल गईं. जिले के नदियों के 6 तटबंध पूरी तरह से टूट गए, बूढ़ी गंडक का बायां तटबंध भी टूटने के कगार पर था, जिसे ग्रामीणों ने अपनी कोशिशों से बचा लिया. सबसे दर्दनाक घटना गुरहनवा स्टेशन के पास महंगुआ गांव में घटी. वहां मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले तीन सहोदर भाई विजय गुप्ता, लालबाबू गुप्ता और मुकेश गुप्ता पानी की तेज धार में बह गए. दो दिन बाद उनके शव मिले. जिले के 27 प्रखण्डों की 280 सड़कें पूरी तरह टूट गई हैं. रक्सौल-पीपरा कोठी राजमार्ग ने गड्ढे और तालाब का शक्ल ले लिया है. मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज और रक्सौल-दरभंगा रेल खण्ड पर परिचालन तो बाढ़ के आते ही बंद हो गया था. लेकिन बाढ़ ने जिस तरह से रेल की पटरियों और पुलों को नुकसान पहुंचाया, उसके कारण अब भी (खबर लिखे जाने तक) मुजफ्फरपुर से गोरखपुर तक या गोरखपुर होकर दिल्ली जाने वाली ट्रेनें उस रूट से नहीं चल पा रही हैं.

राहत और बचाव कार्य में लगी सेना

बाढ़ की विभिषिका का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चम्पारण के इतिहास में पहली बार राहत और बचाव कार्य के लिए एक साथ जल, थल और वायु सेना को लगाना पड़ा. राहत और बचाव कार्यों में गति लाने के लिए बिहार सरकार ने सूचना और जनसम्पर्क विभाग के प्रधान सचिव अनुपम कुमार को विशेष जिलाधिकारी बना कर भेजा. पूरा जिला 10 दिनों तक एनडीआरएफ की टीम और सेना के हवाले रहा. राहत एवं बचाव कार्यों में सेना के 2 बटालियन, 2 हेलिकॉप्टर और एनडीआरएफ के 300 जवानों को लगाया गया था. ये सभी जवान 227 नावों और 24 मोटर वोट के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने के काम में लगे रहे. पानी में फंसे लोगों तक हेलिकॉप्टर के द्वारा खाने का पैकेट पहुंचाया गया. 8 दिनों में दोनों हेलिकॉप्टरों ने 48 उड़ानें भरीं. जिलाधिकारी रमण कुमार के अनुसार, हेलिकॉप्टरों के माध्यम से पौने दो लाख लोगों तक सूखा राशन पहुंचाया गया. जिले में सरकारी सहायता से 303 स्थानों पर कम्यूनिटि किचेन चलाया गया. तकरीबन 50 हजार बाढ़ प्रभावित लोग गांव घर छोड़कर ऊंचे स्थलों, एनएच और बांधों पर शरण लिए थे. मोतिहारी के लुम्बिनी भवन में सरकारी कर्मियों के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सैकड़ो लोगों ने भी सूखा राहत सामग्री की पैकेजिंग का काम किया.

राहत कार्य में जुटे केन्द्रीय कृषि मंत्री व अन्य जनप्रतिनिधि

केन्द्रीय कृषि मंत्री सह स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर स्थिति की समीक्षा की और खुद भी राहत कार्यों में जुटे रहे. श्री सिंह ने भाजपा की ओर से दर्जनों स्थलों पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था कराई और जहां लोग फंसे हुए थे, वहां तक भी राहत सामग्री और खाना पहुंचवाया. इनके साथ स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार भी क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगे रहे. कमोबेश सभी जनप्रतिनिधियों ने आपदा के समय संवेदना दिखाते हुए राहत कार्यों में सहयोग किया.

स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी दिखाई मानवीय संवेदना

स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी आपदा के समय सराहनीय कार्य किया. राधा कृष्ण सेवा संस्थान के अध्यक्ष शंभुनाथ सिकारीया ने जिलाधिकारी रमण कुमार और विशेष जिलाधिकारी अनुपम कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक लाख का चेक दिया. स्वयंसेवी संस्था उपकृति द्वारा एक सप्ताह तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ पीडितों के लिए खाने का पैकेट उपलब्ध कराया गया. वहीं विभिन्न स्थलों पर चिकित्सा शिविर का आयोजन कर दवाएं दी गईं. रोटरी क्लब के सचिव अधिवक्ता राकेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में राहत सामग्री का वितरण किया गया. जबकि रेड क्रास, मारवाड़ी युवा मंच सहित दर्जनों संस्थाओं ने आगे बढ़कर बाढ़ पीडितों तक राहत सामग्री पहुंचाई.

शहर में भी तबाही

बाढ़ से मोतिहारी शहर में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया. शहर के कई मुहल्लों में कमर तक पानी भर गया. लोग घरों को छोड़ कर अन्यत्र जाने को मजबूर हो गए. नकछेद टोला, राधा नगर, भवानीपुर जीरात, चांदमारी, आजाद नगर, अम्बिका नगर सहित कई मुहल्ले डूब गए. गोपालपुर पश्चिमी में एक पक्का मकान पानी में समा गया, जबकि कई धर क्षतिग्रस्त हो गए. नगर परिषद् द्वारा भी राहत कार्य चलाया गया.

नेपाल के चितवन पार्क के जानवर भी बाढ़ में बहे

भारत की सीमा से लगे नेपाल के नेशनल पार्क के जानवर भी बाढ़ की विभिषिका से नहीं बच पाए. चितवन नेशनल पार्क के सूचना पदाधिकारी नरेन्द्र आर्याल के अनुसार, बाघ, गेंडा, हिरण सहित कई अन्य जानवर बाढ़ की धारा में बहने लगे थे. आठ गेंडा और दर्जनों हिरण बाढ़ में बहकर बिहार की सीमा में चले गए, जिसे बाद में पूर्वी चम्पारण के जिला प्रशासन ने नेपाल को सुपूर्द कर दिया. अरेराज के अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि बाढ़ में बहकर आए 15 हिरणों को ग्रामीणों के सहयोग से पकड़कर नेपाल को सौंप दिया गया. वाल्मिकीनगर के वाल्मिकी बाघ अभ्यारण्य और नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के पदाधिकारी अभी भी बाढ़ में बहे कई वन्य प्राणियों की खोज में लगे हैं. पश्चिमी चम्पारण के वाल्मिकी बाघ अभ्यारण्य के पदाधिकारी हाथी पर चढ़ कर बाघों की तलाश कर रहे हैं, ताकि वे कहीं बाढ़ में बह कर रिहायसी ईलाकों में न चले गए हों.

घड़ियालों का खतरा गहराया

नेपाल के चितवन पार्क के पास बड़े घड़ियालों का एक बड़ा आश्रय स्थल है. वे घड़ियाल भी बाढ़ के पानी में बहकर रिहायसी इलाकों में आ गए हैं. वहीं वाल्मिकीनगर के वीटीआर के पास गंडक नदी के संगम स्थल पर छोटे घड़ियाल रहते हैं. यह स्थान घड़ियालों का प्रजनन स्थल भी कहा जाता है, जहां बड़ी संख्या में घड़ियाल अण्डा देती हैं. बाढ़ के कारण इन घड़ियालों का रिहायसी इलाकों में प्रवेश पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज, छपरा और वैशाली जिलों के लिए खतरे का संकेत है. गौरतलब है कि एक माह पूर्व ही बगहा और अरेराज के संग्रामपुर ईलाके में एक घड़ियाल दो लोगों को अपना शिकार बना चुका है.

मुख्यमंत्री ने लिया बाढ़ और राहत का जायजा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ ग्रस्त पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण का दौरा किया और राहत कार्यों का निरीक्षण कर पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने मोतिहारी में विशेष डीएम अनुपम कुमार से राहत कार्यों की जानकारी ली, वहीं बेतिया में भी राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की. सुगौली के एक कम्यूनिटी किचेन में उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और उनकी समस्याएं सुनीं. सुगौली के लोगों ने शिकायत की कि चीनी मील द्वारा गंदा पानी छोड़ने के कारण बदबू और महामारी फैल रही है. इसपर उन्होंने डीएम रमण कुमार निर्देश दिया कि चीनी मील से गंदे पानी की निकासी पर तत्काल रोक लगाते हुए जांच कर कार्रवाई करें.

बाढ़ के बाद का संकट

बाढ़ के बाद महामारी का संकट बढ़ गया है. चारो तरफ फैला पानी अब सड़ने लगा है. शहर के बाहरी इलाके में नगर परिषद् द्वारा फेंका गया कचरा अब महामारी का कारण बनता जा रहा है. हजारों लोगों के घर ध्वस्त हो गए हैं. रोजी-रोटी की समस्या अलग है. ऐसे में सरकार और प्रशासन के लिए इन संकटों से उबरना सबसे बड़ी चुनौती होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

A House Of Badshah Agarbatti

Badshah
Agarbatti Palace
fragrance that defines you
BIHAR'S 1ST AGARBATTI SHOWROOM
एक बार अवश्य पधारें...
₹ 500 या अधिक की खरीद पर निश्चित उपहार और साथ में LUCKY DRAW COUPON भी
खुशबु नहीं जादू है।®
BADSHAH INDUSTRIES
"धरती पर स्वर्ग"®
बादशाह
धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री
Add(I) - Panjabi Coloney, Opp. Badshah Industries, Chitkohra, Patna, Contact : 88 73 776766
Add(II) - Ashoka Tower, Near Lalita Hotel, East Boring-Canal Road, Patna, Contact : 73 19 777609

लोजपा की सक्रियता से एनडीए घटकों में बेचैनी

मगध के पांच जिलों गया, नवादा, औरगाबांद, जहानाबाद और अरवल में लोजपा का संगठन प्रखंड स्तर पर है. यही कारण है कि इसकी गतिविधियां भी किसी राष्ट्रीय दल से कम नजर नहीं आती हैं. रालोसपा मगध के पांच तो हम सात सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी अपनी स्थिति देख चुकी हैं. इन दलों के शायद ही कोई पूर्व प्रत्याशी हों, जो अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं. एक तरह से एनडीए के घटक दलों के लिए इस मामले में लोजपा बड़ी चुनौती दे रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

चुनावी राजनीति के हिसाब से मगध में लोक जनशक्ति पार्टी का चाहे जो हाल हो, लेकिन संगठन के स्तर पर देखें, तो एनडीए के घटक दलों में जदयू को छोड़कर इसकी स्थिति सबसे मजबूत है. ये जानते हुए कि एनडीए का सहयोगी दल होने के कारण लोजपा को बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत अधिक सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है, फिर भी संगठन स्तर पर इसके नेता और कार्यक्रर्ता कार्यक्रम-बैठक करते रहते हैं. साथ ही तमाम नेता समय-समय पर जनसम्पर्क करतते रहते हैं. पिछला चुनाव नहीं जीतने वाले पूर्व प्रत्याशी भी क्षेत्र और वहां के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं.

मगध के पांच जिलों गया, नवादा, औरगाबांद, जहानाबाद और अरवल में लोजपा का संगठन प्रखंड स्तर पर है. यही कारण है कि इसकी गतिविधियां भी किसी राष्ट्रीय दल से कम नजर नहीं आती हैं. रालोसपा मगध के पांच तो हम सात सीटों पर चुनाव लडकर अपनी अपनी स्थिती देख चुके है. इन दलों के शायद ही कोई पूर्व प्रत्याशी हों, जो अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होते है. एक तरह से एनडीए के घटक दलों के लिए इस मामले में लोजपा बड़ी चुनौती दे रहा है. जमीनी स्तर पर लोगों से लोजपा का जुड़ाव अन्य दलों को साफ संदेश दे रहा है कि जातीय गणित पर बिहार में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी, तभी सफलता मिलेगी. लोजपा पर भी दलित जाति के वोट बैक की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है. लेकिन बाद के दिनों में लोजपा ने मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार समेत अन्य महादलित, पिछडी जातियों को अपने वोट बैक से जोड़ा. जिसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला. लोजपा की दलित-महादलित समर्थक वाली पहचान अब बीते दिनों की बात हो चुकी है. आज अगड़ी जातियों के लोग भी लोजपा से जुड़े हैं.

मगध में लोजपा के संगठन के मजबूत होने से सबसे अधिक परेशानी 'हम' को है, क्योंकि दलित-महादलित ही दोनों दलों के वोट बैंक का बेस हैं. यह अलग बात है कि एनडीए का सहयोगी दल होने के कारण भाजपा और अन्य दलों का वोट बैंक भी इनके साथ जुड़ जाता है. 'हम' के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुद मगध के ही निवासी हैं और ये मगध के ही विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों बोधगया, बाराचट्टी, फतेहपुर (अब विघटित) और मखदुमपुर से विधायक रह चुके हैं. ये फिलहाल इमामगंज जिले के विधानसभा (सुरक्षित) से विधायक हैं. मगध में इनकी जाति भुईयां (मांझी) की अच्छी खासी संख्या है. 1999 से अबतक गया लोकसभा क्षेत्र से लगातार मांझी जाति के ही सांसद जीतते रहे हैं. यही कारण है कि अपनी पार्टी 'हम' के लिए जीतन राम मांझी मगध को मजबूत आधार मानते हैं.

2015 के विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी 'हम' को यहां 7 सीटें मिली थीं. जीतन राम मांझी खुद दो विधानसभा क्षेत्रों मखदुमपुर और इमामगंज से चुनाव लड़े. वहीं इनके बेटे संतोष सुमन औरंगाबाद के कुटुम्बा सुरक्षित क्षेत्र से प्रत्याशी थे. संतोष सुमन तो चुनाव हारे ही, मांझी को भी एक जगह से हार का सामना करना पड़ा. वहीं इनके बाकी चार उम्मीदवार भी नहीं जीत सके. मगध के तीन विधानसभा क्षेत्रों अतरी, बाराचट्टी और रफीगंज से चुनाव लड़ने वाले लोजपा उम्मीदवारों को भी सफलता नहीं मिली. बावजूद इसके, लोजपा की सक्रियता मगध के पांचों जिलों में है. इसके सभी जिलाध्यक्ष हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते है. युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और अतरी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले अरविन्द कुमार सिंह खुद सक्रिय रहते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

गया

21 गोत्रों की सात पीढ़ियों का गया में होता है पिंडदान

पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए उमड़े लोग

सुनील सौरभ

दुनियाभर के हिन्दू धर्मावलम्बियों की श्रद्धा के बड़े केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध गया में इन दिनों पितृपक्ष मेला लगा है. 15 दिन के इस मेले में हिन्दू धर्मावलम्बी अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान करने लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं. बढ़ती आबादी के साथ इस मेले में आनेवाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. फलत: राज्य सरकार, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इस मेले की व्यवस्था की जाती है. राजकीय मेला घोषित हो जाने के बाद से राजस्व विभाग भी इस मेले से जुड गया है. इन विभागों के अलावा गया नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अलावा अन्य सभी सरकारी तंत्र भी इस मेले की व्यवस्था में लगे रहते है. सबसे बड़ी जिम्मेवारी पुलिस विभाग की होती है. इस मेले में आसपास के जिले से भी सुरक्षाकर्मियों को लाकर ड्यूटी पर लगाया गया है. गया के पितृपक्ष मेले के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है. आवासन के साथ-साथ तीर्थयात्रियों को पानी, बिजली और यातायात की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. मेला क्षेत्र में जगह-जगह स्वाथ्य शिविर, सुरक्षा शिविर की व्यवस्था है. सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की ओर से विभिन्न तरह का सहायता शिविर भी लगाया गया है. बावजूद इसके पिंडदान करने आए तीर्थयात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन की कार्यनीति को लेकर लोगों में शिकायत है. शिविरों में तैनात सरकारी कर्मी श्रद्धालुओं को गया वाले पंडा के पते और पिंडस्थलों तक जाने आदि की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं. पंडों की तरफ से भी शिकायतें आ रही हैं कि बिना उनकी जानकारी के ही सरकारी कर्मियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है. इनका कहना है कि मेला प्रबंधन पूरी तरह से निष्क्रिय है. न तो हमारा सुझाव लिया जा रहा है और न ही कोई जानकारी दी जा रही है.

हालांकि इन सब शिकायतों और परेशानियों के बावजूद, पिण्डदान करने आए लोगों की श्रद्धाभक्ति में कोई कमी नहीं दिख रही है. पुनपुन घाट से ही मेले की रौनक शुरू हो जाती है. गौरतलब है कि मेले का प्रारंभ पटना जिला स्थित पुनपुन घाट में पूजा-पाठ से होता है. गया क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व पुनपुन नदी के तट पर पिण्डदान कर लेना आवश्यक बताया गया है. पुनपुन को गया क्षेत्र का द्वारा भी कहा जाता है.

पहले पंडा वहां जाकर पूजा कराते थे, किन्तु अब घर बैठे ही रस्म पूरा करा लिया जाता है. पहले पिण्डदान करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही था, लेकिन 1985 में मिथिला के पंडितों ने स्त्रियों को भी पिण्डदान का अधिकार प्रदान कर दिया. फलत: अब स्त्रियां भी पिण्डदान करती हैं. पिण्डदान करने वाले हर स्त्री-पुरुष पहले विष्णुपद 'फल्गु' के तट पर जाते हैं और फिर मुंडन कराकर फल्गु में स्नान करने के बाद अपने पीढ़ीगत गया वाले पंडों के माध्यम से तर्पण का कार्य करते हैं. किसी भी श्राद्धकर्ता को कम-से-कम विष्णुपद, फल्गु और अक्षवट में पिण्डदान करना अनिवार्य है. फल्गु तट पर सीताकुंड है, जहां बालू का पिंड देने का विधान है.

गया में होने वाले पिंडदान की महता की बात करें, तो ये परम्परा वैदिक काल से चली आ रही है. गया की पहचान तो प्राचीन काल से ही धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परा के पितृतीर्थ के रूप में है. वेदों में भी गया का जिक्र मिलता है. गया को तीर्थों का प्राण कहा गया है. अंतिम मोक्ष की प्राप्ति का स्थान गया को ही माना गया है. कहा जाता है कि जो पिता की मृत्यु के बाद क्षय तिथि को सत्पति एवं सच्चरित्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर विधिपूर्वक गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र कहलाने के योग्य होता है. भारतीय ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र के अनुसार, आश्विन के कृष्ण पक्ष का सम्बन्ध पितरों से है और शुक्ल पक्ष का संबंध देवताओं से है. यह माना जाता है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में (सूर्य के कन्या राशि पर स्थित होने पर) यमराज पितरों को यमालय से मुक्त कर देते हैं और वे मनुष्य लोक में आकर अपनी संततितियों से पिंडदान आदि की आशा करते हैं. यदि इनके पुत्रगण इन्हें इनकी तिथियों पर पिण्डदानादि करते हैं, तो वे प्रसन्न होते हैं और इन्हें अभ्युदय का आशीर्वाद देते हैं. इसके विपरीत (पिण्डादानादि न करने पर) वे पुत्रों को शाप भी देते हैं. यही कारण है कि पितृपक्ष में पितृजनो की प्रसन्नता के लिए प्रतिपदा से अमावस्या तक प्रतिदिन तर्पणादि किया जाता है और अपने पितरों की निधन तिथि पर विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म किया जात है.
श्राद्ध का यह कृत्य मात्र पितरों के प्रसाद के लिए ही नहीं किया जाता है, अपितु इससे समस्त प्राणियों को भी तृप्ति होती है.

ऐसे तो पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए गया में सालों भर पिण्डदान होता है. पिण्डदान के लिए लोग यहां देश-विदेश से आते रहते हैं. लेकिन आश्विन महीने के कृष्णपक्ष में यहां पिंडदान का विशेष महत्व है. इसे पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में सारे पितर गया में आते हैं और अपनी संततियों से पिण्डदान की अपेक्षा करते हैं. यही कारण है कि पन्द्रह दिनों तक लगने वाले पितृपक्ष मेले में देश के कोने-कोने से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी हिन्दू धर्मावलम्बी अपने पितरों को पिण्डदान-तर्पण करने गया आते हैं. खासकर नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, फिजी, गुयाना, तिब्बत, म्यांमार, भूटान आदि देशों के श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक जमा होती है. ■

दाँतों के टेढ़े-मेढ़ेपन का इलाज

ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
आर्या डेन्टल क्लीनिक पटेल चौक, हसपुरा
डॉ. अश्वनी आर्या
(बी.डी.एस.) पटेल चौक हसनपुरा, औरंगाबाद
डॉ अश्वनी आर्या ने अपने निजि क्लीनिक हसपुरा औरंगबाद पटेल चौक से बात करते हुए बताया कि बच्चों में दाँतों के टेढ़ेमेढ़ेपन का कारण उनकी इलाज की प्रति मां बाप की उदासीनता है। मूलतः बच्चों का इलाज 6 साल बाद ही शुरू कर देना चाहिए साथ ही उन्होंने बताया कि जिन बच्चों के दांत टेढ़े-मेढ़े होते हैं उनमें कुछ में तो हेरेडेटरी होती है अर्थात उनके दादा-दादी, माता पिता से जो यानि स्केलटन हड्डी की बनावट से होती है। इसके लिए जरूरी है कि 6 साल से 11 साल के अन्दर उनका इलाज तरीके से किया जाय जिसमें कि यदि ग्रोथ के हिसाब से इलाज किया जाता है। 8से 12 साल तक के समय को मिक्स डेन्टीशियन पिरियड कहा जाता है इस समय दांत टूटते और जन्म लेते हैं। इसलिए इस समय भी खास ध्यान देने की जरूरत हैं। एक प्रश्न के जबाव में उन्होंने बताया कि बच्चों के तुतलाट का भी इलाज दांतों के डॉक्टर के पास होता है। इलाज के बाद भी रखें इन बातों का ख्याल 1) टेढ़े-मेढ़े दांतों के ट्रीटमेंट के बाद उसे ऐसे ही न छोड़ दें क्योंकि इसके बाद उनके सरकने और टेढ़े होने की संभावना बनी रहती है इसलिए समय समय पर डाक्टर से सलाह लेते रहें। 2) बच्चे को हर छःमहीने के बाद डैंटिस्ट के पास लेकर जाएं ताकि उनकी आदतों जैसे कि अंगूठा चूसना, जींभ से बार-बार अपने ऊपरी दांतों को धकेलना, दांतों से होंठ अथवा गाल काटते रहना आदि आदतें जो दांतों को टेढ़ा-मेढा करती हैं,को हटाया जा सकें। 3) अगर किसी बच्चे में मुंह से सांस लेने की आदत है तो भी इस आदत को दूर किया जाना चाहिए क्योंकि इस आदत की वजह से ऊपर वाले आगे के दांत बाहर की तरफ आने लगते हैं। 4) अगर आपके बच्चे के दूध वाले दांत नहीं गिरे लेकिन पास की गलत जगह पर पक्के दांत निकलने लगे हैं तो बच्चे को डैंटिस्ट के पास ले जाकर दूध के दांत निकलवाएं नहीं तो पक्के दांत वहीं फिक्स हो जाएंगे। 5) अगर आप सोचते हैं कि डैंटिस्ट के पास जाकर टेढ़े-मेढ़े दांतों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। यह बिल्कुल गलत हैं। आप नियमित रूप से हर छःमहीने बाद बच्चों को डैंटिस्ट के पास जाकर दांत चौक करवाते रहें। अगर कुछ प्राबल्म होगी तो वह साथ-साथ ठीक होती रहेगी। ■ भारती
ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

CRM
TMT BAR

भूकम्प रोधी
जंग रोधी
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

स्वार्थसिद्धि से संकल्पसिद्धि की ओर

अनंत विजय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजनीति में भी अपने गैरपारंपरिक तौर तरीकों से चौंकाते रहे हैं. राजनीति से इतर भी जब वो बातें करते हैं, तो उनकी सोच लोगों को उन प्रदेशों तक में जाती है, जहां जाने में उनके पूर्ववर्ती कतराते रहे हैं. किसी का स्वागत करने के लिए फूल की जगह किताब की पैरोकारी कर प्रधानमंत्री ने सभी पुस्तकप्रेमियों का दिल जीत लिया. अब उनकी इस सलाह पर अमल भी होना शुरू हो गया है, यह देखना प्रीतिकर है कि गुलदस्तों की बजाए नेता अब पुस्तकों से स्वागत कर रहे हैं. इसी तरह से कुछ साल पहले एक पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि हर घर में पूजाघर की तरह एक पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए. उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि घर बनाते समय आर्किटेक्ट से नक्शे में पुस्तकालय के प्रावधान के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए. अभी हाल ही में उन्होंने मन की बात में भी कुछ ऐसी ही बातें की, जो उनकी दीर्घकालीन सोच को एक बार फिर से देश के सामने रख रही हैं. अभी हाल में उन्होंने 1942 को संकल्प का साल मानते हुए आजादी के पचहत्तरवें साल, 2022 को सिद्धि का वर्ष करार दिया यानि, संकल्प से सिद्धि का कालखंड. जब प्रधानमंत्री संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं और समाज के हर तबके से इसको अपनाने की अपील करते हैं, तब उनकी यह अपील समाज के साथ-साथ साहित्य और संस्कृति की देहरी पर भी दस्तक देती है. हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आजादी के पहले रचनाधर्मियों के क्या दायित्व थे, आजादी मिलने के बाद उनके दायित्व क्या हुए और अब आजादी के सत्तर साल बाद रचनाकारों के दायित्व और उनकी प्राथमिकताएं कितनी बदलीं.

अगर हम 1942 या उसके कुछ साल पहले के बारे में विचार करें, तो उस वक्त के साहित्यकारों के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था- आजादी. उनकी रचनाओं के केंद्र में लोक की यही चिंता प्रतिबिंबित होती थी, लोक की यही आकांक्षा भी रहती थी. इस चिंता का प्रकटीकरण उनकी रचनाओं में होता था. 1947 में देश को आजादी मिली, हमारी आकांक्षाएं परवान चढ़ने लगीं, उम्मीदें सातवें आसमान पर जा पहुंचीं. आजादी के बाद के करीब दो दशक तक पूरा देश स्वतंत्रता के रोमांटिसिज्म में रहा. उसके बाद का काल मोहभंग का काल रहा. सत्तर के दशक से तो हमारे देश की बहुलतावादी संस्कृति, जिसे अनेकता में एकता की स्वीकृति मिली हुई थी, उसका निषेध होना शुरू हो गया. एक खास विचारधारा, जो अबतक कमजोर अवस्था में थी, उसको बल मिलना शुरू हो गया. भारतीय संस्कृति, साहित्य और ज्ञान परंपरा के पास जो विश्व दृष्टि थी, उसको मार्क्सवाद के प्रचार-प्रसार के जरिए विस्थापित करने की जोरदार कोशिशें शुरू हुईं. भौतिकता-आधुनिकता और धार्मिकता-आध्यात्मिकता वाली ज्ञान परंपरा को विस्थापित कर आयातित विचार के आधार पर साहित्य रचा जाने लगा. उस दौर में ही रामधारी सिंह दिनकर को कहना पड़ा- 'जातियों का सांस्कृतिक विनाश तब होता है, जब वे अपनी परंपराओं को भूलकर दूसरों की परंपराओं का अनुकरण करने लगती हैं, ...जब वे मन ही मन अपने को हीन और दूसरों को श्रेष्ठ मानकर मानसिक दासता को स्वेच्छया स्वीकार कर लेती हैं. पारस्परिक आदान-प्रदान तो संस्कृतियों का स्वाभाविक धर्म है, किन्तु जहां प्रवाह एकतरफा हो, वहां यही कहा जाएगा कि एक जाति दूसरी जाति की सांस्कृतिक दासी हो रही है. सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है, जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव मानने लगती है. वह गुलामी की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है.' दिनकर को ये इस वजह से कहना पड़ा, क्योंकि हम भाषा और रचनात्मक दोनों स्तर पर अपनी परंपरा को भुलाकर दूसरे देश या कहें कि दूसरी विचारधारा की मानसिक गुलामी के लिए अपनी एक पूरी पीढ़ी को तैयार करने में लगे थे.

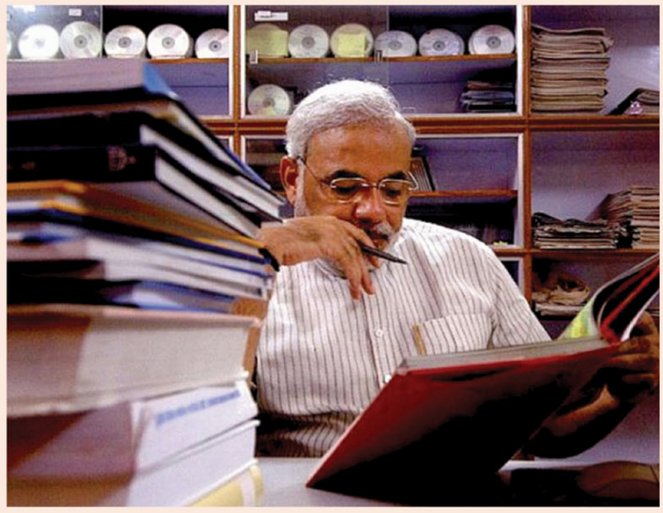

साहित्य में आधुनिकता के नाम पर यह दलील दी जाने लगी कि भारतीय साहित्य आधुनिकता से कोसों दूर है. भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लेखकों को दकियानूसी और पिछड़ा कहकर अपमानित किया जाने लगा. लेखन के केंद्र में नैतिकता, अध्यात्म और सौन्दर्यबोध को निगेट करने की संगठित कोशिशें होने लगी. अदृश्य के प्रति आस्था और परलोक के अस्तित्व में भारतीय जनमानस के विश्वास को खंडित करने जैसी रचनाएं लिखी जाने लगी. इस खंडनवादी लेखन को वैज्ञानिकता का आधार भी प्रदान किया गया, लेकिन ऐसा करनेवाले यह भूल गए कि भारत में लोक की आस्था को खंडित करना आसान नहीं है. हमारे देश में जो सृष्टिबोध है, उसका आधार विश्वास है. भारत की संस्कृति पुरातन संस्कृति है, जहां लोकजीवन और लोक यहां की संस्कृति का आधार रहे हैं. लोक को भी नकारने की कोशिशें हुईं. लोकगीतों को या जो भारतीय ज्ञान परंपरा कंठों में निवास करती थी, उसको कपोल कल्पना कहा जाने लगा. ईश्वर को नकारने की कोशिशें हुईं. नीत्से की उस प्रसिद्ध घोषणा का सहारा लिया गया, जिसमें उसने ईश्वर की मृत्यु की बात की थी. ऐसा प्रचारित करनेवाले लोग लगातार इस बात को छिपाते रहे कि नीत्शे ने इस घोषणा के साथ और क्या कहा था. नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर की मृत्यु बहुत बड़ी घटना है. इस घटना की बराबरी मनुष्य जाति में तभी संभव है, जब एक-एक शख्स स्वयं ईश्वर बन जाए.

सत्तर के दशक में जो हुआ उसपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. इंदिरा गांधी के पहले जवाहरलाल नेहरू के दौर में कांग्रेस एक विचारधारा के साथ चल रही थी और उनसे नेताओं के वैचारिक सरोकार भी होते थे. 1971 में इंदिरा गांधी के मजबूत होने के बाद कांग्रेस ने वैचारिकता का दामन छोड़ दिया और उसको वाम दलों को आउटसोर्स कर दिया. इसका फायदा भी इंदिरा गांधी को हुआ, जब इमरजेंसी के दौर में प्रगतिशील लेखक संघ ने उनका समर्थन किया और दिल्ली में भीष्म साहनी की अगुवाई में समर्थन का प्रस्ताव पास किया गया.

उधर हिंदी साहित्य अपनी पारंपरिक चेतना से प्रेरित होने की बजाए रूसी चेतना से प्रेरित होने लगी. मार्क्सवाद में जिस समाज की कल्पना की गई थी, उसको हिंदी साहित्य में साकार किया जाने लगा. अंतराष्ट्रीय अवधारणा के नाम पर हमारी राष्ट्रीय अवधारणा को नेपथ्य में डाल दिया गया. अंतराष्ट्रीयता के नाम पर मार्क्सवाद की अनुचित उपासना ने हमारी राष्ट्रीय चेतना का नुकसान करना प्रारंभ कर दिया था. अज्ञेय या निर्मल वर्मा जैसे लेखक या विद्यानिवास मिश्र या कुबेरनाथ राय जैसे निबंधकारों को साहित्य के केंद्र में आने से रोकने की कोशिश होती रही. दिनकर को उनके जीवनकाल में ही साहित्य की परिधि पार धकेलने का प्रयास विदेशी विचारधारा के प्रभाव में काम कर रहे आलोचकों और लेखकों ने संगठित रूप से किया. उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रचनाओं का मूल्यांकन ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखा गया. चूंकि दिनकर की रचनाएं इतनी मजबूत थीं कि तमाम प्रयासों के बावजूद उनको जनता से दूर नहीं किया जा सका. निराला के उन लेखों को कालांतर में प्रचारित-प्रसारित नहीं होने दिया गया, जिसमें उन्होंने हिन्दुत्व और हिंदू देवी-देवताओं के चरित्रों पर लिखा था. ऐसे दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं. यहां तक कि अशोक वाजपेयी को भी कलावादी कहकर उन्हें साहित्य की कथित मुख्यधारा से अलग करने का प्रयास हुआ. लेकिन अशोक वाजपेयी की सांगठनिक क्षमता, सत्ता से उनकी नजदीकी और बाद में उनकी आर्थिक संपन्नता की वजह से उनको बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका.

सत्तर के दशक में जो हुआ उसपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. इंदिरा गांधी के पहले जवाहरलाल नेहरू के दौर में कांग्रेस एक विचारधारा के साथ चल रही थी और उनसे नेताओं के वैचारिक सरोकार भी होते थे. 1971 में इंदिरा गांधी के मजबूत होने के बाद कांग्रेस ने वैचारिकता का दामन छोड़ दिया और उसको वाम दलों को आउटसोर्स कर दिया. इसका फायदा भी इंदिरा गांधी को हुआ, जब इमरजेंसी के दौर में प्रगतिशील लेखक संघ ने उनका समर्थन किया और दिल्ली में भीष्म साहनी की अगुवाई में समर्थन का प्रस्ताव पास किया गया.

यह तो साफ है कि जो संकल्प भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त साहित्य में चलकर आया था, वो सिद्धि तक पहुंचने के रास्ते से भटक गया था. लोक और जन की बात करने वाले लोक और जन से ही दूर होते चले गए. अपनी स्वार्थसिद्धि के चक्कर में संकल्प सिद्धि बिसरता चला गया, रचनाओं में भी और व्यवहार में भी. साहित्य को इसका बड़ा नुकसान हुआ, साहित्य की विविधता खत्म हो गई, चिंतन पद्धति का विकास अवरुद्ध हो गया, साहित्येतर विधाएं मृतप्राय होती चली गईं. 2022 तक का वक्त है, अगर हम अपनी आजादी के पचहत्तरवें साल में भी साहित्य को उसकी विविधता लौटा सकें, लोक को उसके केंद्र में स्थापित कर सकें, कंठों के माध्यम से जीवित साहित्य को जिंदा कर सकें, तो हम संकल्प सिद्धि के छूटे हुए डोर को पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं. ■

anant.ibn@gmail.com

ललित कला अकादमी...

आकर्षण का केंद्र रहीं कैदियों की कलाकृतियां

चौथी दुनिया ब्यूरो

तिहाड़ और देश की अन्य जेलों के कैदियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की ललित कला अकादमी में हुई प्रदर्शनी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया. 26 अगस्त को दिल्ली के उपराज्पाल अनिल बैजल ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. उद्घाटन में कला, संस्कृति और भाषा विभाग मंत्रालय, दिल्ली सरकार के सचिव, वी अब्राहम, तिहाड़ के जेल महानिदेशक सुधीर यादव, पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार राम वी सुतार, पद्म श्री से सम्मानित कलाकार बीमन बी दास, और जानी-मानी कला-हस्तियां और कलाप्रेमी उपस्थित रहे. वहां ललित कला अकादमी के प्रशासक सीएस कृष्ण सेट्टी और प्रदर्शनी के संयोजक और प्रसिद्ध कलाकार वीर मुंशी की भी उपस्थिति रही. 31 अगस्त तक चली इस प्रदर्शनी में, तिहाड़ और देश की अन्य जेलों से आए लगभग 80 कैदियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों में से क्यूरेटर वीर मुंशी द्वारा चुनी गई कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया था.

इस प्रदर्शनी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ललित कला अकादमी, तिहाड़ जेल प्रशासन, साहित्य कला परिषद, कैदियों को ट्रेनिंग देने वाले कलाकारों और प्रतिभागी कैदियों की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि कैदियों के प्रदर्शित आर्टवर्क्स से मैं बेहद प्रभावित हुआ. जिस जेनरेशन में मैंने कार्य किया, उस समय की तुलना में आज कारागार का अर्थ पूरा बदल चुका है. इसने खुद को क़ैदियों से भरी एक कुंठित जगह से एक ऐसे स्थान के रूप में रूपांतरित किया है, जो कैदियों को पुनरुत्थान और पुनर्वास का अवसर भी देता है. ललित कला अकादमी को इस प्रदर्शनी के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन करना किसी भी गैलरी के लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि जेलों में क़ैद लगभग 75 प्रतिशत क़ैदी अंडरट्रायल हैं और सज़ा पूरी करके निकलने के बाद ऐसे प्रयास उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में सहयोग करेंगे.

तिहाड़ के महानिदेशक (जेल) सुधीर यादव ने उन कैदियों को इस अवसर पर बधाई दिया, जिनकी कलाकृतियां प्रदर्शनी में लगी थीं. उन्होंने कहा इस प्रदर्शनी के माध्यम से कैदियों की अद्भुत प्रतिभाओं को लेकर उनके परिवारजनों और रिश्तेदारों में भी सार्थक संदेश जाएगा. उन्होंने कैदियों की कृतियां उनके परिवार जनों को भेंट करने की योजना का भी ज़िक्र किया. ललित कला अकादमी के प्रशासक सीएस कृष्ण सेट्टी ने कैदियों द्वारा बनाई गई प्रदर्शित कलाकृतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन कैदियों ने मंझे हुए पेशेवर कलाकारों के टक्कर का काम किया है जिससे उन्हें ताजुब के साथ बेहद ख़ुशी भी है. उन्होंने कहा कि श्री सुधीर यादव जी ने इस प्रयास के माध्यम से एक इतिहास रच दिया है और अकादमी इस तिहाड़ कलाभियान का हिस्सा बनके गौरान्वित महसूस कर रही है. प्रदर्शनी के क्यूरेटर और प्रसिद्ध कलाकार वीर मुंशी का कहना था कि तिहाड़ जेल में इन प्रतिभागी कैदियों के साथ काम करना एक जीवन बदलने वाला अनुभव रहा. उन्होंने दूसरे कलाकारों को भी जेलों में जाकर कैदियों से मिलने और उन्हें कला की महत्ता समझाने का सुझाव दिया जिससे क़ैदियों की जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आ सके. ■

feedback@chauthiduniya.com

लेटलतीफ अधिकारियों की लें ख़बर

चौथी दुनिया ब्यूरो

अस्पतालों में डॉक्टरों या स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति से जुड़ी खबरें आए दिन देखने को मिलती हैं. साथ ही समय पर दफ्तर ना पहुंचना भी कई सरकारी अधिकारियों की आदत में शुमार होता है. इसका खामियाजा अस्पतालों के मरीजों और स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ता है. लोग इसके विरोध में आवाज भी उठाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे अधिकारियों या कर्मियों के खिलाफ ठोस सबूतों के अभाव में उनपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है. ऐसी स्थिति में आरटीआई का सहारा लिया जा सकता है. हम आपको उस आवेदन के प्रारूप के बारे में बता रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप दफ्तरों में समय पर नहीं आने वाले कर्मियों की कुंडली खंगाल सकते हैं और उनपर कार्रवाई के लिए दबाव बना सकते हैं.

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

मैं अपने गांव/कस्बे/शहर में स्थित ..... स्कूल/अस्पताल के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता/चाहती हूं:

1. उपरोक्त संस्थान में कुल कितने कर्मचारी हैं. इन सभी कर्मचारियों की एक सूची प्रदान करें, जिसमें इनके बारे में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई गई हो:
- नाम
- पद
- कार्य भार/ज़िम्मेदारी का विवरण
- वर्तमान कार्यालय में कब से कार्यरत हैं
- प्रतिदिन ड्यूटी पर आने व जाने का समय

2. उपरोक्त सभी कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की पिछले छह महीने की प्रति मुझे उपलब्ध कराएं.

3. अगर कोई कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचता है या बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो विभाग में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था है. कृपया इस सम्बन्ध में नियमों/दिशानिर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएं.

4. पिछले छह महीने में उपरोक्त में से कितने कर्मचारियों के खिलाफ देर से आने या अनुपस्थित रहने के मामले में उपरोक्त व्यवस्था के तहत क्या कार्रवाई हुई है, उसका पूरा विवरण व उस सम्बन्ध में पारित किए गए आदेशों/निर्देशों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.

5. कृपया उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा पिछले छह महीने में लिए कुल अवकाशों (साप्ताहिक अवकाश व अन्य कार्यालय अवकाश दिवसों को छोड़कर) का विवरण उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं..... है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं।

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

feedback@chauthiduniya.com

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:
rti@chauthiduniya.com

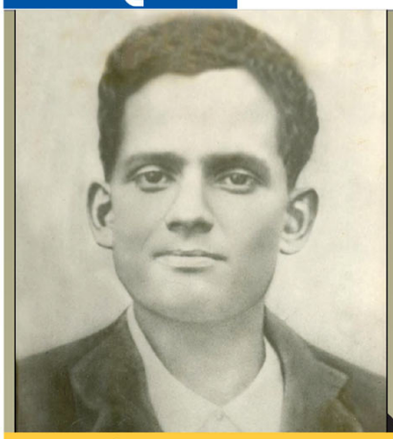

पुण्यतिथि विशेष

अन्याय के विरोध में जारी अनशन से शहीद होने वाला क्रांतिकारी जतींद्र नाथ दास

जन्मदिन- 27 अक्टूबर 1904
पुण्यतिथि- 13 सितम्बर 1929

चौथी दुनिया ब्यूरो

कहा जाता है, पेट की आग बड़े-बड़ों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है. लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक ऐसा भी क्रांतिकारी हुआ है, जिसने अपनी भूख को बगावत का हथियार बना लिया और अंतिम सांस तक डिगा नहीं. अदम्य साहस और देश के लिए मर मिटने वाले जोश-ओ-जुनून से भरे उस क्रांतिकारी का नाम था, जतींद्र नाथ दास. इन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है, वहीं इनके साथी इन्हें जतिन दा कहते थे. 63 दिनों के अनशन सत्याग्रह के बाद अपने जीवन के अंतिम समय में जतींद्र दास ने कहा था, 'गोली खाकर या फिर फांसी पर झूलकर मरना तो बहुत आसान है. जब अनशन करके धीरे-धीरे आदमी मरता है, तो उसके मनोबल का पता चलता है. अगर वो मन से कमजोर है, तो उससे ये कभी नहीं हो पाएगा.' स्वतंत्रता से पहले अनशन से शहीद होने वाले एकमात्र व्यक्ति जतिन दास हैं.

जतींद्र दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कलकत्ता में एक साधारण बंगाली परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम बंकिम बिहारी दास और माता का नाम सुहासिनी देवी था. जतींद्र नौ वर्ष के थे, तभी उनकी मां का स्वर्गवास हो गया. 16 वर्ष की उम्र में 1920 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की. उसके अगले साल 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन शुरू किया, तो जतींद्र उसमें शामिल हो गए. इसी दौरान विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देते हुए वे गिरफ़्तार कर लिए गए. उन्हें 6 महीने की सज़ा हुई. चौरी-चौरा की घटना के बाद जब गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन वापस लिया, तो जतींद्र बहुत निराश हुए. इसके बाद उन्होंने कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज में दाखिला लिया और फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी. एक युवक के माध्यम से जतींद्र प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के सम्पर्क में आए और क्रांतिकारी संस्था 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' के सदस्य बन गए. अपने सम्पर्कों, साहसपूर्ण कार्यों और क्रांतिकारी गतिविधियों से उन्होंने दल में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया. इस बीच जतींद्र दास ने बम बनाना भी सीख लिया था. 1925 में उन्हें 'दक्षिणेश्वर बम कांड' और 'काकोरी कांड' के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया. लेकिन सबूतों के अभाव में उनपर मुकदमा नहीं चल पाया और वे नज़रबंद कर लिए गए. वहां पर राजनीतिक कैदियों से हो रहे दुर्व्यवहार से उनका मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने जेल अधिकारियों से इसकी शिकायत की. लेकिन कोई सुनवाई न होने पर जतींद्र दास ने अनशन करने का फैसला किया. वे पूरे 20 दिनों तक अनशन करते रहे. भूख हड़ताल के कारण उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर 21वे दिन अंततः जेल अधीक्षक ने उन्हें रिहा कर दिया.

1928 के कोलकाता कांग्रेस के दौरान जतींद्र दास कांग्रेस सेवादल में नेताजी सुभाषचंद्र बोस के सहायक थे. वहीं उनकी मुलाकात सरदार भगत सिंह से हुई और उनके अनुरोध पर जतींद्र दास बम बनाने के लिए आगरा आए. 8 अप्रैल, 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केन्द्रीय असेम्बली पर जो बम फेंके, वे जतींद्र दास के द्वारा ही बनाए हुए थे. इस मामले में 14 जून, 1929 को जतींद्र गिरफ़्तार कर लिए गए और उनपर 'लाहौर षड्यंत्र केस' में मुकदमा चला. लाहौर जेल में क्रांतिकारी कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था. वहां इन कैदियों के लिए सब दुखदायी था. जेल प्रशासन द्वारा इन्हें उपलब्ध कराई गई वर्दियां कई कई दिनों तक नहीं धुलती थी.

1928 के कोलकाता कांग्रेस के दौरान जतींद्र दास कांग्रेस सेवादल में नेताजी सुभाषचंद्र बोस के सहायक थे. वहीं उनकी मुलाकात सरदार भगत सिंह से हुई और उनके अनुरोध पर जतींद्र दास बम बनाने के लिए आगरा आए. 8 अप्रैल, 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केन्द्रीय असेम्बली पर जो बम फेंके, वे जतींद्र दास के द्वारा ही बनाए हुए थे. इस मामले में 14 जून, 1929 को जतींद्र गिरफ़्तार कर लिए गए और उनपर 'लाहौर षड्यंत्र केस' में मुकदमा चला. लाहौर जेल में क्रांतिकारी कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था. वहां इन कैदियों के लिए सब दुखदायी था. जेल प्रशासन द्वारा इन्हें उपलब्ध कराई गई वर्दियां कई कई दिनों तक नहीं धुलती थी. इनका रसोई क्षेत्र और भोजन चूहों और तिलचट्टों से भरा रहता था. साथ ही इन्हें कोई भी पठनीय सामग्री जैसे अखबार या कोई कागज आदि नहीं प्रदान किया गया था, जबकि उसी जेल में अंग्रेज राजबन्दियों को सभी सुविधाएं प्राप्त थीं. जेल में क्रान्तिकारियों के साथ राजबन्दियों के समान व्यवहार न होने के विरोध में जतींद्र दास ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ 13 जुलाई, 1929 से भूख हड़ताल शुरू कर दी. उन्होंने ऐलान किया कि एक बार अनशन आरम्भ होने के बाद हम अपनी मांगों की पूर्ति के बिना उसे नहीं तोड़ेंगे. जेल अधिकारियों ने जतींद्र दास और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को जबरन खिलाने की कोशिश की, उन्हें मारा पीटा गया. बाद में जब अनशन पर बैठे क्रांतिकारियों की हालत बिगड़ने लगी, तो जेल अधिकारियों ने जबरन उनकी नाक में नली डालकर उन्हें दूध देना शुरू कर दिया. लेकिन जतीन्द्र को इससे पहले 21 दिनों के अनशन का अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों की ये युक्ति उनपर काम नहीं आई. नाक से डाली नली को सांस से खींचकर वे दांतों से दबा लेते थे. अंग्रेजों को ये पता चल गया. इसके बाद जब जतींद्र ने एक नाक की नली दांतों से दबाई, तो एक जेल अधिकारी ने उनके दूसरे नाक में भी एक नली डाल दी. ये नली जतींद्र के फेफड़ों तक चली गई. उनकी घुटती सांस की परवाह किए बिना अंग्रेज ने जतींद्र के फेफड़ों में दूध भर दिया. इससे उन्हें निमोनिया हो गया. इसके बाद जेल कर्मचारियों ने उन्हें धोखे से बाहर ले जाना चाहा, लेकिन जतींद्र अपने साथियों से अलग होने के लिए तैयार नहीं हुए. अंततः अनशन के 63वें दिन 13 सितम्बर, 1929 को जतींद्र नाथ दास का देहांत हो गया. इस वीर क्रांतिकारी ने मरना स्वीकार किया, लेकिन जीते-जी अन्याय नहीं सहा. जतींद्र के भाई किरण चंद्रदास ट्रेन से उनका शव कोलकाता ले गए. रास्ते में सभी स्टेशनों पर मां भारती के इस लाल के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा थी. उनके अंतिम संस्कार के समय कोलकाता में दो मील लंबा जुलूस निकला था. जतींद्र नाथ दास की इस ऐतिहासिक अहिंसात्मक शहादत का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में किया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

घरेलू उपचार से पाएं वायरल बुखार पर काबू

चौथी दुनिया ब्यूरो

मानसून का मजा तो सब लेते हैं, लेकिन इस दौरान खुद को संक्रमण से बचाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं. मानसून में सबसे ज्यादा वायरल बुखार लोगों को अपना शिकार बनाता है. वायरल कई तरह के संक्रमण का कारण होता है. यहां तक कि कई वायरस भी वायरल का कारण बनते हैं. वायरल के दौरान आमतौर पर चक्कर आना, कफ-कोल्ड होना और गले में खराश जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. कई बार लोग वायरल का इलाज न करके इसके कारण होने वाली परेशानियों का इलाज करने लगते हैं. अगर शुरुआत से ही सावधानियां बरती जाएं, तो इससे बचा जा सकता है. हल्का बुखार होने के साथ ही घरेलू उपचार करना वायरल के प्रकोप से बचा सकता है. कई आयुर्वेद डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं कि अगर बुखार 102 या इससे कम हो, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ घरेलू नुस्खे आजमाकर भी बुखार को खत्म किया जा सकता है. हालांकि इन्हें डॉक्टरी सलाह के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. बुखार कम नहीं होने की स्थिति में डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए. ये घरेलू नुस्खे निम्नलिखित हैं:

वायरल के दौरान आमतौर पर चक्कर आना, कफ-कोल्ड होना और गले में खराश जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. कई बार लोग वायरल का इलाज न करके इसके कारण होने वाली परेशानियों का इलाज करने लगते हैं. अगर शुरुआत से ही सावधानियां बरती जाएं, तो इससे बचा जा सकता है. हल्का बुखार होने के साथ ही घरेलू उपचार करना वायरल के प्रकोप से बचा सकता है.

तुलसी का काढ़ा

बैक्टीरियल विरोधी, कीटाणुनाशक, जैविक विरोधी और कवकनाशी गुण तुलसी को वायरल बुखार के लिए सबसे उत्तम बनाते हैं. एक चम्मच लौंग पाउडर को करीब 20 ताजे और साफ तुलसी के पत्तों के साथ एक लीटर पानी में डालकर उबाल लें. इस काढ़े का हर दो घंटे में सेवन करें.

अदरक, हल्दी और शहद

अदरक में एंटी फ्लेमेबल, एंटीऑक्सिडेंट और वायरल बुखार के लक्षणों को कम करने के गुण होते हैं. पानी में मध्यम आकार के अदरक के दो सूखे टुकड़े या सौंठ पाउडर को डालकर उबालें. दूसरे उबाल में अदरक के साथ थोड़ी हल्दी, काली मिर्च, चीनी आदि को उबालें. इसे दिन में चार बार थोड़ा-थोड़ा पिएं. इससे वायरल बुखार में आराम मिलता है.

धनिये की चाय

धनिये में मौजूद एंटीबायोटिक यौगिक वायरल संक्रमण से लड़ने की शक्ति देते हैं, साथ ही धनिया शरीर की रोग प्रतिरक्षा क्षमता को भी बढ़ाता है. इसके लिए पानी में एक बड़ा चम्मच धनिये के बीज डालकर उबाल लें. इसके बाद इसमें थोड़ा दूध और चीनी मिलाएं. इसे पीने से वायरल बुखार में बहुत आराम मिलता है.

चावल का माढ़

वायरल बुखार के इलाज के लिए प्राचीन काल से लोकप्रिय घरेलू उपाय है, चावल स्टार्च या माढ़. यह पारंपरिक उपाय प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा देता है. यह विशेष रूप से वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों और बड़े लोगों के लिए एक प्राकृतिक पौष्टिक पेय के रूप में कार्य करता है. इसमें स्वादानुसार नमक मिलाकर गर्म-गर्म ही पिएं.

मेथी का पानी

मेथी के बीज में डायेसजेनिन, सपोनिन्स और एल्कलॉइड जैसे औषधीय गुण होते हैं. मेथी के पानी को नियमित रूप से पीने पर वायरल बुखार में लाभ मिलता है. मेथी के बीज, नींबू और शहद का मिश्रण तैयार कर उसका सेवन भी फायदेमंद होता है.

नींबू और शहद

शहद और नीबू का रस भी वायरल फीवर कम करने में कारगर होते हैं. बुखार से बचने के लिए इनका सेवन भी कर सकते हैं.

अन्य सावधानियां

- बुखार पीड़ित के माथे पर पानी की पट्टियां रखें. पट्टियां तब तक रखें, जब तक शरीर का तापमान कम न हो जाए.
- मरीज को हर छह घंटे में पैरासिटामोल की एक गोली दे सकते हैं. बिना डॉक्टर की सलाह के दूसरी कोई भी दवा न दें.
- रोगी को पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट का सेवन करना चाहिए.
- अगर दो दिन में बुखार ठीक न हो, तो मरीज को डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

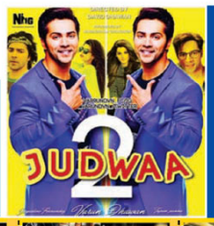

वरुण धवन ने भी लिया रीमेक का सहारा

वैसे तो वरुण धवन ने बॉलीवुड में अभी तक एक भी असफल फिल्म नहीं दी है. लेकिन फिर भी उन्होंने रीमेक फिल्म करने का फ़ैसला किया. 9 सितंबर को वरुण धवन की फिल्म *जुड़वा–2* रिलीज होने जा रही है, जिसे उनके पिता डेविड धवन ने निर्देशित किया है. इस फिल्म में वरुण के साथ जैकलीन फर्नांडिस और तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी. बता दें कि फिल्म *जुड़वा–2* साल 1997 में आई सलमान खान की फिल्म *जुड़वा* का रीमेक है. इस फिल्म को भी डेविड धवन ने ही निर्देशित किया था. इस समय वरुण धवन की *जुड़वा–2* का क्रेज दर्शकों के बीच देखा जा सकता है. सिनेमाई पंडितों की मानें, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है.■

क्या रीमेक फिल्मों के भरोसे चल रहा है बॉलीवुड!

प्रवीण कुमार
feedback@chauthiduniya.com

फिल्मों को लेकर अगर बीते दौर की बात की जाए, तो ये साफ नज़र आता है कि उस दौर में बॉलीवुड अच्छी स्क्रीप्ट और गीतों पर ज्यादा जोर देता था. बहुत कम ही फिल्में ऐसी होती थीं, जो किसी दूसरी फिल्म को कॉपी करके बनाई जाती थी. उस समय फिल्मों का एक क्रेज होता था और दर्शक बड़ी बेसब्री से अपने सुपरस्टार की फिल्मों का इंतजार करते थे. उस समय के निर्देशक भी अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों के सामने कुछ न कुछ नया परोसने की कोशिश करते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है. मौजूदा दौर में बहुत कम ही ऐसी फिल्में बनती हैं, जिसमें किसी दूसरी फिल्म की कॉपी न की गई हो. सही मायने में कहा जाए, तो बॉलीवुड में अब रीमेक फिल्मों का बोलबाला है. हो भी क्यों नहीं, आख़िर ये रीमेक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई जो करती हैं. वो चाहे हॉलीवुड का रीमेक हो या फिर साउथ इंडियन फिल्मों का, इन्होंने पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर काफी तेजी से धमाल मचाया है.

ऐसा नहीं है कि रीमेक फिल्मों का ये कारोबार नया है. एक लंबे समय से बॉलीवुड में रीमेक फिल्में बनाई जा रही है. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में फिल्मों को कॉपी करके बनाने के इस चलन ने खूब रफ्तार पकड़ी है. इसके पीछे के कई कारण भी हैं. पहला तो ये कि ऐसी फिल्मों को लेकर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. बनी–बनाई स्क्रिप्ट मिल जाती है. दूसरी बात ये कि किसी सुपरहिट फिल्म को कॉपी करके दर्शकों के सामने रखना ज्यादा रिस्की भी नहीं रहता. केवल फिल्म को परोसने का अंदाज इस कदर बदला जाता है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आ ही जाती है. नतीजा यह होता है कि ऐसी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करती हैं. उदाहरण के तौर पर देखा जाए, तो सलमान खान ने बॉलीवुड को सबसे ज्यादा सुपरहिट रीमेक फिल्में दी हैं. ये कहना गलत भी नहीं होगा कि सलमान खान आज जिस मुकाम पर हैं, उन्हें वहां पहुंचाने में इन रीमेक फिल्मों का ही सबसे बड़ा योगदान है. सलमान के अलावा अजय देवगन, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जैसे सुपरहिट अभिनेताओं ने भी कई रीमेक फिल्में की हैं.

हाल की बात करें, तो वरुण धवन की फिल्म जुड़वा–2 भी इसी महीने रिलीज होने जा रही है, ये 1997 में आई सलमान खान की फिल्म जुड़वा का रीमेक है. ख़ास बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों का निर्देशन डेविड धवन ने ही किया है. देखना तो बस यह है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित होती है. गौर करने वाली बात ये है कि सलमान खान की फिल्म *जुड़वा* भी एक साउथ इंडियन फिल्म का ही रीमेक थी. उस फिल्म में नागार्जुन, रमाया कृष्णन और सौंदर्या ने मुख्य भूमिका निभाई थी. वैसे बता दें कि इस साल अभी तक *रावता* और *ट्यूबलाईट* जैसी रीमेक फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुईं. अब बारी है *जुड़वा–2* की, जो 29 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. देखते हैं, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है.

भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादातर रीमेक फिल्में सफल रहती हों, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर कब तक दर्शकों को मूर्ख बनाकर बॉलीवुड पैसे बटोरता रहेगा. दर्शक जिन फिल्मों को पहले ही किसी ना किसी दूसरी भाषा और दूसरे अंदाज में देख चुके होते हैं, उन्हीं फिल्मों को बॉलीवुड में तेजी से दर्शकों के सामने परोसा जा रहा है और करोड़ों कमाया भी जा रहा है. यह कहना गलत भी नहीं होगा कि अब बॉलीवुड रीमेक फिल्मों के भरोसे ही ज्यादा चल रहा है. अगर बॉलीवुड में रीमेक फिल्में बननी कम हो जाएं, तो बॉक्स ऑफिस पर इसका रिजल्ट आपको साफ़ दिख जाएगा.

बात जब रीमेक फिल्मों की हो रही है, तो आईए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ सफल रीमेक फिल्मों के बारे में...

राम और श्याम (रामुडु भीमुडु) : बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि तानी कृष्णसनन की 1967 में आई फिल्म *राम और श्याम* असल में तेलुगु फिल्म *रामुडु भीमुडु* की रीमेक है. 1964 में आई रामा राव की इस तेलुगु फिल्म ने अपने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था. इसके हिंदी वर्जन *राम और श्याम* में एक्टर दिलीप कुमार दोहरे किरदार में नजर आए थे.

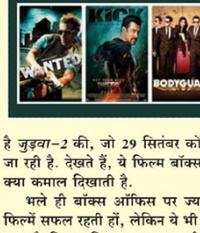

हम आपके हैं कौन (नदिया के पार): सूरज बड़जात्या की फिल्म *हम आपके हैं कौन* 1994 की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी. सलमान खान, माधुरी दीक्षित, रेणुका शहाणे, मोहनीश बहल आदि सितारों ने अपने दमदार अभिनय से इस फिल्म में जान डाल दी थी. यह एक शानदार परिवारिक फिल्म थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. लेकिन इस फिल्म का श्रेय वर्ष 1982 में आई भोजपुरी फिल्म *नदिया के पार* को दिया जाना चाहिए. क्योंकि सूरज बड़जात्या की *हम आपके हैं कौन*, *नदिया के पार* का रीमेक थी.

विरासत (थेवार मगन): 1997 में प्रियदर्शन ने एक फिल्म बनाई, जिसका नाम था *विरासत*. इस फिल्म में अनिल कपूर ने एक नौजवान का किरदार निभाया था. वो नौजवान अपने गांव के विकास के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता. ये फिल्म भी खूब पसंद की गई थी. अनिल कपूर की ये फिल्म साउथ इंडियन फिल्म *थेवार मगन* का रीमेक थी. इस फिल्म में कमल हासन ने शानदार अभिनय किया था.■

आमिर की गज़नी ने बढ़ाया क्रेज

वैसे तो बॉलीवुड में रीमेक फिल्में बनाना कोई नई बात नहीं है. एक लंबे अरसे से बॉलीवुड में फिल्मों के रीमेक बनते आ रहे हैं. लेकिन जब साल 2008 में आमिर खान की फिल्म *गज़नी* आई, तो उस समय आग की तरह ये ख़बर फैल गई कि ये फिल्म क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म *मेमन्टो* (2000) की रीमेक है. फिर क्या था, आमिर खान की गज़नी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया कि लोग देखते ही रह गए. बॉलीवुड में यह पहली ऐसी फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया. इस प्रकार *गजनी* के द्वारा आमिर खान सौ करोड़ की कमाई देने वाले पहले बॉलीवुड स्टार बन गए. एक तरह से गज़नी के बाद ही बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का दायरा बढ़ा. इसके बाद निर्देशक एआर मुर्गुदॉस ने इसका तमिल वर्जन भी बनाया था, जिसमें एक्टर सूर्या ने मुख्य भूमिका निभाई.

आमिर खान ने अपने अब तक के करियर में गज़नी के अलावा भी कई रीमेक फिल्मों में काम किया है. जिनमें *जो जीता वही सिकंदर*, *गुलाम*, *3 इडियट्स*, *दिल है कि मानता नहीं*, *अकेले हम अकेले तुम*, *मन*, *सरफरोश* आदि प्रमुख हैं. ■

रीमेक फिल्म को सिंघम भी पसंद करते हैं

बॉलीवुड के दूसरे स्टार एक्टर्स की तरह अजय देवगन ने भी रीमेक फिल्मों को चुनना ज्यादा पंसद किया है. अपने करियर में उन्होंने कई सफल रीमेक फिल्में दी हैं. अजय बॉलीवुड में पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से सक्रिय हैं और आज भी अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं.

अजय की अब तक की रीमेक फिल्मों में *हिम्मतवाला*, *युवा*, *आग*, *संडे*, *इंसान*, *कयामत*, *प्यार तो होना ही था*, *बोल बच्चन*, *आक्रोश*, *गोलमाल*, *सन ऑफ सरदार*, *एक्शन–जैक्सन*, *सिंघम*, *सिंघम रिटर्नस* आदि शामिल हैं.■

बीते दौर से रीमेक फिल्में करते आ रहे हैं अक्षय

फिल्म *मानीचित्राथझू* एक मलयालम फिल्म है. मनोचिकित्सा पर आधारित इस कॉमेडी–हॉरर फिल्म को 1993 में काफी सफलता मिली. इसी से प्रेरित होकर 2007 में प्रियदर्शन ने इसका हिंदी वर्जन अक्षय कुमार को लेकर बनाया, जिसका नाम था *भूल–भूलैया*. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पंसद किया और फिल्म हिट रही.

वैसे बता दें कि बॉलीवुड में अक्षय कुमार ने भी काफी रीमेक फिल्मों का सहारा लिया है. *मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी*, *इंसान*, *राउडी राठौड़*, *हॉलीडे*, *गब्बर*, *बॉस*, *खट्टा–मिठ्ठा*, *कम्बख्त इश्क*, *गरम मसाला*, *हेरा–फेरी*, *दे दना दन* आदि ऐसी रीमेक फिल्में हैं, जिन्होंने अक्षय को बॉलीवुड में टॉप का अभिनेता बनाने में काफी मदद की है. ■

वॉन्टेड से बना सलमान का करियर

पुरी जगन्नाध की लिखी व निर्देशित फिल्म *पोकिरी* एक तेलुगु एक्शन फिल्म है, जिसमें महेश बाबू और इलायाना डीक्रूज ने मुख्य भूमिका निभाई थी. पोकिरी तेलुगु में अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है. कई भाषाओं में इसके रीमेक भी बने. इसे तमिल भाषा में प्रभु देवा ने निर्देशित किया था. बाद में प्रभु देवा ने ही सलमान खान को लेकर इसका हिंदी वर्जन बनाया, जिसका नाम था वांटेड. इसमें सलमान खान को एक गैंगस्टर के रोल में दिखाया गया था, जो बाद में अंडरकवर कॉप के रूप में सामने आता है. यह फिल्म सलमान के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई. सलमान के गिरते करियर को वॉन्टेड ने ही ऊपर उठाया था. वॉन्टेड के बाद से सलमान खान के करियर में एक बड़ा मोड़ आया. बॉलीवुड में अगर सबसे ज्यादा रीमेक फिल्मों का रिकॉर्ड होगा, तो वो यकीनन सलमान खान का ही होगा. सलमान ने वॉन्टेड से पहले *जुड़वा*, *बंधन*, *हम आपके हैं कौन*, *बीवी नंबर–1*, *तेरे नाम*, *हर दिल जो प्यार करेगा*, *क्योंकि*, *हम तुम्हारे हैं सनम*, *नो एंट्री* आदि रीमेक फिल्में की है. ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं. वॉन्टेड के बाद भी सलमान ने कई रीमेक फिल्में की. जिनमें *रेडी*, *बॉडीगार्ड*, *एक था टाइगर*, *किक*, *जय हो*, *बजरंगी भाईजान*, *ट्यूबलाईट* आदि फिल्में शामिल हैं. सलमान की इन सभी फिल्मों ने रिकॉर्डतोड़ सफलता हासिल की. यह कहना गलत नहीं होगा कि आज सलमान का जो जलवा है, उसमें रीमेक फिल्मों का सबसे बड़ा हाथ है.■

रीमेक फिल्मों के पोस्टर्स